हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

क्रिकेट में कटुता

विश्व क्रिकेट में पैदा ताजा तनाव दुखद और निराशाजनक है। आगामी 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय था, पर पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच से हटने का फैसला सुनाकर अपनी बेवजह की दुश्मनी का इजहार कर दिया है। ध्यान रहे कि पहले टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में ही होना था, मगर पाकिस्तान ने भारत में खेलने पर आपत्ति जताई थी और इसी वजह से श्रीलंका को भी आयोजक के रूप में शामिल किया गया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाला है, वह खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं। अब क्रिकेट की विश्व संस्था आईसीसी में नाराजगी है और आयोजकों को घाटा होना तय है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने का कोई कारण नहीं बताया है। वैसे, आईसीसी की ओर से अभी भी यह कोशिश जारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा फैसला न करे, जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचे।

कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर पूरी तरह से राजनीति हावी हो गई है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग भारत में ज्यादा होती है और न खेलने का फैसला उसने किया है। हम यह मानते हैं कि जो देश हमें आतंकवाद से पीड़ित करता है, उसके साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम साल 2008 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गई है। इससे पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है, मगर पाकिस्तानी हुक्मरान इस पहलू को मानने से हिचकते हैं। वहां का क्रिकेट बोर्ड अपने खर्चे के लिए विश्व क्रिकेट पर निर्भर है और विश्व क्रिकेट में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा पैसा भारतीय है। अपनी कट्टर और खोखली सियासत से प्रभावित पाकिस्तान को यह मानने में बहुत परेशानी होती है कि विश्व क्रिकेट को चलाए रखने में भारत का सर्वाधिक योगदान है। पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों में सुधार के लिए तैयार नहीं है। शायद उसे लगता है, भारत या भारतीय बोर्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिसाल के लिए, एशिया कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तानी बोर्ड के अध्यक्ष ने विजेता भारत को नहीं सौंपी है। बड़ा सवाल है कि जो भारतीय बोर्ड अपने हिस्से की ट्रॉफी नहीं ले पाया, वह अब आगे क्या कड़े कदम उठाएगा?

भारत क्रिकेट की महाशक्ति है, तो यह सच संतुलित ढंग से दुनिया के सामने आना चाहिए। क्रिकेट प्रेमियों की भावना के साथ खिलवाड़ रुकना चाहिए।

वैसे, अनुमान है, इस बार भारतीय बोर्ड कड़े कदम उठाएगा, क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच की भारी मांग होती है। प्रसारण के समय दस-दस सेकंड के विज्ञापनों की कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। अब समय आ गया है, जब भारतीय बोर्ड को कमाई के साथ सम्मान की भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर भारत क्रिकेट की महाशक्ति है, तो यह सच संतुलित और न्यायपूर्ण ढंग से दुनिया के सामने आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भावना के साथ खिलवाड़ रुकना चाहिए। विश्व क्रिकेट को पहले बांग्लादेश और अब पाकिस्तान ने जिस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। भारत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिकेट सियासत का जरिया बनकर समस्याओं को न बढ़ाए। असंख्य भारतीयों की धारणा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मगर भारतीय बोर्ड जहां भी पाकिस्तान के साथ खेलना जरूरी होता है, कोई न कोई राह निकालता आया है। यह भारत की भलमनसाहत है, पर पाकिस्तान ने इसका जैसा उत्तर दिया है, उसका अनुकूल प्रति-उत्तर अवश्य जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 03 फरवरी, 1951

बचत पखवाड़ा

दिल्ली राज्य में फरवरी माह का प्रथम पखवाड़ा बचत पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अपनी बचत के रुपये सरकार की बचत योजनाओं में लगाने को विशेष रूप से प्रेरित किया जाये।

राष्ट्रीय विकास की बड़ी-बड़ी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार नदियों पर बड़े-बड़े बांध बांधना चाहती है, ताकि सिंचाई की व्यवस्था की जा सके और खेती की उपज बढ़ाकर देश की खाद्य समस्या को, जो एक विकटतम समस्या है, हल किया जा सके। इन बांधों के जरिये बिजली भी बड़े पैमाने पर पैदा की जायेगी और उद्योग-धंधों के विकास के लिए सुलभ की जायेगी। स्पष्टतः ही इन योजनाओं का लक्ष्य देश के आर्थिक साधनों का विकास करके लोगों की दरिद्रता और अभाव को दूर करना है। सरकार के पास अपनी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त रुपये उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सरकार चाहती है कि लोग इस काम में हाथ बंटायें। वे सरकार की बचत योजनाओं में रुपये लगाकर ऐसा कर सकते हैं। बचत योजनाओं में रुपये लगाना आज की परिस्थितियों में देशभक्ति की भावना का परिचय देना होगा।

बचत योजनाओं में रुपये लगाने में केवल राष्ट्र का ही हित नहीं है, बल्कि स्वयं व्यक्तियों का भी लाभ है। इस प्रकार जो रुपये लगाये जायेंगे, उसका सरकार माकूल ब्याज देगी। इस प्रकार अपनी बचत को अतिरिक्त आय का साधन भी बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी सारी आमदनी को खर्च कर डालता है अथवा आमदनी से अधिक खर्च कर देता है, वह बुद्धिमानी का काम नहीं करता। बुद्धिमान मनुष्य वही है, जो अपनी आय का एक अंश अनिवार्य रूप से बचाकर रखता है, ताकि वह आड़े समय में उसके काम आये।... दूसरे, वे पांच वर्ष और दस वर्ष की अवधि के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं।

सरकार ने बचत की एक और अधिक सुविधाजनक योजना इस वर्ष निकाली है। वह है दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपोजिट योजना। इस योजना में रुपये जमा कराने वालों को साढ़े तीन प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज मिलेगा और वे ब्याज की रकम प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकेंगे।

विरासत, नीति, तरक्की की त्रयी त्रिपुरा

यहां स्कैन करें

ज्योतिरादित्य एम सिंधिया | केंद्रीय मंत्री

सशक्त बुनियादी ढांचे के सहारे त्रिपुरा ने अपनी उन विशिष्ट शक्तियों को आगे बढ़ाया है, जो इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हैं, ताकि उसका सामर्थ्य राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला से जुड़ सके।

त्रिपुरा को समझने के लिए केवल उसके भौगोलिक स्वरूप या विकास के आंकड़ों को देखना पर्याप्त नहीं है। धान के खेतों की फैली हरियाली, नहरों पर बिखरी धूप और गांव की छतों पर सुनाई देने वाली रवींद्र संगीत की मीठी स्वर-लहरियां मिलकर यहां की दिनचर्या तय करती हैं। कभी-कभी शाम की नम, ठंडी हवाओं में सचिन देव बर्मन के सुरों की झिलमिलाहट सुनाई देती है, जो इस भूमि की सांस्कृतिक गहराई को शब्दों से परे पहुंचा देती है। मैंने अपनी हालिया यात्रा में जब ये दृश्य देखे, तो महसूस हुआ कि त्रिपुरा कैसे परंपरा और आधुनिकता का सम्मिलित अभियान बन चुका है।

यही अभियान त्रिपुरा की जमीनी हकीकत का एक प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व को 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में देखने का जो दृष्टिकोण दिया, उसी के अनुरूप त्रिपुरा में 'कनेक्टिविटी' को विकास की पहली शर्त बनाया गया। सड़कें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भाजपा सरकार के दौरान राज्य का सड़क नेटवर्क 850 किलोमीटर से बढ़कर 1,550 किलोमीटर से अधिक हो गया है। महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा अब एक आधुनिक प्रवेश द्वार बन चुका है। 30 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला यह आधुनिक टर्मिनल न केवल राज्य को देश और दुनिया से जोड़ रहा है, बल्कि यहां आने वाले हर यात्री के साथ नई संभावनाएं भी ला रहा है। ब्रॉड-गेज रेल नेटवर्क अब त्रिपुरा के सबसे दक्षिणी शहर सबरूम तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'हीरा' (हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज) मॉडल ने सुनिश्चित किया है कि निवेश, पर्यटन और अवसर अब त्रिपुरा तक सहजता से पहुंचें। इस सशक्त बुनियादी ढांचे के सहारे त्रिपुरा ने अपनी उन विशिष्ट शक्तियों को आगे बढ़ाया है, जो इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हैं, ताकि उसका स्थानीय सामर्थ्य राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से प्रभावी रूप से जुड़ सके।

राज्य में माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखते हुए मैंने यह अनुभव किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार और निजी संस्थाओं के साझा प्रयासों से 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण के तहत 450 करोड़ रुपये की इस परियोजना को आकार दिया जा रहा है, ताकि त्रिपुरा भारत के उभरते पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से अपनी जगह बना सके। चार-पांच दिनों का 'एंड-टु-एंड टूरिस्ट सर्किट' ठोस ढांचागत विकास और मानवीय सेवाओं, दोनों को जोड़ता है। सुगम रास्ते, ठहरने की सुव्यवस्थित जगहें, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड और हर पड़ाव पर अनूठा ज्ञान मिलकर सैलानियों को एक समग्र कहानी सुनाते हैं।

महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा से शुरू होकर सिपाहीजाला वन्य जीव अभ्यारण्य, टेपानिया, माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, नीरमहल, उनाकोटी और डंबूर झील तक का यह मार्ग प्रकृति, आस्था और लोक कला को एक सूत्र में जोड़ देता है। उनाकोटी इस अनुभव का केंद्र है। पहाड़ियों पर उकेरी गई विशाल आकृतियां, भगवान शिव की 30 फीट ऊंची मुखाकृति, पत्थर पर तराशी गई जटाएं और रेखाएं, इस स्थल को अद्वितीय बना देती हैं। यह धरोहर बताती है कि त्रिपुरा में विरासत को सहेजते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी सोच के साथ माताबारी सर्किट की आधारशिला रखी गई, ताकि आस्था और आधुनिक सुविधाएं एक साथ आगे बढ़ें।

त्रिपुरा की आर्थिक पहचान को वैश्विक मंच तक ले जाने वाली सबसे सुंदर कहानी अगरवुड की है, जिस पर इस प्रदेश की राजधानी का नाम अगरतला पड़ा। यही अगरवुड अब नर्सरी से लेकर सुगंधित तेल की प्रोसेसिंग तक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 80 करोड़ रुपये की 'अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट परियोजना' की नींव रखी गई है। इस पहल के तहत असम के गोलाघाट और त्रिपुरा के कदमतला में दो 'क्लस्टर प्रोसेसिंग सेंटर' स्थापित किए जाएंगे, जहां 'वैल्यू एडिशन' और 'मार्केट लिंक' के जरिये विश्व बाजार को सीधे त्रिपुरा लाया जा रहा है। यह 'लोकल टु ग्लोबल' का जीवंत उदाहरण है। अपने दौरे के दौरान मुझे कदमतला की संगीता मोहंता जैसी महिला उद्यमी से मिलने का मौका मिला, जो इस परिवर्तन की पहचान बनकर सामने आईं। उनके लिए अगरवुड सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का आधार है। उनके प्रयासों से कई महिलाएं आजीविका से जुड़ रही हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा हाल में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 80 करोड़ रुपये की बांस परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसने 'ग्रीन गोल्ड', यानी बांस को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी उद्योग के रूप में स्थापित करने को दिशा दी है। इसके साथ, अमेजन, फ्लिपकार्ट और एटीपी (ऑल टाइम प्लास्टिक्स) जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ किए गए समझौते के माध्यम से यहां का बांस उद्योग तेजी से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ रहा है। इन अभियानों के केंद्र में स्थानीय कारीगर, महिलाएं और युवा हैं, जिनकी सहभागिता से यह उद्योग आजीविका, उद्यम और आत्मविश्वास का स्रोत बन रहा है। विकास की यही लय जंगल और खेत, दोनों में समान रूप से दिखाई देती है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को बल दिया है। त्रिपुरा लगभग 1,000 मेगावाट क्षमता के साथ 'पावर सरप्लस' राज्य बन चुका है। इसकी इस क्षमता ने बांस और अगरवुड प्रोसेसिंग इकाइयों व घरेलू जीवन, सबको नया बल दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने यहां बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए द्वार खोले हैं, जिससे युवा व कारीगर, दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

त्रिपुरा की संस्कृति और त्योहार इसके विकास की कहानी को भावनात्मक आधार देते हैं। चतुर्दश देवता की मान्यताएं व दुर्गापूजा की भव्यता, भाषिक विविधता के पार भी एकता का संदेश देती है। माता त्रिपुर सुंदरी के प्राचीन मंदिर में भक्ति का गहन अनुभव और जंपुई की पहाड़ियों में बसी लोककथाएं संकेत देती हैं कि यहां 'विकास भी, विरासत भी' का मंत्र किस संतुलित और संवेदनशील तरीके से मूर्त रूप ले रहा है। एक ऐसा राज्य, जहां परंपरा व आधुनिकता साथ-साथ चलते हैं और जहां पूर्वोत्तर भारत का विकास आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय विकास की धारा को गति दे रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है, जिसे स्थानीय शक्ति, नीतिगत संकल्प और सांस्कृतिक आत्मा ने मिलकर तय किया है। इस यात्रा में आने का निमंत्रण त्रिपुरा स्वयं दे रहा है और इसे देखने का अनुभव हर यात्री के लिए अविस्मरणीय होगा।

(लेखक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री हैं)

चुनाव को करीब देख फिर धर्म की शरण में द्रमुक

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

बीते इतवार को जब दिल्ली बजट भाषण पर बहस में डूबी हुई थी, ठीक उसी दिन तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। दरअसल, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा थी और इसी दिन तमिल त्योहार 'थाईपुसम' मनाया जाता है। तमिलनाडु के धर्मपरायण लोगों के लिए इस दिन का बहुत महत्व होता है।

लंबे समय तक खुद को नास्तिक कहने वाले दल (द्रमुक) ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए इसी त्योहारी दिन को चुना। 'थाईपुसम' थाई और पुसम शब्दों से मिलकर बना है। थाई एक तमिल महीने का नाम है, जिसकी पहली पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) ने इसी दिन अपनी मां पार्वती द्वारा दिए गए दिव्य हथियार से सूरपद्मण नामक राक्षस का संहार किया था। तमिलनाडु में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन इस बार यह त्योहार इतवार को ही पड़ गया। इस दिन लोग शिव मंदिरों, खासकर भगवान मुरुगन के मंदिरों में उमड़ पड़े और पूजा-अर्चना की। जाहिर है, द्रमुक ने श्रद्धालुओं को खुश करने के लिए इस दिन का चयन किया, इससे यही संदेश गया है कि इस पार्टी को भी धर्म के समर्थन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। द्रमुक को सत्ता विरोधी लहर के साथ-साथ अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। अन्नाद्रमुक तो है ही।

खुद को नास्तिक कहने वाले द्रमुक ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए पवित्र 'थाईपुसम' त्योहार के दिन को चुना।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक- दोनों परंपरागत प्रतिद्वंद्वी दलों ने अपने गठबंधन लगभग तय कर लिए हैं। छोटी-मोटी कुछ अड़चनें हैं, जिनको वे आने वाले दिनों में सुलझा लेंगे। समय की कसौटी पर खरे उतरे द्रमुक गठबंधन के इस चुनाव में भी बने रहने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसके एक प्रमुख घटक कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने रुख की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह सौदा तय लग रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इकाइयों के कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडणकर द्रमुक नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आने वाले हैं।

कांग्रेस 234 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 33 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि पिछले चुनावों में उसे 25 सीटें मिली थीं। हालांकि, उसे पुडुचेरी में ज्यादा परेशानी हो रही है। वहां उसका दबदबा है और वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि द्रमुक भी वहां नेतृत्व का दावा कर रही है और उसके नेता जगतरक्षकन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के डाटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती के नेतृत्व वाला गुट अभिनेता विजय के साथ गठबंधन पर जोर दे रहा है। चक्रवर्ती का कहना है कि विजय के पास चुनाव जीतने के बेहतर मौके हैं। प्रवीण और विजय, दोनों चुनावी राजनीति में नए हैं, पर वे अपनी राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं।

द्रमुक का दूसरे घटकों से कमोबेश गठबंधन हो गया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के भी संपर्क में है। इधर, अन्नाद्रमुक के सभी गुटों को एकजुट करने में नाकाम रही भाजपा ने अब यह प्रयास छोड़ दिया है। वैसे, उसका गठबंधन टीटीवी दिनाकरन को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा है। इस बार उसे पीएमके से भी समझौता किया है, जिसका तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में काफी प्रभाव है। अन्नाद्रमुक 150 से 160 सीटें अपने पास रखेगी और बाकी सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। भाजपा 30 सीटें मांग रही है, मगर वह 22 पर मान सकती है।

अभिनेता विजय ने धमाकेदार शुरुआत की और कई दलों को गठबंधन के लिए बुलाया। दुर्भाग्य से, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अब विजय ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का एलान किया है। उनके प्रत्याशी पारंपरिक पार्टियों के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। लाख टके का सवाल यही है कि विजय किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? द्रमुक और अन्नाद्रमुक- दोनों तमिल दल दावा कर रहे हैं कि अभिनेता के आने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे भी जानते हैं कि उनकी यह बात विश्वसनीय नहीं है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

समय से परेशान

आज आदमी का मन समय को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। हर किसी को कहीं-न-कहीं जल्दी पहुंचना है। लोग लक्ष्य-केंद्रित हो गए हैं। अगर कोई लक्ष्य है, तो वहां जल्दी पहुंचना है, किसी और से भी ज्यादा जल्दी। इस रफ्तार के पागलपन की वजह से 'इंस्टेंट' चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं।

रफ्तार जितनी बढ़ गई है, उतना अधैर्य बढ़ गया है। सब कुछ अभी चाहिए। भोजन का नाम भी हो गया 'फास्ट फूड'! इसका 'साइड इफेक्ट' भी है। तेज रफ्तार के साधनों की सनक ने लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्र बना दिया है। इंतजार करना दंड भोगने जैसा मालूम होता है। इस रवैये ने लोगों से उनकी शांति, उनका आराम और उनकी नींद छीन ली है। नींद के लिए एक शांत दिमाग चाहिए, जो अपने आप में ठहरकर विश्राम कर सके।

ओशो कहते हैं, मुझे इस स्थिति में एक सकारात्मक पहलू भी दिखता है। यह बात कि लोग एक पल का भी इंतजार नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वे हर पल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हर पल की इस अहमियत का इस्तेमाल उन्हें ध्यान से परिचित कराने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान का मतलब है- पल में जीना, क्षण क्षण जीना। ध्यान करने वाला भी हरेक पल को अहमियत देता है, लेकिन फर्क यह है कि वह हर पल में गहराई से उतरता है, जबकि तेज आदमी पल को सतही तौर पर जीता है। वह पागलों की तरह एक पल से दूसरे पल में कूद रहा है।

इस स्थिति का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मन की बेचैनी दूर करने के लिए ध्यान की छोटी-छोटी विधियां करें, जो तुरंत नतीजे दे सकती हैं। ये विधियां आप काम-काज करते हुए कर सकते हैं। अलग से जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए देखें। इसे बदलने की कोशिश न करें, सिर्फ देखने से ही सांस धीमी हो जाएगी। अपना काम करते रहें और सांस को देखते रहें। सांस धीमी होने के साथ आपका मन 'रिलैक्स' होने लगेगा और अपने आप शांति की शीतल बयार बहने लगेगी।

इस भरी दुनिया में क्या आपको अपनी याद रहती है? नहीं, लोग खुद को भूल ही जाते हैं। अब प्रयत्नपूर्वक खुद को याद करें। जब कभी भी आपको अपनी याद आए, अपना ध्यान वर्तमान पल में ले आएं। कभी-कभी आप भूल जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, फिर से ध्यान को खींचकर यहां ले आएं। आप महसूस करेंगे, अचानक तनाव खो गया है।

इंतजार करना अब दंड भोगने जैसा मालूम होता है। इस रवैये ने लोगों से उनकी नींद छीन ली है। नींद के लिए एक शांत दिमाग चाहिए, जो अपने आप में ठहरकर विश्राम कर सके।

एक दिन के लिए टेलीग्राम की तरह बात करें। आप व्यर्थ बोलने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, कोई हिसाब है? कम बोलें, सिर्फ जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा दस शब्द। इससे बहुत ऊर्जा बचेगी!

अमृत साधना

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

ग्रीनलैंड मामले में डोनाल्ड ट्रंप की नैतिकता पर बहस करते समय यह याद करना मुनासिब होगा कि यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका में कैसे-कैसे औपनिवेशिक जुल्म किए थे। डेनमार्क ने खुद अफ्रीका से लगभग पांच लाख गुलामों को अमेरिका भेजा था।

अनुलोम-विलोम
केंद्रीय बजट

विकास, अनुशासन और संतुलन का प्रतीक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। वास्तव में यह बजट हमारे देश की आर्थिक स्थिरता और तेज विकास के संतुलन पर केंद्रित रहा। बजट का कुल अनुमानित आकार लगभग 54 लाख करोड़ रुपये रखा गया है तथा सरकार ने देश के विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बजट में सड़क, रेल, बंदरगाह और शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार सृजन की उम्मीद जताई गई है। बजट में राजकोषीय घाटा नियंत्रण का स्पष्ट संकेत मिलता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी का लगभग 4.3 प्रतिशत रखा गया है। वास्तव में, इससे वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। इस बजट में जहां एक ओर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, वहीं पर दूसरी ओर मेक इन इंडिया को और सशक्त करने के प्रयास किए गए हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है तथा तकनीक आधारित उद्योगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, इससे सफल होने के लिए सुधारों का सिलसिला जारी रखना होगा। तीन कर्तव्यों से प्रेरित इस आम बजट में आर्थिक वृद्धि, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण करना है और सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से ज्यादा सुधारों की शुरुआत की गई है। इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। बजट में विकास के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई को मान्यता देते हुए, 10,000 करोड़ रुपये के एसएसएमई विकास निधि का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि निर्धारित विशेषताओं के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस बजट का लक्ष्य शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक स्थिति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

रोजगार सृजन के ठोस उपाय नदारद

केंद्रीय बजट 2026-27 में कई मायनों में चुनौतियां विद्यमान हैं। बजट वास्तविक क्रियान्वयन चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं देता। चाहे वह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर हों, फ्रेट कॉरिडोर हों या खनिज और औद्योगिक कॉरिडोर, इन परियोजनाओं की सफलता केवल घोषणा करने से नहीं होगी। यदि ये परियोजनाएं निर्धारित समय और गुणवत्ता के अनुसार पूरी नहीं हुईं, तो निवेश और रोजगार सृजन में देरी होगी, जिससे बजट की महत्वाकांक्षाएं आधी रह सकती हैं।

इस बजट में मानव पूंजी और कौशल विकास पर जोर तो है, लेकिन रोजगार सृजन के ठोस उपाय बहुत सीमित हैं। एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए बजट प्रावधानों की पर्याप्तता को लेकर भी सवाल है। इस बजट में राजकोषीय घाटा और वित्तीय अनुशासन पर जोर देने के बावजूद विकास और सामाजिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास और किसानों की आय बढ़ाने जैसी योजनाएं शामिल हैं, लेकिन भारत में योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना हमेशा आसान नहीं रहा। टेक्सटाइल और बायो-फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाया गया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए और अधिक व्यापक नीति, निर्यात संवर्द्धन उपाय और टेक्नोलॉजिकल नवाचार पर जोर देने की आवश्यकता है।

समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। यह बजट नीति निर्माण और दृष्टिकोण के स्तर पर सही दिशा में कदम है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान और परिणाममुखी नीतियों के बिना इसके महत्व और प्रभाव सीमित रह सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

सरकारी पक्ष बजट को देश का विकास वाला बजट बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि इस आम बजट से भारत का विकास संभव है? जब तक इस बजट की योजनाओं को पंख लगेंगे, तब तक अगले वित्तीय वर्ष के बजट का समय आ जाएगा। जब तक देश में राजनीतिक भेदभाव रहेगा, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक दिल्ली में जो योजनाएं अमल में लाई जाएंगी, वे दूरदराज के शहरों और गांवों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगी। मीडिया में यही बताया गया कि यह बजट दूरदर्शी है, क्या अब तक बजट पेश किए क्या वे दूरदर्शी नहीं थे?

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

सच बोलना सबसे बड़ी तपस्या

सत्य ही सर्वस्व है। सत्य के बिना सदाचार, दान, कीर्ति, धन किसी काम के नहीं। जहां सत्य होगा, वहां ये सभी होंगे। सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य के द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट जा सकता है। जंगलों, पहाड़ों और वीराने में एकांतवास करना तपस्या नहीं है। जीवन में सच बोलना और सच की राह पर चलना ही सबसे बड़ी तपस्या है।

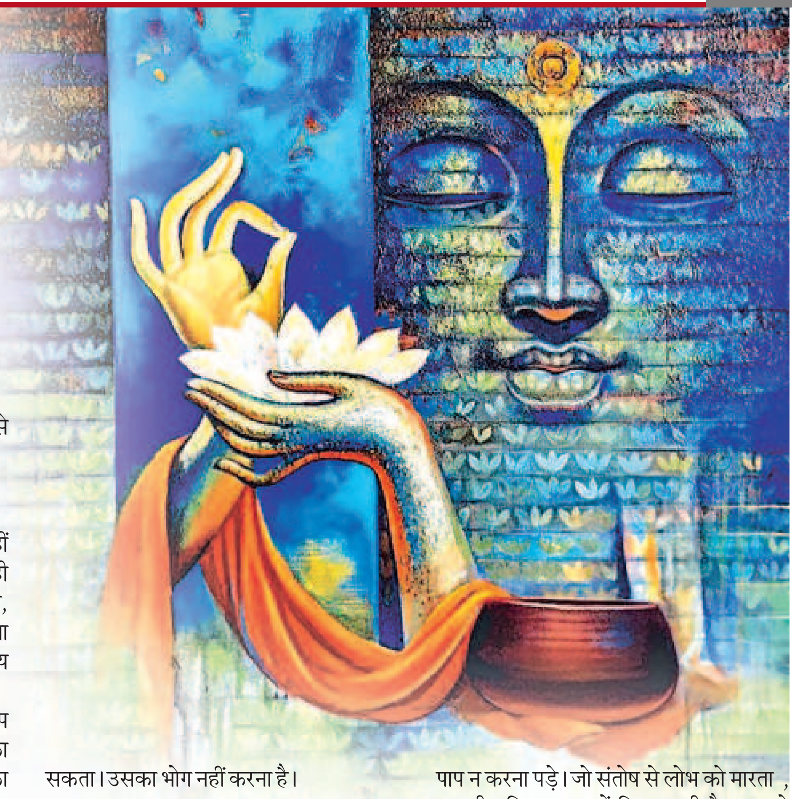

अध्यात्म

रामचंद्र डोंगरे

धर्म के चार पद हैं- सत्य, तप, दया और पवित्रता। इन चार चरणों में सत्य सर्वोपरि है। महाभारत में राजा सत्यदेव की कथा आती है। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि चंचला लक्ष्मी उनके महल से कुछ समय पश्चात चली जाएगी।

एक दिन सुबह जब सत्यदेव उठे, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को घर से निकलते देखा। राजा ने आश्चर्य से उस स्त्री से पूछा, 'आप कौन हैं?' जवाब मिला, 'मेरा नाम लक्ष्मी है। अब मैं इस घर से जा रही हूं।' राजा ने कहा कि आप जा सकती हैं। लक्ष्मीजी चली गईं। उसके पीछे एक सुंदर पुरुष को बाहर जाते देखकर राजा ने पूछा, 'आप कौन हैं?' उत्तर मिला, 'मेरा नाम दान है। लक्ष्मी के जाने के बाद आप दान नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपका घर छोड़ कर जा रहा हूं।' राजा ने कहा कि आप भी जा सकते हैं।

सत्य ही सर्वस्व

इसके बाद तीसरा सदाचार और चौथा यश, पुरुष के रूप में बाहर आए। राजा के पूछने पर लक्ष्मी तथा दान के साथ जाने की कहने पर राजा ने दोनों को जाने दिया। जब पांचवां पुरुष सत्य जाने लगा, तो राजा ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहा, 'मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आप मुझको किसलिए छोड़ रहे हैं? आपके लिए मैंने लक्ष्मी, दान आदि सबका त्याग किया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आपके जाने पर मेरा सब कुछ चला जाएगा।' यह सुनकर सत्य वहीं रह गया। सत्य घर में से बाहर नहीं आया, अतएव गई हुई लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी वापस आ गए। सत्य ही सर्वस्व है। सत्य के बिना सदाचार, दान, कीर्ति, लक्ष्मी किस काम के? इसलिए घबराओ नहीं। जहां सत्य होगा, वहां इन सभी को रहना ही पड़ेगा।

सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य के द्वारा मनुष्य नारायण के निकट जा सकता है।' परमात्मा के लिए दुख सहन करना तप है। प्रभु की आराधना करना तप है। दुख सहन करते हुए जो प्रभु का भजन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। वाणी और व्यवहार में संयमरूप तप का पालन करो, लेकिन सत्य इन सबसे श्रेष्ठ है। कलियुग में पवित्रता नहीं है। कपड़ों पर लगा हुआ दाग छूट सकता है। कलेजे में लगा दाग नहीं छूटता। मरने के बाद जो साथ जाने वाला है, उस मन की शांति को अक्षुण्ण रखो। मन को स्वच्छ रखो।

धर्म के चार अंग

'दया' के लिए श्रुति में निर्देश है कि जो सिर्फ अपने लिए पका कर खाता है, वह अन्न नहीं खाता, पाप पका कर खाता है।

सत्य, तप, दया और पवित्रता धर्म के चार अंग हैं। ये चारों तत्व जिसमें होंगे, वह धर्मी है।

कलियुग में दान प्रधान है। दया अर्थात दान के एक पांव के ऊपर धर्म टिका हुआ है। राजा परीक्षित ने जब कलियुग से राज्य को छोड़कर जाने को कहा, तो कलि ने पूछा कि मैं कहां रहूं? मेरे रहने को जगह दें। तब परीक्षित ने उसे रहने के लिए चार स्थान बताए- जुआ, हिंसा, स्त्री-संग और मदिरा। इन चार स्थानों में असत्य, निर्दयता, आसक्ति और मद ये चार अधर्म रहते हैं। इनसे कलि को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब तो गंदी जगह हैं, एक स्थान मेरे को और दें। राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। इस प्रकार स्वर्ण के माध्यम से कलि को राजा में प्रवेश करने का अवसर मिला।

भोग नहीं, उपयोग करें

ज्ञान बहुतों में होता है, पर ज्ञान की दृढ़ता सब में नहीं होती। प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है, वही मिलेगा। फिर भी मनुष्य झूठ बोलता है। संपत्ति, संतान और लक्ष्मी तो प्रारब्ध से मिलती है। जितना लिखा है, उतना तो मिलेगा ही। मृत्यु के समय मनुष्य में सयानापन आता है, पर वह किस काम का?

यदि प्रभु तुम्हें अधिक दें, तो पाप न करो। पाप की निवृत्ति होने पर ही इंद्रियों को भक्ति रस का सुख मिलता है। इंद्रियां भोग का नहीं, भक्ति का साधन हैं, इसलिए इंद्रियां नहीं बिगड़ें, इसका ध्यान रखो। जितेंद्रिय होने की कोशिश करो।

संपत्ति होने पर यदि संतोष नहीं हो, तो संपत्ति दुख का कारण बन जाती है। संतोषी व्यक्ति को जब सपंत्ति की प्राप्ति होती है, तो वह उसका उपयोग विवेक से करता है।

कितनों को तो खाने को नहीं मिलता, इसलिए दुखी रहते हैं। पर कितने ही ऐसे भी हैं, जो अधिक खाकर अजीर्ण से पीड़ित रहते हैं।

'लक्ष्मी' माता है। उसका उपयोग तो किया जा सकता है, पर उसका स्वामी नहीं बना जा सकता। उसका भोग नहीं करना है।

पाप का जनक लोभ

'लक्ष्मी' मेरी है, ऐसा समझने वाले को लक्ष्मी मारती है। पर लक्ष्मी नारायण की है, ऐसा समझने वाले का उद्धार करती है। वृद्धावस्था में क्रोध और काम तो शांत होते हैं, पर लोभ बढ़ता है। लोभ पाप का जनक है। पाप बढ़ने पर लोग दुखी होते हैं।

लोभ को संतोष से जीतो। मनुष्य जब सोचता है कि मुझे कम मिला है, तभी पाप करता है, इसलिए जो भी मिला है, वह मेरी योग्यता से अधिक है, ऐसा समझकर संतोष रखो, जिससे पाप न करना पड़े। जो संतोष से लोभ को मारता , उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर रहती है। मन को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म जरूरी है। मन से पूछो कि मुझे जो मिला है- क्या मैं उसके योग्य हूं? इस पर जब विचार करोगे, तो लगेगा कि जीव ने बहुत पाप किए हैं।

जीव जब देता है, तो उसके देने में संकोच रहता है। पर ईश्वर जब देता है, तो उसमें कोई संकोच-सीमा नहीं रहती। भगवान से यदि कोई दूसरी वस्तु मांगोगे, तो उसे देकर वे छिटक जाएंगे, इसलिए उनसे तो स्वयं उन्हें छोड़कर अन्य वस्तु की याचना ही न करो।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

03 फरवरी से 09 फरवरी 2026 तक

03 फरवरी (मंगलवार) : फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि रात्रि 12.41 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि। गंडमूल रात्रि 10.11 मिनट तक।

04 फरवरी (बुधवार) : फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि रात्रि 12.10 मिनट तक पश्चात चतुर्थी तिथि। भद्रा दोपहर 12.26 मिनट से रात्रि 12.10 मिनट तक।

05 फरवरी (गुरुवार) : फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि रात्रि 12.23 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि। श्री गणेश चतुर्थी व्रत।

06 फरवरी (शुक्रवार) : फाल्गुन कृष्ण पंचमी तिथि रात्रि 01.19 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि।

07 फरवरी (शनिवार) : फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 02.55 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि। भद्रा रात्रि 02.55 मिनट से।

08 फरवरी (रविवार) : फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि रात्रि 05.02 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक पश्चात अष्टमी तिथि। भद्रा अपराह्न 03.59 मिनट तक। श्रीनाथ उत्सव।

09 फरवरी (सोमवार) : फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि (दिन–रात)। जानकी व्रत।

–पं. ऋभुकांत गोस्वामी

उदारता और सेवा सर्वोत्तम धर्म

यक्ष-युधिष्ठिर संवाद

दुर्योधन को गंधर्व चित्रसेन के बंधन से मुक्त कराकर पांडव द्वैत वन वापस आ गए। उसी समय एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास आकर बोला- 'महाराज, मैंने अरणियों के साथ अपना सामान एक वृक्ष पर टांगा हुआ था। एक मृग उसे लेकर भाग गया है। आप उसे वापस दिलाने की कृपा करें।' युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए पहले जल पीने के लिए कहा और नकुल से जल लाने के लिए कहा।'

समीप ही एक जल कुंड था। नकुल ने कुंड में जैसे ही पात्र डाला, सरोवर से आवाज आई- 'ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल ले सकते हो।' नकुल ने उस आवाज की अनसुनी करते हुए पानी लेना चाहा। आवाज लगाने वाले यक्ष ने तुरंत उसे अचेत कर दिया। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम भी क्रम से पानी भरने आए और यक्ष के प्रश्नों की ओर ध्यान न देने के कारण अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर आए। उनसे भी यक्ष ने वही बात कही। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष से प्रश्न पूछने के लिए कहा।

यक्ष : धर्म का एकमात्र साधन क्या है? यश प्राप्ति व स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है?

युधिष्ठिर : दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है। दान यश का एकमात्र उपाय है। सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन है।

यक्ष : मनुष्य की आत्मा कौन है? भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र कौन है? युधिष्ठिर : पुत्र मनुष्य की आत्मा है। पत्नी भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है।

यक्ष : सर्वोत्तम लाभ व सुख क्या है? युधिष्ठिर : निरोगता सर्वोत्तम लाभ है। संतोष सर्वोत्तम सुख है।

यक्ष : धर्म से बढ़कर क्या है? कौन-सा धर्म सर्वोत्तम है? वह क्या है, जिसको नियंत्रण करके प्रसन्नता होती है? किनके साथ मित्रता करके दुख नहीं होता?

युधिष्ठिर : उदारता धर्म से बढ़कर है। सेवा सर्वोत्तम धर्म है। मन का नियंत्रण करके प्रसन्नता होती है। सज्जनों की मित्रता से कभी दुख नहीं होता।

यक्ष : किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? किस वस्तु के त्याग से शोक नहीं होता?

युधिष्ठिर : अहंकार के त्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध के त्याग से शोक नहीं होता।

यक्ष : तप का लक्षण क्या है? सबसे बड़ी क्षमा क्या है? युधिष्ठिर : स्वधर्म का पालन ही तपस्या है। सुख-दुख को सहन करना सबसे बड़ी क्षमा है।

यक्ष : दुर्जय शत्रु कौन है? अंत न होने वाली बीमारी क्या है?

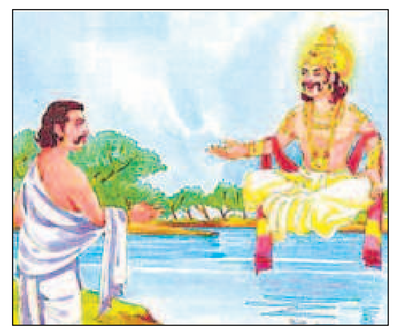

युधिष्ठिर : क्रोध दुर्जय शत्रु है। लोभ कभी समाप्त न होनेवाली बीमारी है।

यक्ष : सबसे बड़ा स्नान व दान क्या है?

युधिष्ठिर : मनोविकारों का त्याग सबसे बड़ा स्नान है। प्राणी की रक्षा ही सबसे बड़ा दान है।

यक्ष : उत्तम मार्ग क्या है? सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति कौन है?

युधिष्ठिर : सज्जनों द्वारा सेवन किया मार्ग उत्तम मार्ग है। जो परिवार के साथ प्रसन्न रहता है, वही सबसे प्रसन्न व्यक्ति है।

युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इनसे प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया।

डॉ. रवींद्र नागर

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

वाणी को वश में रखें भावनाओं में न बहें

कुंभ राशि में बुध-राहु की युति का बारह राशियों पर क्या प्रभाव होगा?

–उपदेश पाण्डेय, कानपुर

आज रात्रि 09.54 मिनट पर बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से मौजूद राहु से बुध की युति होगी। इससे 'जड़त्व' योग बनेगा। यह कुछ राशियों के लिए शुभ, कुछ के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। बुध-राहु युति 11 अप्रैल, 2026 की रात्रि 01.20 मिनट तक रहेगी। इस दौरान बुध 26 फरवरी से 21 मार्च, 2026 तक वक्री रहेंगे। आइए जानते हैं, बुध-राहु युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेष : आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। लेनदारी देनदारी का निपटारा। नए कार्य में संलग्नता। मानसिक अशांति रहेगी।
वृष : तरक्की। मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आर्थिक लाभ। कुछ रुके काम बनेंगे।
मिथुन : भाग्य का साथ। छोटी-लंबी यात्रा। धार्मिक पर्यटन या विदेश यात्रा। रुके धन की वापसी। नई खरीदारी।
कर्क : मानसिक अशांति। स्वास्थ्य समस्या। दुर्घटना। आर्थिक हानि।
सिंह : साझेदारी। वैवाहिक जीवन एवं मित्रता में मतभेद। संयमित व्यवहार से कुछ रुके काम बनेंगे।
कन्या : स्वास्थ्य समस्या। कुछ

विवादित मामलों में सफलता। निवेश संबंधी मामलों में सफलता।
तुला : रुके काम बनेंगे। संतान से जुड़े मांगलिक कार्य। खर्च की अधिकता।
वृश्चिक : निवास या कार्य स्थल में परिवर्तन। माता का स्वास्थ्य बाधित। पूंजी निवेश में सतर्कता हितकर।
धनु : मांगलिक कार्य। चल संपत्ति की खरीद। कार्य स्थल पर नई जिम्मेदारी।
मकर : नए संबंध-संपर्क। पुराने लेन-देन एवं विवादित मामलों में राहत। घर में मांगलिक कार्य होंगे।
कुंभ : अचानक धन लाभ। मानसिक अशांति। स्वास्थ्य समस्या। बड़े निर्णय को टालें।
मीन : स्वास्थ्य, मरम्मत एवं खरीदारी पर खर्च की अधिकता। परिवार-साझेदारी में मतभेद।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन–मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी–24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर–16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301 (उत्तर प्रदेश)

गुनाहों की माफी मांगने और उनसे दूर रहने का दिन

शब-ए-बारात (03 फरवरी)

शब–ए–बारात मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे चंद्र दर्शन के अनुसार मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 15वीं (शब) रात को मनाया जाता है।

पैगंबर-ए-इस्लाम ने फरमाया कि 'रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा। रमजान मेरी उम्मत का महीना है।' इस रात में इबादत करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। लोगों के अमाल (कर्म) रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। शब-ए-बारात एक फारसी शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है- शब यानी रात और बारात यानी मुक्ति (छुटकारा) मतलब गुनाहों से छुटकारे की रात। ये रात उन खास रातों में एक होती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कुबूल करता है।

इस्लामिक धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात को क्षमा (माफी) के रूप में देखा जाता है, जब मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और आने वाले पवित्र माह रमजान के लिए खुद को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से हलवा व अन्य मीठे व्यंजन बनाकर रिश्तेदारों और गरीबों में बांटें जाते हैं। मस्जिदों, कब्रिस्तानों व दरगाहों की साफ-सफाई की जाती है।

शब-ए-बारात बेहद फजीलत वाली रात अल्लाह से दया (रहम) और अपने पापों (गुनाहों) की माफी मांगने की रात मानी जाती है। उलेमा फरमाते हैं कि मुसलमानों को शब-ए-बारात की रात अल्लाह का जिक्र, कुरआन की तिलावत, अस्तग्फारऔर नमाज पढ़ने में गुजारनी चाहिए।

इस रात की इबादत और अगले दिन का रोजा (ये रोजा फर्ज नहीं बल्कि निफल होता है) अल्लाह को बहुत पसंद है। मुसलमानों को शब-ए-बारात की रात को खासकर नौजवानों को बिना किसी हुड़दंग और शोरशराबे के मनाना चाहिए। इस रात को मुसलमान मस्जिदों, घरों में इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं।

इस दिन केवल अल्लाह की ही इबादत नहीं की जाती है, बल्कि जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी कब्र पर जाकर रातभर दुआ की जाती है। फूल पेश कर उनको याद किया जाता है। कब्रिस्तानों में रोशनी की जाती है और दुनिया को अलविदा कह गए अपनों के लिए माफी की दुआएं की जाती हैं। कब्र के मुर्दों को इस रात अल्लाह पाक आजाद कर देता है।

मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि वो इस दिन अपने घर की ओर रुख करते हैं, इसीलिए शब-ए-बारात के दिन घर में मीठा बनाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि यह वह रात है, जब अल्लाह आने वाले वर्ष के लिए नियति निर्धारित करता है। सालभर के होने वाले तमाम काम बांटे जाते हैं। जैसे किसका जन्म (पैदाइश) होगा, किसकी मृत्यु (इंतकाल) होगी, किसे कितनी रोजी मिलेगी आदि। हर इंसान के गुनाहों और अच्छाइयों का लेखा-जोखा भी इसी रात को होता है।

शब-ए-बारात मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण रात है। यह क्षमा (माफी) और आत्मचिंतन की रात है। मुसलमान इस रात अल्लाह का जिक्र, कुरआन की तिलावत और नमाज पढ़ने में गुजारे। साथ ही ज्यादा-से-ज्यादा गरीब, बेसहारा, बेवाओं (विधवाओं) और यतीमों (अनाथ) की सदका व खैरात से मदद करते हुए अल्लाह की इबादत करे। इसके साथ-साथ मुसलमान सामाजिक बुराइयों जैसे झूठ, ईर्ष्या-द्वेष, शराब, सूद, लड़ाई-झगड़े से दूर रहने का संकल्प ले।

–नासिर कुरैशी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। खर्च भी बढ़ेंगे।

वृष : धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार में भागदौड़ भी अधिक रहेगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मिथुन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

कर्क : मन परेशान तो रहेगा, परंतु वाणी में मधुरता रहेगी। फिर भी धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर बढ़ सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं। सचेत रहें। कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

धनु : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध व वाद-विवाद से बचें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आय में वृद्धि भी होगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे।

मकर : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी।

मीन : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार विस्तार के लिए माता से धन मिल सकता है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

03 फरवरी, मंगलवार, **शक संवत्:** 14 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 21 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 14 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि रात्रि 12.41 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, मघा नक्षत्र रात्रि 10.11 मिनट तक पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शोभन योग रात्रि 02.39 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, तैतिल करण। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन–रात)। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक तक राहुकालम्। गंडमूल रात्रि 10.11 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम एक घर बना रहे हैं। कृपया इसका नक्शा देखकर बताएं कि क्या यह ठीक है?

–निर्माण गहलौत, ऋषिकेश

■ आपके प्लॉट का दक्षिण पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा कटा हुआ है। ऐसे प्लॉट पर घर बनाना उचित नहीं होगा। आपकी बिल्डिंग का मुख्य द्वार अंतरिक्ष नामक पद पर है। इससे घर में चोरी होने की संभावना रहती है। प्लॉट में बिल्डिंग पूर्व एवं उत्तर की ओर है। इसे दक्षिण एवं पश्चिम की ओर शिफ्ट करें या फिर आप प्लॉट के बीच में भी ले सकते हैं। मुख्य द्वार के पास कॉमन टॉयलेट बना है। यह ठीक नहीं होता। आपके मास्टर बेडरूम में पांच कोने है। यह ठीक नहीं है। कमरे को चार कोनों का ही रखें।

वर्ग पहेली : 8229

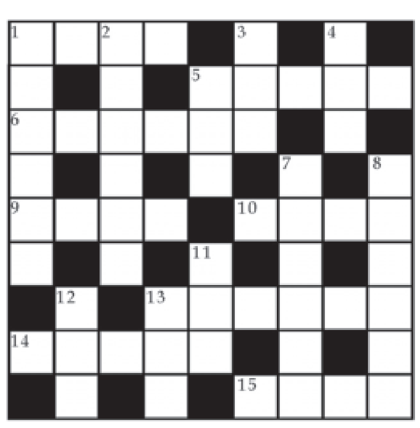

बाएं से दाएं
1. उदरस्थ करना; खाना; निगलना; हड़पना (4)
5. भेंट हो जाना; मिलन हो जाना; उलझ जाना (3,2)
6. जानवरों को काबू करने के लिए उनके नाक में रस्सी डालना; बस में करना (3,3)
9. कहानी; कहावत; किस्सा; अफवाह; उड़ती खबर; किंवदंती (4)
10. कारागृह; कैदखाना; बंदीगृह; बंदीघर (4)
13. अभ्यास करना; काम सिद्ध करना; आराधना करना; उपासना करना (3,3)
14. क्षमा देना; जाने देना; माफ करना (2,3)
15. आदान-प्रदान; परस्परता; लेन-देन;संबंध (2,2)

ऊपर से नीचे
1. दूसरे का धन हजम करना; खयानत करना; घपला करना; घोटाला करना (3,3)
2. सुंदर नेत्रों वाला; राजीव लोचन; कृष्ण (6)
3. आपत्ति करना; एतराज करना; चलने के समय रोक कर कुछ पूछना; दोष देखना; हस्तक्षेप करना; देगचा; बड़ा घड़ा (3)
4. रूई से भरी ओढ़नी (3)
5. अपने स्थान से हटना; खिसकना; निश्चित तिथि बदलना; स्थगित होना (3)
7. कटु आलोचना करना; किसी के बारे में बुरी-बुरी बातें कहना; किसी के संबंध में , खराब बातें बताना; निंदा करना (3,3)
8. आज्ञापत्र देना; किसी प्रकार के अधिकार या अनुमति का सूचक पत्र देना (4,2)
11. पाक करना; भोजन बनाना; पकाना (3)
12. मानदंड; मापने वाला; मद्यपान का पात्र (3)
13. अंबुज; कमल; एक सुंदर पक्षी; चंद्रमा (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8228

प	ति	त	पा	व	न	■	अ	■
रा	■	म	■	ज्ञ	■	प	व	न
ग	ल	त	फ	ह	मी	■	हे	■
ना	■	मा	■	स्त	■	त	ल	वा
■	श	ह	र	■	सी	प	ना	■
क	प	ट	■	ज	■	स्या	■	जा
■	थ	■	वि	ल	य	क	र	ना
जे	ले	बी	■	धा	■	र	■	मा
■	ना	■	स	रा	ह	ना	हो	ना

सुडोकू : 8211

*कठिन

	9				3			6
	4				8		5	
		2			5			
8				6		9		2
4		3		7				5
			1			7		
	3		9				1	
7			8				4	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8210

4	9	3	2	6	7	1	8	5
7	6	5	3	1	8	9	2	4
8	1	2	5	9	4	3	7	6
1	8	4	7	2	6	5	9	3
2	5	7	1	3	9	6	4	8
6	3	9	8	4	5	2	1	7
3	2	8	4	5	1	7	6	9
9	7	1	6	8	3	4	5	2
5	4	6	9	7	2	8	3	1

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, टैरिफ कम होने पर कपड़ा, फार्मा और आईटी जैसे क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

अमेरिकी शुल्क में कटौती का निर्यात क्षेत्र को मिलेगा लाभ

उम्मीद

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कहा है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर सहमति बनी है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका भारत पर लगने वाला जवाबी शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।

अमेरिकी शुल्क में कटौती का निर्यात क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ऐसे में संभावना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द हो सकेगा। समझौते होने पर व्यापारिक रूप से दोनों पक्षों को लाभ होगा। भारत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान अवधि में 60.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। इस तरह से चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात में 9.75 प्रतिशत का उछाल आया है। निर्यात के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर रहा है, जबकि उसके बाद यूएई और फिर चीन का नंबर आता है लेकिन यूएई और चीन को होने वाले निर्यात (क्रमशः 28.92 और 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) अमेरिकी की तुलना में बेहद कम रही है। निर्यात क्षेत्र के नजरिए से अमेरिका हमारे सामान का सबसे बड़ा खरीदार है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए वर्ष 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

दोनों देशों को इन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ

अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा निवेश और तकनीक को भी लाभ मिलेगा। साथ भारत आमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होने की संभावना है।

1 व्यापार में स्थिरता
टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होने से भारत-अमेरिका व्यापार अधिक सुगम और स्थिर हो सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा।

2 ऊर्जा सुरक्षा पर असर
अमेरिका से तेल और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ने से भारत को वैकल्पिक सप्लाई स्रोत मिलेंगे। हालांकि रूसी तेल से सस्ता विकल्प मिलना चुनौती हो सकता है।

3 निवेश और तकनीक
अमेरिका से तकनीक और निवेश बढ़ने की संभावना है, जिससे भारत के विनिर्माण, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल क्षेत्र को फायदा हो सकता है।

4 भू-राजनैतिक संतुलन
अमेरिका के साथ व्यापार और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होने से भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हो सकती है। जो हाल में ठीक नहीं चल रही थी।

65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया भारत ने चालू वित्त वर्ष में

60 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था 2024-25 में

महीनेवार निर्यात की स्थिति

महीना	2024-25	2025-26
अप्रैल	7.22	8.38
मई	7.68	8.83
जून	6.64	8.27
जुलाई	6.26	8.00
अगस्त	6.41	6.83
सितंबर	5.43	6.21
अक्टूबर	6.27	6.90
नवंबर	5.70	6.98
दिसंबर	6.89	7.01

नोट : निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर में है।

टैरिफ कम होने से भारतीय उत्पादों की धमक बढ़ेगी

नई दिल्ली, एजेसी। वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) में कटौती करने की घोषणा की है। इस फैसले से पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को न केवल बड़ी राहत मिली है, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारत में बने उत्पादों की धमक बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती का सबसे सकारात्मक असर रत्न-आभूषण और फार्मा (दवा) क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं और तराशे हुए हीरों का सबसे बड़ा खरीदार है। टैरिफ कम होने से इन उत्पादों की लागत घटेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में इनकी मांग में भारी उछाल आने की संभावना है।

रत्न और आभूषण क्षेत्र जरूरी : यह सेक्टर अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित था। अब शुल्क कम होने से सोने के गहनों और हीरों का निर्यात फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ेगा। सूरत और मुंबई के हीरा व्यापारियों के लिए यह संजीवनी की तरह है।

फार्मास्युटिकल को भी फायदा : भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है। टैरिफ घटने से भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिका में सस्ती होंगी, जिससे आम अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी और भारतीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा।

टेक्सटाइल की मांग बढ़ेगी : रेडीमेड कपड़ों, धागे और कालीनों पर लागत कम होने से भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री अब वियतनाम और बांग्लादेश को कड़ी टक्कर दे सकेगी।

समुद्री उत्पाद को लाभ : फ्रोजन झींगा और मछली के निर्यात पर लगने वाले भारी शुल्क में कमी आएगी। इससे तटीय राज्यों के मछुआरों और सीफूड एक्सपोर्टर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा।

कृषि और खाद्य उत्पाद : कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से भारतीय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

इंजीनियरिंग और ऑटो पाट्र्स के क्षेत्र को फायदा

आयरन, स्टील और एल्युमीनियम के पुर्जों पर टैक्स का बोझ कम होने से भारतीय इंजीनियरिंग फर्मों के लिए नए ऑर्डर के रास्ते खुलेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भी अपने बजट 2026 में चमड़ा और जूता उद्योग के कच्चे माल पर ड्यूटी कम की थी। अब अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने से इस सेक्टर का दोहरा फायदा होगा। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश में लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		
81,666	+943.52	
टॉप गेनर		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
पावर ग्रिड	270.15	7.61
अदाणी पोर्ट्स	1042.90	4.76
टॉप लूजर		
इंफोसिस	1629.00	-1.85
एक्सिस बैंक	1317.85	-1.53

निफ्टी		
25,088	+262.95	
टॉप गेनर		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
पावर ग्रिड	1332.50	3.46
टीएमपीवी	1132.00	2.24
टॉप लूजर		
श्रीराम फाइनेंस	966.00	-3.17
एक्सिस बैंक	1309.20	-2.33

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,52,700	-12,800
चांदी	2,60,000	-52,000

करेंसी

डॉलर/रुपया
91.49 +0.44

कब क्या हुआ

2 अप्रैल, 2025
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक 'लिबरेशन डे' टैरिफ पहल के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 26 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया।

10 अप्रैल, 2025
ट्रंप ने नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की, हालांकि सभी अमेरिकी आयातों पर 10 प्रतिशत का आधारभूत शुल्क लागू रखा गया।

31 जुलाई, 202
ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीद जारी रखा तो अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे।

7 अगस्त, 2025
भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

भारत ने इन देशों के साथ किए एफटीए

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रखा है, जो देश के व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इन समझौतों के जरिए व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाता है और दोनों देशों के लिए लाभकारी बाजार तैयार होता है।

भारत के साथ एफटीए करने वाले प्रमुख देशों और समूहों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, सार्क, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भी फ्री ट्रेड डील की है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, इन समझौतों से भारत को वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

किस पर कितना टैरिफ

देश	टैरिफ
ब्राजील	50%
म्यांमार	40%
श्रीलंका	20%
वियतनाम	20%
बांग्लादेश	20%
पाकिस्तान	19%
थाईलैंड	19%
मलेशिया	19%
अफगानिस्तान	15%
वेनेजुएला	15%
मॉरीशस	15%
जापान	15%

"भारत-अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोनों देशों में अपार संभावनाएं हैं। तकनीक पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिक को फायदा होगा।
- **अश्विनी वैष्णव**, केंद्रीय मंत्री

भारत अब रूस से नहीं, हमसे तेल खरीदेगा : ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा।

- अमेरिका ने कहा, भारत के साथ सहमति बनी
- पहले भारत रूस से खरीदता था सस्ता तेल

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ भी हटाया जा रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते भारत ने सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा, जिससे आयात लागत कम हुई। हालांकि हाल के महीनों में भारत ने रूस से तेल आयात धीमा करना शुरू किया है। जनवरी में यह करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो फरवरी में घटकर लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन और मार्च में 8 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है।

सोना-चांदी-बाजार की चाल बदलेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के टैरिफ में कटौती से वैश्विक व्यापार तनाव घटेगा है और आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिलेगा। इसका सीधा असर निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर पड़ता है, जिससे सोना-चांदी और शेयर बाजार की चाल बदलती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन-सा एसेट फायदे में रहेगा।

सोना और चांदी पर प्रभाव : आमतौर पर ट्रेड टैरिफ और आर्थिक तनाव के समय सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यदि टैरिफ कम होते हैं तो वैश्विक व्यापारिक तनाव कम होगा। इससे निवेशकों का डर कम होगा और वे सोने-चांदी से पैसा निकालकर शेयर बाजार जैसे अधिक रिटर्न वाले एसेट्स में लगा सकते हैं। इससे सोने-चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट या ठहराव आ सकता है।

रुपये की मजबूती: अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करने से भारत का निर्यात बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना-चांदी आयात करता है, इसलिए सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं।

चांदी की मांग : टैरिफ कम होने से वैश्विक विनिर्माण बढ़ता है। चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल में अधिक होता है। इसलिए इसकी औद्योगिक मांग बढ़ सकती है, जो कीमतों को नीचे जाने से रोक सकती है।

भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव

टैरिफ में कटौती शेयर बाजार के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगी निर्यात क्षेत्र में तेजी : आईटी, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और फार्मा जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद अमेरिका में सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। एफआईआई का निवेश बढ़ना : व्यापारिक संबंध सुधरने से विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारतीय बाजार को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे, जिससे बाजार में भारी निवेश आ सकता है। कम टैरिफ का मतलब है बेहतर व्यापारिक गतिविधियां।

देश-दुनिया

एप्सटीन फाइल्स में कई और हस्तियों के नाम

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफ्री एप्सटीन से जुड़े दस्तावेजों में कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम सामने आए हैं। हालांकि इन सभी ने किसी भी प्रकार के यौन अपराध में संलिप्तता से इनकार किया है और किसी पर भी आपराधिक आरोप तय नहीं हुए हैं।

कई दूसरे बड़े नाम भी शामिल : एप्स्टीन फाइल्स में 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक आयोजन समिति के प्रेसीडेंट केसी वासरमैन, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन और इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी पर कोई ना कोई आरोप है, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया है।

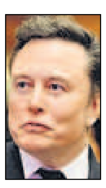

ऐलन मस्क
एपस्टीन फाइल्स में टेस्ला के मालिक ऐलन मस्क का नाम भी शामिल है। ईमेल्स में एपस्टीन के द्वीप पर जाने की चर्चा है, लेकिन मस्क ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि उन्होंने एपस्टीन के निमंत्रण को ठुकरा दिया था।

स्टीवन टिश
एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क जायंट्स फुटबॉल टीम के को-ओनर स्टीवन टिश का नाम भी सैकड़ों बार दर्ज है। टिश ने बताया कि भले ही वो एपस्टीन को जानते थे, लेकिन वो उसके साथ किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं थे।

एंड्रयू विंडसर
ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, फाइल्स में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वर्जीनिया गिउफ्रे ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एपस्टीन ने उन्हें 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।

2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक आयोजन समिति के प्रेसीडेंट केसी वासरमैन का नाम भी शामिल है

- जिन पर भी आरोप है सभी ने इससे साफ इनकार किया है

रिचर्ड ब्रैनसन
वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन का उससे संपर्क रहा। हालांकि, ब्रैनसन की कंपनी ने सफाई दी कि उन्हें एपस्टीन के खिलाफ गंभीर आरोपों की पूरी जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने उससे दूरी बना ली थी।

मिरोस्लाव लाजैक
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लाजैक भी इस लिस्ट का हिस्सा रहे। आरोपों के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लाजैक संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी एप्सटीन से मुलाकात की तस्वीरे सामने आईं थीं।

डीजीसीए ने सीसीआई को सौंपी किराए की जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। डीजीसीए ने सभी शेड्यूल्ड एयरलाइंस की रूट की जानकारी, मार्केट शेयर और औसत किराए सहित कई तरह की जानकारी कॉम्पिटिशन कमीशन को दी है।

कमीशन इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने गलत बिजनेस तरीकों का इस्तेमाल किया। एयरलाइन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन के सवालों के जवाब में, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नीतिगत उपायों की समीक्षा करती रहेगी।

एप्पल की भारत में रिकॉर्ड 28% बाजार हिस्सेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 28 प्रतिशत की अपनी अब तक की सबसे अधिक मूल्य हिस्सेदारी दर्ज की है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार यह उपलब्धि प्रीमियम उपकरणों के बढ़ते चलन के कारण संभव हुई है, जिसमें उपभोक्ता तेजी से महंगे उपकरण चुन रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जहां बिक्री की संख्या में वृद्धि स्थिर है, वहीं बाजार का कुल बिक्री मूल्य बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय खरीदार अब महंगे मॉडल ले रहे हैं। 2024 में भारत में एप्पल की मूल्य हिस्सेदारी 23 प्रतिशत थी।

समस्या | एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर नाराजगी जताई

नदी सुखा सकते हैं, वापस बना नहीं सकते

नई दिल्ली, एजेंसी। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर चिंता जताई है। न्यायाधिकरण ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नदी चैनलों को कुछ पैसे खर्च करके नष्ट या सुखाया जा सकता है, लेकिन भारी रकम खर्च करके भी इन्हें वापस बनाया नहीं जा सकता।

न्यायाधिकरण ने हाल में कानपुर और उन्नाव में अवैध रेत खनन से गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। उसने इस पर सख्ती से रोक लगाने को कहा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही पर नाराजगी

न्यायाधिकरण ने अपनी टिप्पणी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी लापरवाह रहने पर नाराजगी जताई। कहा कि याचिका में प्रस्तुत किए गए तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि खनन कार्य में प्रोजेक्ट प्रमोटर द्वारा पर्यावरण कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

मुख्य सचिव सभी डीएम को निर्देश जारी करें

न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि निष्पादित खनन पट्टे की एक प्रति तुरंत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह बेहद जरूरी है।

बिल्हौर में बांट दी गई गंगा नदी की धारा

न्यायाधिकरण ने कहा कि याचिका से यह भी पता चला कि कानपुर के बिल्हौर में अवैध रेत खनन करने वालों ने गंगा नदी में अवैध पुल बना डाला था। इससे नदी की धारा दो हिस्सों में बंट गई थी। न्यायाधिकरण ने इस पर गहरी चिंता और नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकती थी।

कारपोरेट कॉर्नर

नॉर्दर्न रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रशिक्षण से दक्षता की ओर नाम का तीन दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों के काम करने के तरीकों में नवाचार को बढ़ावा देना देना था। इस दौरान नॉर्दन रेलवे के प्रमुख वित्तीय सलाहकार संजय उप्रेती, रेलवे बोर्ड की सदस्य अपर्णा गर्ग, जनरल मैनेजर एके वर्मा, मंजुषा जैन समेत अन्य मौजूद रहे।

एस. उषा ने निदेशक का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। एस. उषा ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया की निदेशक (मार्केट ऑपरेशन) का पदभार ग्रहण किया है। इस पद को संभालने वाली वह प्रथम महिला अधिकारी हैं। उषा वर्ष 1989 बैच की कालीकट विश्वविद्यालय से बी.टेक (विद्युत अभियांत्रिकी) स्नातक हैं तथा उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।

सेल ने शुरू की खास प्रतियोगिता

नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) लिमिटेड ने सेल-ई-बीआरएटीआईओएन : स्टील से देश निर्माण, सेल है मजबूत भरोसे की पहचान नाम से एक खास प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के जरिए देश के आम नागरिकों को सेल से जुड़ी कहानियों को वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्मों या डिजिटल विज्ञापनों के जरिए दिखाने का मौका दिया जा रहा है। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 है। हर विजेता को 10,000 का इनाम दिया जाएगा।

आईआईटी रोपड़ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए सेना के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किए। एमओए पर मेजर जनरल विक्रम वर्मा और प्रो. राजीव आहूजा, निदेशक आईआईटी रोपड़ ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल (सेवानिवृत्त), प्रो. वीरभद्र सिंह रावत, प्रो. सारंग गुमफेकर, ब्रिगेडियर कौशल पंवार, कर्नल तरुण बड़ोला समेत अन्य मौजूद रहे।

माओरी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की और दिल्ली के साथ सांस्कृतिक पर्यटन संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया। वर्ल्ड एंड अस: न्यूजीलैंड फेस्टिवल -इंडिया चैप्टर के बैनर तले भारत दौरे पर आए आओटेरोआ (न्यूजीलैंड) के एक प्रतिष्ठित माओरी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल ने डीटीटीडी (दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम) के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने तुगलकाबाद जंक्शन केबिन (दिल्ली क्षेत्र) और पलवल सेक्शन पर स्वदेशी कवच प्रणाली के इंस्टॉलेशन का निरीक्षण किया। चार लाइन वाले इस (35 किमी) सेक्शन में 152 मेन लाइन ट्रैक किलोमीटर हैं। उत्तर रेलवे ने कॉरिडोर के पूरे हिस्से में कवच प्रणाली लगाई है, जिसके अंतर्गत प्रमुख स्टेशन यार्ड, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम वाली दो मेन लाइनें शामिल हैं ।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने श्रीनगर से कटरा रेल खंड का गहन निरीक्षण किया। यह निरीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब घाटी भारी बर्फबारी हो रही है। महाप्रबंधक ने श्रीनगर, पंपोर, अनंतनाग और काजीगुंड सहित कई प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया।

गेल ने 5,706 करोड़ रुपये राजस्व बताया

नई दिल्ली। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने बीते नौ महीनों के लिए ऑपरेशन से 1,03,899 करोड़ रुपये का राजस्व बताय। नौ महीनों के लिए टैक्स से पहले लाभ पिछले साल की के 12,123 करोड़ के मुकाबले 7,387 करोड़ रहा और टैक्स के बाद लाभ पिछले साल के 9,263 करोड़ के मुकाबले 5,706 करोड़ रहा।

परिणाम प्रयास के अनुपात में ही प्राप्त होता है

सतही आरोपों की राजनीति

गलवन में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका वह उल्लेख कैसे कर सकते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पर गलतबयानी का आरोप लगाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और वह चल नहीं सका। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेता को सदन में बोलने से रोका गया। हंगामे के पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे इतना तो स्पष्ट ही है कि वे यही सिद्ध करना चाहते थे कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया। राहुल गांधी कितनी तैयारी से आए थे, इसका पता इससे चलता है कि वे संदर्भ तो गलवन का देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख डोकलाम का किया। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

सब जानते हैं कि गलवन में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। इसे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे भी एक नहीं कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। जहां तक उनकी पुस्तक की बात है, तथ्य यही है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है। यह भी एक तथ्य है कि जिस पत्रिका ने इस पुस्तक के कथित अंश छापे हैं और उनकी अपने हिसाब से व्याख्या की है, वह आधे-अधूरे तथ्यों के साथ सनसनी फैलाने के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी।

चिंता की बात

दिल्ली में बड़ी संख्या में किशोरवय लड़के-लड़कियों का लापता होना अत्यंत चिंताजनक है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब ये सामने आता है कि विगत दस वर्षों में दिल्ली में 50 हजार से अधिक किशोर व किशोरियां लापता हुए, जिनमें लड़कियों की संख्या करीब 37 हजार थी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इनकी तलाश कर 44 हजार से अधिक किशोर-किशोरियों का पता लगाया, लेकिन फिर भी अब तक साढ़े चार हजार लड़कियों समेत छह हजार किशोर-किशोरियों का पता नहीं लग पाया है। राजधानी में बड़ी संख्या में बच्चों का लापता होना चिंता की बात है, लेकिन उनमें किशोरियों की संख्या अधिक होना और उनमें भी बड़ी संख्या में किशोरियों का पता नहीं लग पाना गंभीर है।

> राजधानी में पुलिस को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति अधिक गंभीरता से काम करने की जरूरत है

दिल्ली पुलिस लापता बच्चों को ढूंढने में प्रयासरत अवश्य है, ऐसे कई बच्चों का पता भी लगा लिया जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बच्चों का अब भी पता नहीं चल पाया है, जो दर्शाता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस को और काम करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बड़ी संख्या में किशोरियों का लापता होना दर्शाता है कि लड़कियों की सुरक्षा के प्रति अधिक गंभीरता दर्शाने की जरूरत है। बड़ी संख्या में किशोरियों का लापता होना यह भी संदेह पैदा करता है कि कहीं कोई संगठित गिरोह तो इसके पीछे नहीं है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अनिश्चित वैश्विक माहौल में सरकार संतुलित बजट पेश करने में सफल हुई?

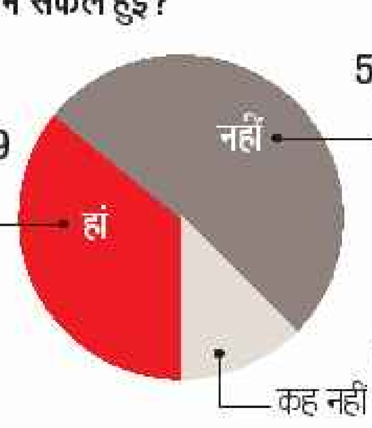

आज का सवाल

क्या आइसीसी को श्रीलंका में भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले के कारण पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुनिश्चित हो रक्षा व्यय की गुणवत्ता

हर्ष वी. पंत

रक्षा व्यय में बढ़े आवंटन के साथ भविष्य की दिशा तो स्पष्ट है, पर यदि इसे सही तरह अमल में नहीं लाया जाता तो क्षमताओं में वृद्धि की गति प्रभावित हो सकती है

आम बजट में रक्षा व्यय में बढ़ोतरी वैश्विक एवं क्षेत्रीय रणनीतिक उथल-पुथल के बीच निरंतरता का ही एक संकेत है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए हैं। इसमें 63,733 करोड़ विमान और एयरो-इंजन के लिए और 25,023 करोड़ नौसेना के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 5.54 लाख करोड़ राजस्व व्यय के लिए हैं। इसमें पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान है। स्पष्ट है कि सरकार ने रक्षा आत्मनिर्भरता के अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। नागरिक, प्रशिक्षण तथा अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और कलपुर्जों को मूल सीमा शुल्क से छूट देने तथा विमान रखरखाव, मरम्मत एवं कायाकल्प में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर शुल्क माफ करने का निर्णय इसका संकेत है कि राजकोषीय नीति को औद्योगिक रणनीति के साथ समन्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उपाय घरेलू एयरोस्पेस निर्माण को मजबूत करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए हैं। विशेष रूप से रक्षा आपूर्ति श्रृंखला की प्रीमियम श्रेणी में यह बात और सटीक बैठती है।

भारत का रक्षा बजट निरंतर बढ़ने पर है, जो देश के जटिल सुरक्षा परिदृश्य के संज्ञान से प्रेरित है। ऐसा परिदृश्य जो उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर तनाव से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। इसलिए पुराने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं अनिवार्यता बन गया है। हमें बढ़ते आवंटन को नई तकनीकों की बढ़ती लागत जैसे तकनीकी पेच में नहीं फंसाना चाहिए। हमें बस यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना है जो आवंटन किया गया है वह प्रभावी ढंग से खर्च भी किया जाए। इसमें व्यय की गुणवत्ता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस दिशा में यह एक अच्छा संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय यानी नई तकनीकों एवं आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच रक्षा पूंजीगत व्यय लगभग 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो पिछले दशक की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। इस क्रम में वेतन, पेंशन और रखरखाव वाले राजस्व व्यय का हिस्सा घटा है। स्पष्ट है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी जैसा सुनियोजित कदम भविष्य की सैन्य क्षमताओं को आकार देने में महती भूमिका निभाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन रणनीतिक रूप से आवश्यक हो गया है। यदि भारत को पारंपरिक सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है तो उन्नत विमानों, पनडुब्बियों, ड्रोन और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताओं में निवेश करना ही होगा।

अवधेश राजपूत

यह अच्छी बात है कि पूंजीगत व्यय बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षित रूप से कम है। याद रखना होगा कि वित्तीय बाधाएं, प्रतिस्पर्धी विकास प्राथमिकताएं और राजस्व व्यय का संरचनात्मक बोझ सैन्य आधुनिकीकरण की गति को सीमित करते हैं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तकनीक की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने होंगे। खास तौर से चीन जैसे देश को देखते हुए, जो अगली पीढ़ी के प्लेटफार्मों, साइबर क्षमताओं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और एआइ सक्षम प्रणालियों में भारत की तुलना में भारी-भरकम खर्च कर रहा है। समय के साथ भारतीय सामरिक नीति-नियंताओं ने भी साइबर, इलेक्ट्रानिक युद्ध, अंतरिक्ष और ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना शुरू किया है, लेकिन इन क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन पारंपरिक प्लेटफार्मों में निवेश की तुलना में कम ही है। यदि भारत को इस अंतर को कम करना है तो रक्षा अनुसंधान और विकास में निरंतर वृद्धि महत्वपूर्ण होगी।

हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर भारत पहल ने भी रक्षा खर्च की संरचना को बदला है। बीते कुछ वर्षों के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत खरीद स्वदेशी स्रोतों के लिए निर्धारित की गई है, जो घरेलू निर्माण क्षमता को विकसित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में दृढ़ता को दर्शाता है। इस रणनीति के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। रक्षा उत्पादन में रिकार्ड तेजी आई है। रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़कर करीब 23,500 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। लगभग 90 देशों को निर्यात से इसमें विविधता भी झलकती है। स्पष्ट है कि ऐसा विकास भारत की रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाते हुए उसके भू-राजनीतिक कद को भी विस्तार देता है। इससे रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी मान्यता मिलती है। इसके बावजूद आत्मनिर्भरता की अपनी सीमाएं हैं। खासतौर से उच्चस्तरीय और अधुनातन तकनीकों एवं हथियारों के मामले में विदेशी निर्भरता कायम है। इस अंतर को पाटने के लिए केवल नीति ही नहीं मंशा भी दिखानी होगी। इसके लिए शोध एवं विकास में निरंतर निवेश, सक्षम इकोसिस्टम और खरीद एवं बजट क्रियान्वयन में व्यापक दक्षता की आवश्यकता होगी। निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद जीडीपी के अनुपात में हमारा रक्षा खर्च अभी भी 2.2 प्रतिशत पर अटका हुआ है। यह स्थिति अन्य वित्तीय दबावों और दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है, लेकिन इस मामले में राजस्व व्यय जैसी प्रतिबद्धता खर्च में लचीलेपन की गुंजाइश को और सीमित करती है। इसलिए तात्कालिक परिचालन आवश्यकताओं और दीर्घकालिक रणनीतिक परिवर्तन के बीच संतुलन साधना भारतीय सामरिक नीति-नियंताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस कसौटी पर रक्षा बजट पारंपरिक विरोधाभासों को भी दर्शाता है, जो महत्वाकांक्षाओं और वित्तीय सीमाओं से जुड़ा है। रक्षा क्षेत्र को बढ़े आवंटन के साथ भविष्य की दिशा तो स्पष्ट है, लेकिन यदि इसे सही तरह से अमल में नहीं लाया जाता तो क्षमताओं में वृद्धि की गति प्रभावित हो सकती है।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

समानता की अनदेखी करने वाले नियम

पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन नियमों का मकसद शैक्षणिक संस्थानों से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, नस्ल या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना था, लेकिन इन नियमों ने व्यापक विवाद को जन्म दिया। सामान्य वर्ग के छात्र इस आशंका से घिर गए कि इन नियमों में उन्हें पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इन नियमों में शिकायत की सत्यता जांचने या झूठी शिकायतों को छांटने का कोई ठोस प्रविधान नहीं दिखता। हर आरोप पर तुरंत समिति बैठाकर तेज कार्रवाई तो तय है, लेकिन साक्ष्य की परख, गवाहों की सुनवाई, गोपनीयता और अपील जैसी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आरोप लगते ही कार्रवाई होने की जल्दी में सही जांच कैसे होगी? यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों और संवैधानिक निष्पक्षता के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएगी? वास्तव में न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि होते दिखना भी चाहिए, अन्यथा भरोसा टूट जाता है।

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

समता का मर्म है सभी के साथ न्याय। कमजोर को ताकत देकर दूसरे को कमजोर करना कोई समाधान नहीं

विवादों के घेरे में आई यूजीसी की पहल ● फाइल

कानूनी दृष्टिकोण से अनुच्छेद-14 के हिसाब से देखें तो यूजीसी के नए नियम समानता के अधिकारों की अनदेखी करते हैं, जबकि अनुच्छेद-15(1) जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रविधान करता है। अदालतों ने कई बार माना है कि गरिमा, निष्पक्षता और उचित प्रक्रियाओं तक पहुंच जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। यदि किसी शिक्षक या छात्र को जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वह अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर ओबीसी में नहीं आता, तो उसके पास बचाव का कोई कानून न होना प्रक्रियात्मक अन्याय है। बड़ी बात यह है कि यूजीसी गाइडलाइन की धाराएं आपस में ही मेल नहीं खातीं। नियम-2 वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव मिटाने की बात करता है, दूसरी और नियम-3(सी) न्याय के अधिकार को केवल कुछ जातियों तक सीमित कर देता है।

पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को 'हतोत्साहित' किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रविधान रखा गया था, लेकिन अंतिम अधिसूचित नियमों में झूठी शिकायतों से संबंधित प्रविधान हटा दिया। वास्तव में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निपटने वाले प्रविधानों को हटाना इस गाइडलाइन के लिए ढांचागत कमजोरी के रूप में सामने आया। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में 60 प्रतिशत विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि इन 60 प्रतिशत विद्यार्थियों में ही कोई किसी का जाति आधारित भेदभाव करता है तो क्या होगा? इस पर ये नियम चुप हैं। जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा-498 ए के तहत कई बार ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां झूठे या गलत मामले दर्ज कराए गए और निर्दोष फंसे, वैसा ही खतरा यूजीसी के समता नियमों में भी दिख रहा था। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इनके दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच सुझाए थे।

दुनिया भर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और शिक्षण प्रणालियां भी विविधता और समानता के सिद्धांत अपनाती हैं। अमेरिका के प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास एक स्वतंत्र इकाई होती है, जो भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। इस जांच प्रक्रिया में शिकायतकर्ता और आरोपित, दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। जांच प्रोटोकाल में साक्ष्यों के मानक, अपील का अवसर, गोपनीयता आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, ताकि न्याय हो भी और होता हुआ दिखे भी। अक्सर वहां बाहरी या तटस्थ जांचकर्ता नियुक्त किया जाता है, रिपोर्ट लिखित रूप में तैयार होती है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। इसी तरह ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी एंटी-डिस्क्रिमिनेशन नीतियां सबके लिए समान होती हैं। कोई भी छात्र यदि उत्पीड़न झेलता है, चाहे वह अल्पसंख्यक समूह का हो या बहुसंख्यक का, उसके लिए शिकायत दर्ज करने और न्याय पाने का प्रविधान होता है। हार्वर्ड, आक्सफोर्ड आदि ने नियमित सेंसिटाइजेशन वर्कशाप, मेंटरिंग प्रोग्राम और डायवर्सिटी कोर्स-वर्क शुरू किए हैं, ताकि छात्र-छात्राओं में पारस्परिक सम्मान एवं संवेदनशीलता विकसित हो। समता का वास्तविक अर्थ है सभी के साथ न्याय। एक कमजोर को ताकत देकर दूसरे को कमजोर करना समाधान नहीं। सभी को साथ लेकर चलना ही टिकाऊ रास्ता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां कानून सबके लिए बराबर होता है। यही हमारे संविधान का मूलभाव है। अगर कहीं सामान्य वर्ग के छात्र के साथ गलत हो रहा है, तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा परिवेश बनाने पर भी काम हो, जहां शिकायत की नौबत कम आए।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम

प्रेम को सभी भावनाओं में सबसे उत्कृष्ट एवं पवित्रतम भाव माना गया है। प्रेम के बिना संसार में सब नीरस लगता है। यह मनुष्य के विचारों, भावनाओं और हृदय की गहराइयों में रचा-बसा होता है, जो कभी भी, कहीं भी और किसी भी माध्यम से परिलक्षित हो जाता है। देखा जाए तो प्रेम भाव सभी प्राणियों के स्वभाव में जन्मजात होता है, जिसकी अभिव्यक्ति के तरीके सभी में भिन्न-भिन्न होते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रेम के भिन्न-भिन्न रूप समाहित हैं। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने माता-पिता और भाई-बहनों से सर्वाधिक प्रेम करता है। इसके पश्चात जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, उसके प्रेम की परिधि का भी विस्तार होता जाता है। फिर उसकी प्रेम-परिधि में संपूर्ण परिवार, प्रियजन, मित्रजन, समाज और राष्ट्र का समावेश होने लगता है।

जितना व्यक्ति का मन और हृदय ग्रंथिमुक्त और विशाल होता है, उतना ही पवित्र प्रेम उसके अंतर्मन में व्यापकता के साथ बसता है। माता-पिता के साथ किया गया प्रेम जन्मजात और रक्त-संबंधित होता है, जो आजन्म निभाने वाला और अटूट होता है। इसमें निःस्वार्थ प्रेम की भावना, आशा और विश्वास निहित होते हैं। भाई-बहनों से किया गया प्रेम स्नेह की डोर से बंधा होता है, जो आपसी कर्तव्यबोध को निभाने के साथ-साथ व्यक्ति के सुख-दुख में साथ देने का भाव और अपनत्व लिए होता है। इसी प्रकार दो अनजान व्यक्तियों का प्रेम पति-पत्नी के संबंध के रूप में परिणत होता है, जो प्रेम, विश्वास, समर्पण और सामंजस्य की धरा पर टिका होता है। इसके अतिरिक्त समाज और राष्ट्र से प्रेम सामाजिक संरचना से तालमेल बिठाने, जीवन-यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा समाज और राष्ट्र के हित में आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा देता है। प्रेम की डोर में बंधकर ही जीवन सार्थक बनता है। इसलिए प्रेम ही मानव जीवन का सार है।

मुकेश ऋषि

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

जमीन पर उतरे बजट

'खास तरह का आम बजट' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। जहां भाजपा और उसके समर्थित दल बजट को अच्छा बता रहे हैं, वहीं विपक्ष और विरोधी पार्टियां इसे नकार रही हैं। जिन राज्यों में गैर-भाजपा सरकारें हैं, वे यह कहकर असंतोष जता रही हैं कि उन्हें बजट में कुछ नहीं मिला। बजट पर सभी की अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बात सब मानेंगे कि बजट कितना भी बढ़िया क्यों न हो, जब तक वह जमीन पर लागू नहीं होगा, तब तक उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है। इसे देखते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट में की गई सभी घोषणाएं इसी वित्त वर्ष में लागू हों। अक्सर देखा गया है कि बजट में की गई घोषणाएं वर्षों तक लटकी रहती हैं, जो उचित नहीं है। केवल इसी बजट से देश का विकास तय हो जाएगा, ऐसा मानना भी सही नहीं है। विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक देश में आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते और कर प्रणाली में इस तरह सुधार नहीं किया जाता कि हर व्यक्ति अपना वाजिब टैक्स सरकार को दे तथा सरकार इस कर राशि का उपयोग उद्योगों और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र की कायापलट के लिए करे। देश के विकास में मुफ्तखोरी भी एक बड़ी बाधा है। सरकारें सरकारी खजाने में जमा टैक्स के एक बड़े हिस्से को मुफ्तखोरी की योजनाओं में बेवजह खर्च कर देती हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। अच्छा होता यदि सरकार बजट में देश को इस प्रवृत्ति से मुक्त करने के कुछ उपाय भी प्रस्तुत करती।

raju09023693142@gmail.com

वेटलैंड का अस्तित्व खतरे में

एक तरफ ग्लेशियरों में जमा बर्फ 26,700 करोड़ टन प्रतिवर्ष की गति से पिघल रही है। जिससे समुद्र में जलस्तर में वृद्धि हो रही है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं क्षरण का खतरा बढ़ रहा है। इससे पेयजल की आपूर्ति में भी कमी हो जाएगी। वन की कटाई भी एक करोड़ से अधिक एकड़ प्रति वर्ष की गति से जारी है। वन क्षेत्र के विस्तार की गति भी कम हुई है। वेटलैंड के क्षेत्रफल में तेजी से गिरावट आ रही है। यह जंगलों की अपेक्षा तिगुनी गति से विलुप्त हो रहे हैं। जो पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। वेटलैंड वह जमीन होती है जो पानी से ढकी रहती है। इसे धरती का स्पंज कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ का पानी सोखती हैं और गंदगी साफ करके हमें साफ पानी देती हैं। यद्यपि आधुनिक तकनीक से इनके क्षरण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर तकनीक काफी नहीं होगी। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त कानून और समाज की सक्रियता नही हुई तो वेटलैंड देश समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विकास के नाम पर पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ें आ रही हैं। इन्हीं सब कारणों के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग में तेजी होती जा रही है। मानव के अस्तित्व पर भी संकट दिख रहा है। हर वर्ष ग्लोबल वार्मिंग पर मंथन किया जाता है, लेकिन उस पर पूरे देश सामूहिक रूप से प्रयास नहीं कर रहे हैं।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

गगनयान आत्मनिर्भरता का प्रतीक

भारत आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसका आत्मविश्वास आकाश से भी ऊंचा दिखाई देता है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन की तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल सपने देखने वाला देश नहीं रहा बल्कि उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इससे पहले प्रस्तावित मानवरहित मिशन भारत की वैज्ञानिक सोच अनुशासन और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम की शुरुआत 2027 से होगी और उससे पहले तीन मानवरहित मिशन पूरे किए जाएंगे। यह रणनीति बताती है कि भारत किसी भी सफलता को जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठोस तैयारी और कठोर परीक्षण के बाद ही हासिल करना चाहता है। अंतरिक्ष यात्रा में मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि होती है और भारत इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से समझता है। मानवरहित गगनयान मिशन भारत की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यह पूरे कार्यक्रम की नींव है। इसमें प्रयुक्त हर प्रणाली हर तकनीक और हर यंत्र की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। राकेट प्रणाली हो या कैप्सूल नियंत्रण तंत्र हो या पुनः प्रवेश प्रणाली हर स्तर पर शत प्रतिशत सफलता का लक्ष्य रखा गया है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की परिपक्वता और वैश्विक मानकों के अनुरूप सोच को दर्शाता है। गगनयान का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में मानव भेजना नहीं है बल्कि यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

X पोस्ट

केंद्र सरकार ने आम बजट में अपना काम कर दिया है। अब गेंद रिजर्व बैंक के पाले में है। सरकार के वित्तीय अनुशासन को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति को नीतिगत दरों में कटौती करनी ही चाहिए।

हर्ष गुप्ता मधुसूदन@harshmadhusudan

नेताओं का एक वर्ग है जो वैसे तो शेयर बाजार के प्रदर्शन को अर्थव्यवस्था को मापने का कोई पैमाना नहीं मानता, लेकिन जब बाजार में तेज गिरावट आती है तो एकाएक उन्हें अर्थव्यवस्था में उसके महत्व की अनुभूति होने लगती है।

मिलिंद देवड़ा@milinddeora

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किसी तरह की दृढ़ता का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय टीम के हाथों एक और करारी हार की शर्मिंदगी से बचने का उपाय अधिक लगता है।

शिवानी शुक्ला@iShivani_Shukla

अगर एपस्टीन फाइल्स की जानकारियों में लेशमात्र भी सच्चाई है तो अमेरिकी सत्ता के गलियारे कुछ और नहीं, बल्कि मध्यकालीन मुगल हरम के ही आधुनिक संस्करण नजर आते हैं। विकास सारस्वत@VikasSaraswat

जनपथ

कितनी हमने पाक को दे दी दान जमीन,
कितनी भारतवर्ष से छीन ले गया चीन ?
छीन ले गया चीन कौन था तब का मुखिया,
यदि चर्चा छिड़ जाय उधड़ जाएगी बखिया !
हे नेता प्रतिपक्ष बहस करते हो इतनी,
नेहरू जी ने भूमि गंवाई बोलो कितनी ??

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 200

दिल्ली में किशोरों से ज्यादा लापता हो रहीं किशोरियां

कई-कई वर्ष तक पुलिस नहीं लगा पा रही लापता बच्चों का पता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : देश की राजधानी से हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे शामिल हैं, जिनकी तलाश के लिए उनके स्वजन वर्षों तक थाने चौकी के चक्कर काटने के बाद घर बैठ जाते हैं। लेकिन, पुलिस उनका पता नहीं लगा पाती है। चिंता की बात ये है कि इसमें सर्वाधिक संख्या 12 से 18 साल की किशोरियों की है, जो घर से बाहर जाने के बाद वापस नहीं लौटीं। कुछ दिनों तक तो इन किशोरियों के माता-पिता इस उम्मीद में दरवाजे को ताकते हैं कि शायद उनकी बेटी लौटेगी। लेकिन, उनके हाथ जब हर दिन निराशा लगती है तो वह मान लेते हैं कि उनकी बेटी किसी मानव तस्करी करने वाले गिरोह का शिकार हो चुकी है। बेटियां ही नहीं राजधानी में बेटे भी लापता हो रहे हैं, जिनमें से कुछ मिल रहे हैं तो कुछ के स्वजन वर्षों से इंतजार ही कर रहे हैं।

वर्ष 2025 की बात करें तो एक साल में 12 से 18 साल के 1111 किशोर और 3970 किशोरियां लापता हुई हैं। इनमें से 238 किशोर और 1013 किशोरियों का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। इसी तरह 2026 में एक जनवरी से 15 जनवरी तक 12 से 18 साल के 31 किशोर और 138 किशोरियां लापता हो गई हैं। इसमें से 12 किशोर और 109 किशोरियों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है।

संपादकीय » चिंता की बात

हर दिन लापता हो रहे हैं राजधानी से 63 लोग

10 वर्षों में सभी आयु वर्ग के आंकड़ों को देखा जाए तो दिल्ली से कुल 2,55,432 लोग लापता हुए, जिनमें 2,01,455 को पुलिस ने ढूंढ लिया। 53,977 अभी तक लापता हैं। इसमें करीब 37 हजार किशोरियां शामिल हैं। यानी इन 10 वर्षों में रोजाना करीब 63 लोग गायब हुए हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इनकी तलाश कर 44 हजार से अधिक किशोर-किशोरियों का पता लगाया, लेकिन फिर भी अब तक साढ़े चार हजार लड़कियों समेत छह हजार किशोर-किशोरियों का पता नहीं लग पाया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 18 हजार से अधिक किशोर-किशोरियां लापता हुए, जिनमें लड़कियों की संख्या साढ़े दस हजार से अधिक थी। इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस द्वारा जारी 15 जनवरी तक के आंकड़ों में कुल 800 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 169 किशोरियों समेत 509 लड़कियां हैं।, विशेष आयुक्त, क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि लापता बच्चों के मसले पर दिल्ली पुलिस लगातार गंभीरता से काम करती है। गुमशुदा बच्चों को लगातार ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं।

डरा रहे हैं ये आंकड़े

राजधानी से लापता होने वाले अधिकांश बच्चे भले सीधे मानव तस्करी गिरोह के शिकार नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली में कई राज्यों से तस्करी करके बच्चों को लाया जाता है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था जस्ट राइट्स फार चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रविकांत की मानें तो एक अप्रैल 2023 से 29 जनवरी 2026 तक दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 6,759 नाबालिगों को मुक्त कराया गया, जिनमें 2,134 लड़कियां और 3,281 लड़के शामिल थे। इस अवधि में दिल्ली में 2,407 मानव तस्करी के केस दर्ज हुए। ये बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल आदि राज्यों से लाए गए थे। चिंता की बात ये है कि मुक्त कराए गए बच्चे लालच, धोखे और धमकी के कारण गिरोहों के जाल में फंसे थे।

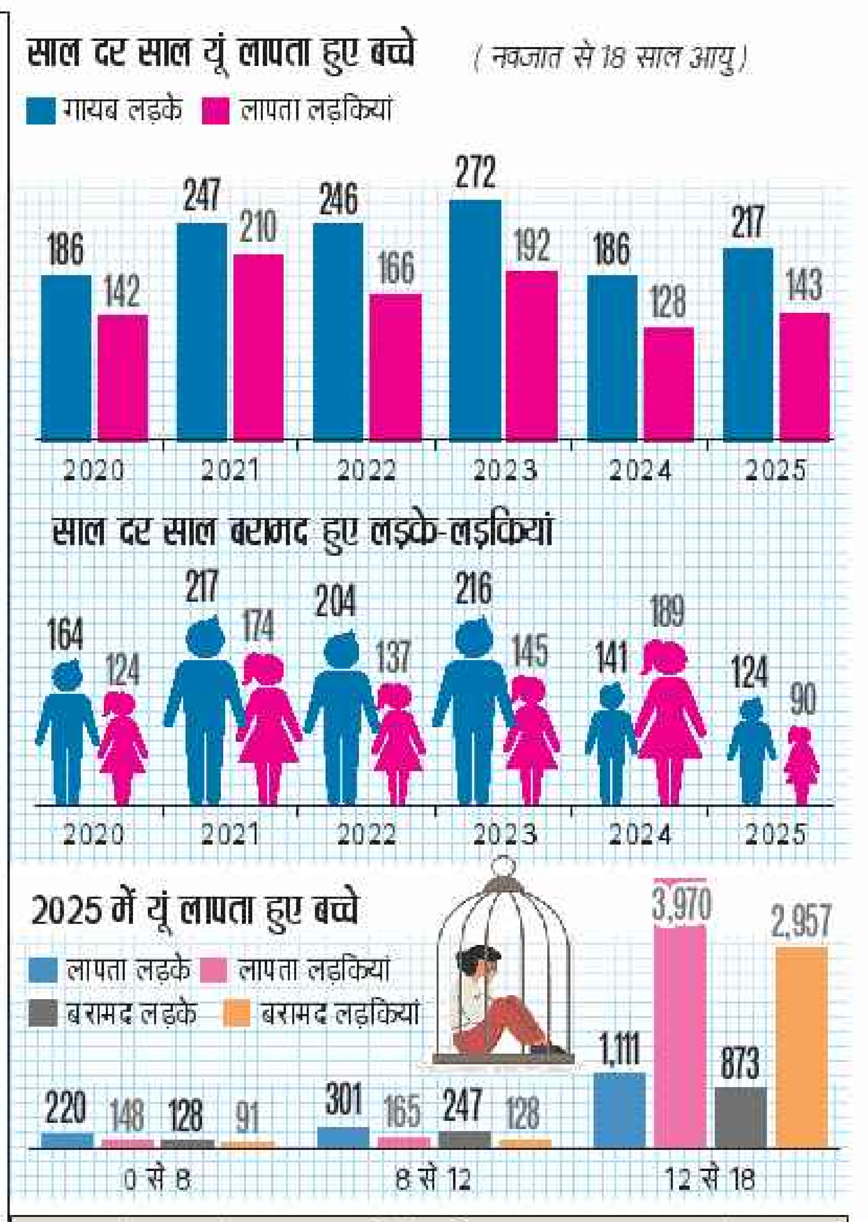

2026 में एक से 15 जनवरी के बीच यूं लापता हुए बच्चे

उम्र	लापता लड़के	लापता लड़कियां	बरामद लड़के	बरामद लड़कियां
0 से 8	6	3	3	0
8 से 12	8	5	3	0
12 से 18	31	138	19	29

हरि नगर में जाम हुए नाले की सफाई करे पीडब्ल्यूडी : एनजीटी

हरि नगर में हनुमान पार्क के बाहर पीडब्ल्यूडी का नाला ● जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: हरि नगर स्थित हनुमान पार्क के समीप जाम नाले की सफाई करने का एनजीटी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है। गंदगी को लेकर दायर शिकायत पर एनजीटी ने पाया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया और पार्क के पास सड़क पर कचरा फैला है। साथ ही मुख्य सड़क का नाला भी कचरे के कारण जाम पाया गया। वहीं, एमसीडी ने रिपोर्ट में कहा कि जर्जर डंपिंग यार्ड को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कचरा डालने पर 5000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं, नाले का रखरखाव पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है।

उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई करने का

छह सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट एनजीटी रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने का दिया निर्देश

आदेश दिया। एनजीटी ने रिकार्ड पर लिया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की है। एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी को सफाई का कार्य कर छह सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर मामले को दोबारा पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। स्थानीय निवासी गुलदीप भाटिया ने शिकायत में कहा था कि हरि नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास एक डंपिंग यार्ड था और इसे हरित पट्टी क्षेत्र में बनाया गया था।

चार साल में सबसे ठंडी रही दो फरवरी, अब बढ़ेगा तापमान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली : रविवार को दिल्ली में फरवरी की शुरुआत दो साल में सबसे ठंडी रही तो सोमवार (2 फरवरी) का दिन चार सालों के दौरान इस महीने का सबसे ठंडा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान फरवरी 2022 के बाद सबसे कम रहा। हालांकि, आने वाले दिनों में धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले के मुकाबले इसमें 7.1 डिग्री की गिरावट आई। सोमवार को यह 24.6 डिग्री रहा था। दूसरी तरफ फरवरी में यह चार साल का सबसे कम अधिकतम तापमान है। इससे पहले तीन फरवरी 2022 को यह 14.4 डिग्री गया था। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 100 से 86 प्रतिशत रहा। राजघाट दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सोमवार को सुबह के समय मध्यम से घने कोहरे ने परेशान किया। इससे दृश्यता भी प्रभावित हुई। सुबह आठ से साढ़े आठ बजे के बीच आइजीआइ एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर महज 100 मीटर तक रह गया। मौसम विज्ञानियों ने अधिकतम तापमान में इस बड़ी गिरावट की वजह दिन भर बादल छाए रहना बताया। बादल छाने रहने से ही कोहरा भी गहराया। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 20 डिग्री और 08 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

सोमवार को बढ़ी ठंड के साथ छाए कोहरे में सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर पटपड़गंज के समीप धीमी गति आवागमन करते वाहन ● ध्रुव प्रकाश मिश्र

सोमवार को कहां कितना रहा तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

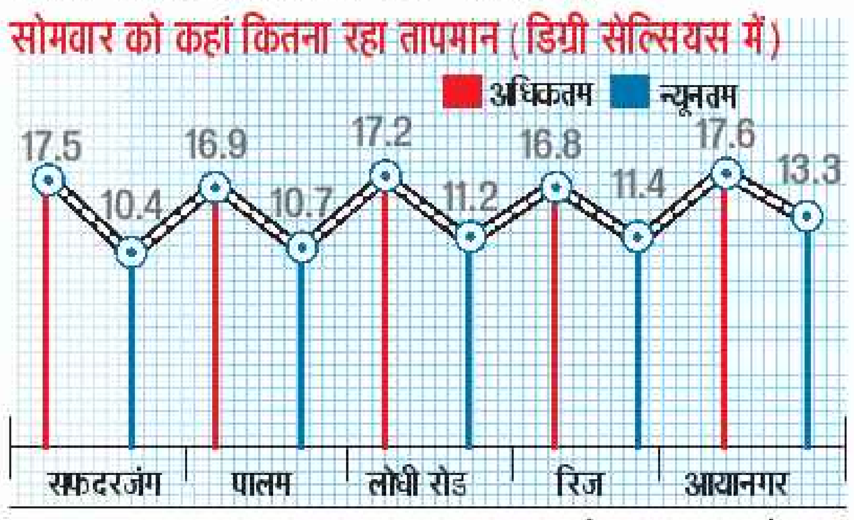

कोहरा से 220 उड़ानों में देरी, 40 रद

जासं, नई दिल्ली : एनसीआर में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया था। इससे आइजीआइ एयरपोर्ट पर हवाई यातायात चरमरा गया। सुबह से शाम छह बजे तक 220 उड़ानों के परिचालन में देरी हुई, जबकि 40 उड़ानें रद हुईं। इसके अलावा, कम दृश्यता के चलते 10 विमानों को जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ की ओर डायवर्ट करना पड़ा।

सोमवार तड़के चार बजे से सुबह नौ बजे के बीच रनवे पर दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिसने परिचालन ठप कर दिया। दोपहर 12 बजे बाद धूप निकलने से दृश्यता में सुधार हुआ और यह बढ़कर 500 से 800 मीटर तक पहुंची, जिससे लैंडिंग प्रक्रिया में कुछ तेजी आई। हालांकि, सुबह के भारी बैकलाग के कारण रनवे पर विमानों की लंबी कतार लग गई है, जिससे उड़ानों को प्रस्थान के लिए 3-4 घंटे का इंतजार करना पड़ा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) ने दोपहर में एक्स पर यात्रियों एडवायजरी जारी की, इसमें कहा कि उत्तर भारत के हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण परिचालन प्रभावित हुआ है। सूत्र बताते हैं कि नए ड्यूटी समय सीमा के नियम ने भी रद उड़ानों की संख्या बढ़ाने का काम किया। उड़ानों को प्रस्थान के लिए, तीन-चार घंटे इंतजार करने से कई एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स की ड्यूटी समय सीमा समाप्त हो गई थी। ऐसे में कनेक्टिंग विमान दिल्ली नहीं पहुंचने पर आखिरी समय में उड़ानें रद कर दी गईं।

दिल्ली के प्रदूषण में आई थोड़ी और कमी

राज्य, जागरण ● नई दिल्ली : राजधानी के प्रदूषण स्तर में सोमवार को थोड़ी और गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की गति कम होने के कारण वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण सोमवार सुबह प्रदूषण के स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सुबह दस बजे दिल्ली का एक्यूआइ 184 पहुंच गया था। यानी हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंच गई थी। लेकिन, बाद में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई। शाम चार बजे तक औसत एक्यूआइ 210 पहुंच गया। एक दिन पहले यह 265 के स्तर पर रहा था।

चार वर्ष बाद नींद से जागा दिल्ली जल बोर्ड, सर्वहित अपार्टमेंट से लिए पानी के सैंपल

जागरण प्रभाव

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली: द्वारका के सेक्टर-17 में स्थित सर्वहित अपार्टमेंट के लोग चार वर्ष से दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना करते रहे हैं। एक फरवरी को दैनिक जागरण ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों की टीम अपार्टमेंट पहुंची। जल बोर्ड की टीम ने पानी के सैंपल लिए। जल बोर्ड की टीम का नेतृत्व जूनियर इंजीनियर मोहित कटारिया और नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग की टीम का नेतृत्व हंसराज मीणा कर रहे थे।

दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम की दोनों टीमें सोमवार शाम पानी की आपूर्ति के समय पहुंची थीं, ताकि जलापूर्ति के समय ही लोगों के घरों में जाकर पानी के सैंपल लिए जा सकें। जल बोर्ड के इंजीनियर मोहित कटारिया ने बताया कि पानी में मौजूद हानिकारिक तत्वों की जांच करने के लिए सैंपल लिए गए हैं। जल बोर्ड के कार्यपालक अभियंता हंसराज मीणा ने कहा कि लोगों की समस्या के निदान के लिए दिन में टीम को मौके का मुआयना करने भेजा गया था। उन्होंने माना कि कालोनी की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है। अपार्टमेंट के लोगों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि कालोनी में जल्द मुख्य पाइपलाइन बदली जाएगी।

सर्वहित अपार्टमेंट में 800 परिवार रहते हैं। दूषित जलापूर्ति होने से कई लोग पेट व चर्मरोग की बीमारी की चपेट में आए थे। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए दैनिक जागरण का आभार जताया है।

समस्या के समाधान के लिए मांगा एक सप्ताह का समय : स्थानीय लोगों ने बताया कि इस अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। तब से अब तक मुख्य सप्लाई लाइन को नहीं बदला गया है। इसमें जगह-जगह लीकेज होने से इसमें सीवर और नाले के गंदा पानी मिल जाता है। वहीं उनके घरों में पहुंचता है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीवर और दिल्ली नगर निगम के नाले के गंदा पानी अपार्टमेंट में बनाए गए दिल्ली जल बोर्ड के पिट में जाता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जब टीम जांच कर रही थी, तब भी पिट में सीवर का गंदा पानी पाया गया। पहले अधिकारियों का कहना था कि उसमें सीवर का नहीं, बल्कि अपार्टमेंट में छत से गिरने वाला पानी जाता है। अब जांच के बाद उन्होंने समस्या के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है।

द्वारका सेक्टर 17 के सर्वहित अपार्टमेंट में पानी का सैंपल लेते दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ● जागरण

द्वारका में भी इंदौर जैसी त्रासदी का खौफ, चार साल से हो रही दूषित पानी की आपूर्ति

दूषित जलापूर्ति पर एक फरवरी को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर

1998 में अपार्टमेंट बनने के बाद से अब तक कभी भी नहीं बदली गई पानी की मुख्य पाइपलाइन

सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए विश्व बैंक से मांगी मदद

राब्यू, जागरण. नई दिल्ली: मानसून के दौरान राजधानी में होने वाले जलभराव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार जिस ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम कर रही है, अब उसे लेकर चिंतित है। दरअसल, इस परियोजना के लिए भरकम राशि की जरूरत है, जो करीब 57 हजार करोड़ है। सरकार ने इसके लिए लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है।

दिल्ली सरकार की हाल ही में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। इसमें दिल्ली सरकार ने योजनाएं पेश कीं। विश्व बैंक के अधिकारियों को ड्रेनेज मास्टर प्लान को लागू करने में एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य भागीदार एजेंसियों की भूमिकाओं के बारे में बताया गया और इसे लागू करने की अनुमानित लागत करीब 57,000 करोड़ रुपये के बारे में भी बताया। इस मास्टर प्लान की डीपीआर विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को दी गई है। जिसमें दिल्ली के तीन प्रमुख नाले नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस-यमुना शामिल हैं। बता दें कि बहुप्रतीक्षित ड्रेनेज मास्टर प्लान का पिछले साल सितंबर में मसौदा जारी किया था।

ग्रेनो में फिर नाले में गिरी कार, बाल-बाल बचे कैब सवार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : इंजीनियर युवराज मेहता की मौत बेसमेंट के लिए खोदे गए एक प्लाट में भरे पानी में डूबकर हो गई थी। सिस्टम की लापरवाही से हुई इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोखिम वाले स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा के ठोस उपाय करने का आदेश दिया था। उसके 15 दिन बाद तक भी व्यवस्था नहीं सुधरी है। कासना कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात कोहरे के कारण रास्ता नहीं दिखने फिर एक कार नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में सभी सुरक्षित बच गए।

इटावा निवासी सुनील कुमार ओला टैक्सी कंपनी से जुड़ी कार पर चालक रिजवान के साथ शनिवार रात सेक्टर इकोटेक-छह स्थित ओपो कंपनी की ओर जा रहे थे। भाटी गोलचक्कर के पास घना कोहरा होने से दृश्यता बेहद कम थी। गोलचक्कर पर 90 डिग्री मोड़ है। कोहरे के कारण चालक को यह नहीं दिखा। इससे कार सीधे नाले में जा गिरी। नाले में पानी बेहद कम और बहाव धीमा होने से दोनों कार से बाहर निकल गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे डायल 112 के कर्मियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला तत्काल मौके पर पहुंचे। उस समय कार में कोई नहीं था। पुलिस ने रविवार को क्रेन से कार बाहर निकलवाई। पुलिस ने घटना की जानकारी जिला प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों को दी थी। रविवार को दोनों विभागों के अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच की। यह नाला 90 डिग्री मोड़ पर है, लेकिन बैरिकेडिंग, बैरियर, रिफ्लेक्टर टेप आदि सुरक्षा इंतजाम नहीं थे।

ग्रेटर नोएडा में भाटी गोल चक्कर के पास कार नाले में गिरी कार ● जागरण

कोलकाता राजधानी सहित कई ट्रेनें देरी से रवाना

राब्यू, जागरण। नई दिल्ली: कोहरे के कारण पिछले कुछ दिनों से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी व हमसफर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। सोमवार को करीब 35 ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से दिल्ली के स्टेशनों पर पहुंचीं। कोलकाता राजधानी, दरभंगा हमसफर सहित कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा। दरभंगा हमसफर आठ घंटे, राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस सवा तीन घंटे, कोलकाता राजधानी दो घंटे, बरौनी हमसफर विशेष सवा घंटे के विलंब से रवाना हुई।

फार्म-जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण हेतु
सूरतगढ़ बीकानेर टोल रोड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

	प्रासंगिक विवरण	
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉरपोरेट ऋणग्रस्त का नाम	सूरतगढ़ बीकानेर टोल रोड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन U45400WB2012PTC174476
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	[illegible], 2/3, [illegible], कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत- 700027
3.	वेबसाइट का यूआरएल	[illegible]
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	राजस्थान राज्य में एनएच-62 के [illegible] 172.384 किमी के सूरतगढ़ बीकानेर टोल रोड [illegible]
5.	कॉरपोरेट ऋणग्रस्त के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	16337 पीसीयू (रियायत समझौते के अनुसार, 1-04-2021 [illegible])
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	कॉरपोरेट देनदार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिचालन से 57.23 करोड़ रुपये का राजस्व और 6.79 लाख रुपये की अन्य आय दर्ज की है। (वित्त वर्ष 2023-24 का कुल राजस्व: रुपये 84.34 करोड़)
7.	कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	लगभग 175
8.	[illegible]	गोपनीयता वचनबद्धता प्रस्तुत करने के बाद आवश्यक विवरण cirp.sbtrc@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता कहां उपलब्ध है:	संहिता की धारा 25(2)(h) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता और एक ईमेल cirp.sbtrc@gmail.com पर भेजकर प्राप्त की जा सकती है
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.02.2026
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	28.02.2026
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.03.2026
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10.03.2026
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	15.03.2026
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14.04.2026
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.sbtrc@gmail.com
17.	एमएसएमई के रूप में कॉरपोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण	UDYAM-WB-01-0000380

तिथि: 03.02.2026
स्थान: अहमदाबाद
एसडी/-
प्रवीणचरण प्रफुल्लचरण [illegible]
सूरतगढ़ बीकानेर टोल रोड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (CIRP में)
IBBI रजिस्ट्रेशन नं. IBBI/IPA-002/IP-N00331/2017-2018/10987
पत्राचार के लिए ईमेल: cirp.sbtrc@gmail.com
एएफए मान्य: 31.12.2026 तक

पियर-सी को घरेलू से अंतरराष्ट्रीय में बदलने पर तेजी से हो रहा काम

गौतम कुमार मिश्रा ● जागरण

- आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हो रहा बदलाव
- चार में से एक पियर घरेलू और तीन का अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए किया जाएगा उपयोग

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 (टी-3) पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा बदलाव हो रहा है। टर्मिनल-3 के डोमेस्टिक पियर-सी को इंटरनेशनल आपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। डायल द्वारा किए जा रहे इस बदलाव से टी-3 की अंतराष्ट्रीय यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता में 50% बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे टी-3 की इंटरनेशनल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता दो करोड़ से बढ़कर तीन करोड़ सालाना हो जाएगी। इन दिनों पियर यूज को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में बदलने का काम तेजी से चल रहा है। मार्च में यह काम पूरा हो जाने की संभावना है।

टी-3 के पीयर-सी में इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। ब्रिज को भी बाइफर्केट किया गया है। डायल का कहना है कि घरेलू उड़ानों को धीरे-धीरे अलग-अलग टर्मिनल में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि टी-3 में स्पेस फ्री हो सके। एअर इंडिया ने 26 अक्टूबर 2025 से 60 घरेलू उड़ानों को टी-3 से टी-2 में शिफ्ट कर दिया, जबकि बाकी 120 फ्लाइट्स टी-3 में ही रहेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी घरेलू उड़ानें अब टी-1 से संचालित हो रही हैं। इंडिगो भी अपने आपरेशंस को टी-1, टी-2 और टी-3 में बांट रही हैं। इन सबसे पूर्व टी-2, जो अप्रैल 2025 से अपग्रेडेशन के लिए बंद था, को 26 अक्टूबर 2025 को दोबारा खोला गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में आइजीआइ एयरपोर्ट पर 7.92 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हुई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय यात्री 2.16 करोड़ थे। टी-3, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का केंद्र है, में जगह की कमी महसूस की जा रही थी। टी-3 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रोजाना आवाजाही 67,000 से 68,000 तक पहुंच गई, जो क्षमता से अधिक है। इससे इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर और कनेक्टिंग फ्लाइट्स में समस्या हो रही थी। पियर के उपयोग में बदलाव से इंटरनेशनल ट्रैफिक को बेहतर मैनेज करने में मदद मिलेगी, खासकर बढ़ते इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर और नए रूट्स के साथ। बदलाव के बाद टी-3 में अब तीन इंटरनेशनल पियर्स (ए, बी और सी) होंगे, जबकि एक पियर (डी) डोमेस्टिक के लिए रहेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में पियर एक लंबा गलियारा होता है, जो मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग से जुड़ा होता है। इसमें दोनों तरफ एयरक्राफ्ट पार्क करने के लिए बोर्डिंग गेट्स होते हैं, जहां से यात्री एरोब्रिज से प्लेन में चढ़ते हैं।

आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के पियर-सी पर चल रहा काम ● सौ. सुधी पाठक

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए वेटिंग टाइम होगा कम

विदेशी उड़ानों के इंतजार में बैठे यात्रियों के लिए बदलाव के बाद वेटिंग टाइम कम होगा, क्योंकि विमानों के लिए अधिक गेट्स उपलब्ध होंगे और कुल मिलाकर आइजीआइ एयरपोर्ट की दक्षता बढ़ेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी एयरलाइंस को अधिक स्लाट्स मिल सकेंगे। यह बदलाव एयरपोर्ट के मास्टर प्लान 2026 का हिस्सा है।

व्हीलचेयर के लिए पैसे मांगने पर यात्री ने जताया रोष

जासं, नई दिल्ली: आइजीआइ एयरपोर्ट पर यात्री ने व्हीलचेयर मांगने पर कर्मचारी द्वारा 500 रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली एयरपोर्ट को टैग कर यात्री ने इस कृत्य को शर्मनाक करार दिया। संबंधित वीडियो साझा करते हुए कहा कि उसने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वजन के लिए व्हीलचेयर मांगी, तो कर्मी ने कहा कि अगर इसे पहले से एयरलाइन के माध्यम से बुक नहीं किया है, तो 500 रुपये चार्ज देने होंगे। उसने लिखा 'अगर एडवांस में बुक करो तो फ्री, लेकिन अगर कोई भूल जाए या टेक्नोलाजी नहीं जानता तो क्या होगा। डायल ने कहा, फ्री सर्विस एयरलाइन की जिम्मेदारी है (प्री-बुकिंग पर) और आन-स्पाट पेड है।

बजट 2026-27

सेंसेक्स	सराफा (दिल्ली के भाव) सोना 10 ग्राम	चांदी 1 किलो	डालर ($)
81,666.46	₹1,52,700	₹2,60,000	₹91.49
↑ 943.52	↓ ₹12,800	↓ ₹52,000	↓ ₹0.44

बजट बोल

भारत में डाटा सेंटर इस्तेमाल करने वाला विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए प्रस्तावित लंबी अवधि की कर-छूट वैश्विक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए पसंदीदा जगह के तौर पर देश की स्थिति को मजबूती देगी। इस कर-छूट का आगे चलकर डाटा सेंटर क्षेत्र में बड़ा असर होगा और घरेलू डाटा सेंटर का इस्तेमाल काफी बढ़ जाएगा।- राजेश नांबियार, प्रेसिडेंट, नैसकाम

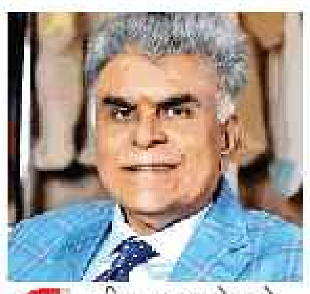

सीमाशुल्क से जुड़े सुधारों और कागजी प्रक्रिया को आसान बनाने से लेनदेन लागत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी। इससे निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी होगी। भरोसेमंद आयातकों की पहचान, कार्गो सत्यापन में कमी और इलेक्ट्रानिक सीलिंग का इस्तेमाल करके फैक्ट्री से पोर्ट तक क्लीयरेंस जैसे उपायों से लाजिस्टिक्स लागत घटेगी। **ए. शक्तिवेल**, चेयरमैन, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

पूंजीगत खर्च में 22.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, फ्रेट कारिडोर और इनलैंड वाटरवेज पर फोकस, और 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम से इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां मजबूत होंगी। इससे कारोबारी लाजिस्टिक्स में सुधार आएगा जिससे स्टील की डिमांड को समर्थन मिलने की उम्मीद है। **नवीन जिंदल**, प्रेसिडेंट, इंडियन स्टील एसोसिएशन

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर ग्लास उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के लिए कैपिटल गुड्स पर छूट से घरेलू उत्पादों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग लागत को अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनिश्चितकालीन ड्यूटी छूट कोयला-मुक्त बिजली के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती है। **पवन गर्ग**, संस्थापक, फुजियामा पावर

जीडीपी में ज्यादा योगदान करने वाले राज्यों को होगा अधिक आवंटन

- केंद्र के राजस्व में दक्षिणी राज्यों का हिस्सा कम करने की आशंका गलत साबित हुई
- 16वें वित्त आयोग के मुताबिक- ज्यादा आबादी वाले राज्यों को करने होंगे आर्थिक सुधार

आवंटन में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य

राज्य	आवंटन	वृद्धि
कर्नाटक	63,050	7387
केरल	36,355	6975
गुजरात	57,311	4228
हरियाणा	20,772	4090
पंजाब	30,464	2885

आवंटन में कमी वाले शीर्ष राज्य

राज्य	आवंटन	कमी
मध्य प्रदेश	1,12,134	7677
अरुणाचल प्रदेश	20,665	6151
उत्तर प्रदेश	2,68,911	4884
बंगाल	1,10,119	4701
मेघालय	9631	2076

(राशि करोड़ रुपये में)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उसे लागू करने का जो रोडमैप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया है, उससे दक्षिणी राज्यों की यह आशंका निर्मूल साबित हुई है कि केंद्र के राजस्व में उनका हिस्सा कम करने की चाल चली जा रही है। इसके साथ ही ज्यादा आबादी वाले राज्यों को साफ संकेत दिया गया है कि उन्हें आर्थिक सुधारों को तेज करते हुए इकोनमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

वैसे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है लेकिन आवंटन के नए फार्मूले में जीडीपी में योगदान जैसे नए पैमाने शामिल किए हैं। यानी यह फार्मूला उन राज्यों को अधिक हिस्सेदारी देगा जो राष्ट्रीय जीडीपी में ज्यादा योगदान देते हैं। नया फार्मूला अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगा और इससे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के मुकाबले ज्यादा मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बताया था कि पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए लागू होगी। आयोग ने वर्टिकल डिवोल्यूशन (केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी) को 41 प्रतिशत पर बनाए रखने की सिफारिश की है जबकि होरिजेंटल डिवोल्यूशन (राज्यों के बीच वितरण) के फार्मूले में बदलाव किए गए हैं। नए मानकों में जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, प्रति व्यक्ति आय और राज्य की जीडीपी में योगदान शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आवंटन के आधार में जीडीपी योगदान को स्वीकार करना है। जीडीपी योगदान की वेटेज (फार्मूला तय करने में हिस्सेदारी) 10 प्रतिशत किया गया है जबकि क्षेत्रफल का वेटेज 15 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। जीडीपी योगदान को फार्मूले में पहली बार शामिल किया गया है। बता दें कि दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 15वें वित्त आयोग के बाद यह शिकायत कर रहे थे कि मौजूदा फार्मूला उन्हें जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर मानव विकास सूचकांकों के कारण दंडित करता है। राष्ट्रीय जीडीपी में बड़े योगदान के बावजूद (दक्षिणी राज्यों का कुल जीडीपी में योगदान 30% से अधिक) केंद्रीय कर में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है।

नए फार्मूले में कर्नाटक को मिलेंगे 7,387 करोड़ रुपये अतिरिक्त : अब जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक कर्नाटक को नए फार्मूले की वजह से अतिरिक्त 7,387 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जबकि केरल को 6,975 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। गुजरात और हरियाणा को खासा (क्रमशः 4,228 करोड़ रुपये और 4,090 करोड़ रुपये) अतिरिक्त मिलेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के आवंटन की हिस्सेदारी कम होगी। सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश के आवंटन में 7,677 करोड़ रुपये की होगी। वैसे ज्यादा जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों का कुल हिस्सा अभी भी समग्र तौर पर ज्यादा होगा। लेकिन इन राज्यों पर दबाव बढ़ेगा कि वह अपने विकास दर को तेज करें और राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाएं।

राजस्व घाटा अनुदान खत्म करने से राज्य नहीं होंगे प्रभावित

नई दिल्ली, प्रेट्र: व्यय सचिव वी. वुअल्नाम ने सोमवार को कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान खत्म करने की सिफारिश का राज्यों की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अनुदान कुछ ही राज्यों को मिल रहा है और चालू वित्त वर्ष में इसमें शामिल कुल रकम घटकर सिर्फ 13,000 करोड़ रुपये रह गई है। 16वें वित्त आयोग ने 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच सालों के लिए केंद्रीय टैक्स में राज्यों की 41 प्रतिशत हिस्सेदारी का सुझाव दिया है।

एक साक्षात्कार में वुअल्नाम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने भी राजस्व घाटा अनुदान को धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों की वित्तीय सेहत को एक स्थिर प्लेटफार्म प्रदान करेंगी।

विकसित भारत को चाहिए तीन-चार बड़े बैंक

वित्तीय सेवा सचिव ने कहा- एसबीआइ और एचडीएफसी बैंक में विश्वस्तरीय बैंक बनने की पूरी क्षमता

- बजट में बैंकों के रिफार्म के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का किया गया है एलान
- सरकार बैंकों में एफडीआइ सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर सकती है

मुख्य बातें

- 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 37 लाख करोड़ के क्रेडिट की जरूरत होगी
- अभी देश में 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैंक के कर्ज का हिस्सा नहीं बन पाए
- अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट 256 लाख करोड़, इसे 2030 तक करना चाहते हैं दोगुना

सरकार जीवन बीमा कंपनी एलआइसी में हिस्सेदारी घटाने के लिए अगले वर्ष फालो-आन आफर (एफपीओ) लाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अभी एलआइसी में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 3.5 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये मई 2022 में बेची गई थी, जिससे सरकार को करीब 21 हजार करोड़ रुपये मिले थे।-**एम. नागाराजु**, वित्तीय सेवाओं के सचिव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्तीय सेवा सचिव एम. नागाराजु ने बताया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए तीन-चार बड़े बैंकों की जरूरत है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की तरह भारत में भी वैश्विक स्तर के बैंक होने चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बड़े बैंक के रूप में विकसित हो सकते हैं। एसबीआइ में दुनिया के शीर्ष बैंक बनने की क्षमताएं मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गत रविवार को पेश बजट में बैंकों के रिफार्म के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का एलान किया गया है।

नागाराजु ने बताया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 30 लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था तैयार करनी होगी और इस काम के लिए 37 लाख करोड़ के क्रेडिट की जरूरत होगी। अभी देश में 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैंक के कर्ज का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अभी बैंकों का गैर वित्तीय सेक्टर का क्रेडिट या कर्ज जीडीपी के 56 प्रतिशत के बराबर है जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत काफी अधिक है। हम इस प्रतिशत को जीडीपी के 150 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर सकती है। उन्होंने बताया कि इस पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार किया जा रहा है।

विकसित भारत के लिए बैंकों की बैलेंस शीट को करना होगा दोगुना : नागाराजु ने बताया कि विकसित भारत में बैंकिंग सेक्टर की अहम भूमिका होगी और 30-35 करोड़ लोगों को बैंकिंग्र क्रेडिट का हिस्सा बनाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इसके लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ही बजट में बैंकिंग बदलाव को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की गई है। कमेटी किन-किन बातों का पर विचार करेगी, इसे तय करने के बाद कमेटी का गठन होगा। अभी यह तय नहीं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी। नागाराजु ने बताया कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट को दोगुना करना चाहते हैं, क्योंकि विकसित भारत के लिए हमें कारोबार के लिए सभी को लोन देना होगा। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक की बैलेंस शीट 256 लाख करोड़ की है जिसे वर्ष 2030 तक हम दोगुना करना चाहते हैं।

बैंकों की साइबर चूक की वजह से सिर्फ तीन प्रतिशत फ्राड होते हैं: साइबर फ्राड के बारे में पूछे जाने पर नागाराजु ने बताया कि बैंकों की साइबर चूक की वजह से सिर्फ तीन प्रतिशत फ्राड होते हैं। 70 प्रतिशत फ्राड पोंजी स्कीम की वजह से होता है। लोग लालच में आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों में साइबर सिक्युरिटी अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य किया जा रहा है। बैंकों की तरफ से डिजिटल लेन-देन की सुविधा को विस्तार देने को लेकर नागाराजु ने बताया कि एसबीआइ के योनो एप से ग्राहक सीधे तौर पर भुगतान भी कर सकता है। इस प्रकार से अन्य बैंक भी अपनी-अपनी सेवा का विस्तार कर सकते हैं।

एसटीटी में वृद्धि का मकसद घरों की बचत को सट्टेबाजी से बचाना

- सीईए ने कहा- ट्रांजेक्शन टैक्स में वृद्धि का मकसद राजस्व एकत्र करना नहीं
- एसटीटी में वृद्धि का मकसद डेरिवेटिव मार्केट में प्रणालीगत जोखिम को संभालना

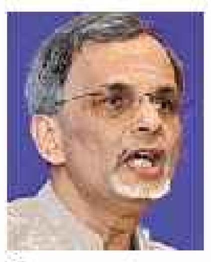

वी अनंत नागेश्वरन

नई दिल्ली, आइएएनएस: मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि बजट में वायदा कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) में वृद्धि का मकसद राजस्व एकत्र करना नहीं है बल्कि घरों की बचत को सट्टेबाजी से बचाना है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए बजट फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत और आप्शंस प्रीमियम और आप्शंस के इस्तेमाल पर मौजूदा दर 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया।

दरअसल, एसटीटी हर लेनदेन पर लगता है, लेकिन ज्यादा टैक्स उन भागीदारों के लिए ट्रेडिंग की लागत बढ़ा देती है जो बार-बार खरीदते और बेचते हैं। इसमें इंट्रा डे स्ट्रैटेजी भी शामिल है, जो टर्नओवर पर निर्भर करती है। रविवार को बजट पेश होने के बाद राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने भी कहा था कि देश की जीडीपी या सिक्योरिटीज मार्केट के आकार की तुलना में एफएंडओ मार्केट में होने वाला कामकाज सट्टेबाजी के दायरे में है। इससे खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। सरकार का इरादा सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है। एसटीटी में वृद्धि का मकसद डेरिवेटिव मार्केट में प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। वाल्यूम की तुलना में ट्रांजेक्शन टैक्स अभी भी मामूली है।

कर सुधारों से विवाद कम करने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली, एएनआइ: राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी सुधारों से करदाताओं को अपनी देनदारियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने, विवादों को कम करने और अपने आकलनों पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की ओर से आयोजित बजट-बाद कार्यक्रम में श्रीवस्ताव ने कहा कि प्रत्यक्ष कराधान में प्रमुख सुधारों को उजागर किया है और आयकर रिटर्न को संशोधित करने की समयसीमा को एक तिमाही बढ़ा दिया गया है। स्पेशल इकोनमिक जोन (एसईजेड) इकाइयों के लिए घरेलू बिक्री पर प्रस्तावित छूट इनको ग्लोबल अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करने के लिए एक 'सीमित समय' के लिए होगी।

वृद्धि संभावनाओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाता है बजट

रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा- बजट में सुधारों की गति को बनाए रखने से निजी निवेश को तेज करने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत का बजट वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक मजबूत पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के साथ सरकारी कर्ज में धीरे-धीरे कमी लाकर व्यापक स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हालांकि, बजट में बड़े सुधारों का एलान नहीं किया गया है, लेकिन रेटिंग एजेंसी का मानना है कि सुधार जारी रहेंगे। फिच ने कहा कि हाल के सुधारों की गति को बनाए रखने से निजी निवेश को तेज करने में मदद मिलेगी और भारत की संभावित वृद्धि को अधिक फायदा और लचीलापन मिलेगा। फिच ने अगले वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर निकट और मध्यम अवधि की संभावनाओं दोनों के लिए सहायक होना चाहिए।

वहीं एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने विश्वास जताया है कि जीएसटी से होने वाली कमाई में गिरावट के बावजूद सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपने 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बजट राजकोषीय अनुशासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। एसएंडपी ने कहा कि घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में मदद केंद्रीय बैंक से लगातार बड़े लाभांश और संभावित पूंजीगत खर्च में कमी से मिलेगी।

रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि उपभोक्ता खर्च और सार्वजनिक निवेश अगले वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2028 में सात प्रतिशत पर बनाए रखेंगे। जीएसटी दरों में कमी और आयकर कटौती जैसे बदलावों से चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में खपत के विकास का एक बड़ा चालक बनकर उभरने की संभावना है।

वृद्धि से जुड़ी प्राथमिकताओं के मजबूत संकेत देता है बजट

नई दिल्ली, एएनआइ: वैश्विक निवेश बैंक मार्गन स्टेनली ने कहा है कि बजट सरकार की वृद्धि से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में एक मजबूत संकेत देता है। यह तकनीक आधारित वृद्धि एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। मार्गन स्टेनली ने भारतीय इक्विटीज पर अपना सकारात्मक नजरिया दोहराया है और अपनी ताजा रिपोर्ट में फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अपना भरोसा फिर से दोहराया है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सेक्टर बजट में वृद्धि समर्थित उपायों और पूंजीगत खर्च पर जोर से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट कर्ज से जीडीपी अनुपात कम करने और राजकोषीय समेकन की धीमी गति को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता है।

भारत का मध्यम अवधि का परिदृश्य सकारात्मक: गोल्डमैन सैक्स

नई दिल्ली, एएनआइ: गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम रखने के संकेत के चलते भारत का मध्यम अवधि का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक कर्ज को कम करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।

रिपोर्ट में बताया कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1% पर बनाए रखा गया है, जिसमें ज्यादा आवंटन इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों के लिए किया गया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा, ''हम इसे लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए एक सकारात्मक संकेत मानते हैं, हालांकि हाल के वर्षों में बजट में आवंटित रकम का उपयोग कुछ हद तक कम रहा है।'

जरूरत पड़ी तो रुपये को संभालने के लिए उठाएंगे कदम

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने सोमवार को कहा कि नियामक के साथ मिलकर सरकार रुपये पर बारीकी से नजर रख रही है और अगर स्थिति ज़्यादा खराब होती है, तो हम देखेंगे कि इसे कैसे संभालना है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया, "डालर के मुकाबले रुपये के 90 से ऊपर जाने पर हर कोई इसके बारे में बात करने लगता है। हम भी इस पर बारीकी से नजर रखने लगते हैं। यह फ्लो का मामला है, और हम इससे प्रभावित होते हैं।" आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 और 22 जनवरी 2026 के बीच रुपया लगभग 6.5 प्रतिशत गिर गया, जिससे यह इस अवधि में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गया। इसकी गिरावट जापानी येन के बराबर थी, जो लगभग 5.5 प्रतिशत गिरा। हालांकि, अन्य एशियाई देशों जैसे फिलीपीन के पेसो और इंडोनेशियाई रुपिया में देखी गई गिरावट से ज्यादा थी।

52 हजार रुपये और सस्ती हुई चांदी, सोना भी लुढ़का

- पिछले तीन सत्रों में चांदी की कीमत 1,44,500 रुपये गिरी
- 12,800 रुपये सस्ता होकर 1,52,700 पर आया सोना

नई दिल्ली, प्रेट्र: कमजोर वैश्विक रुझान और मजबूत डालर के बीच चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही। सोमवार को दिल्ली में यह 52,000 रुपये, या लगभग 17 प्रतिशत गिरकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। शनिवार को यह सफेद धातु 72,500 रुपये (19 प्रतिशत) गिरकर 3.12 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी। पिछले तीन सत्रों में चांदी की कीमतें 1,44,500 रुपये (लगभग 36 प्रतिशत) गिरकर 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम (29 जनवरी) के सर्वकालिक उच्चस्तर से नीचे आ गई हैं।

बिकवाली का असर सोने की कीमत पर भी दिखाई दिया। सोमवार को इसकी कीमत 12,800 रुपये (7.73 प्रतिशत) गिरकर 1,52,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले सत्र में यह 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले तीन सत्रों में यह 30,300 रुपये (लगभग 17 प्रतिशत) गिरकर 29 जनवरी के 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने रिकार्ड उच्चस्तर से नीचे आ गया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटीज के विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बातचीत के बीच डालर में उछाल और अमेरिका व ईरान के बीच तनाव कम होने के साथ अमेरिका में शटडाउन का डर एक बार फिर टल गया है। इसका सोने और चांदी की कीमतों पर असर दिखाई दिया।' वैश्विक बाजार में हाजिर सोना 83.75 डालर गिरकर 4,781.60 डालर प्रति औंस और हाजिर चांदी 1.2 डालर गिरकर 83.49 डालर प्रति औंस रह गई।

जनवरी में मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों में हुआ मामूली सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में जनवरी में मामूली सुधार देखने को मिला। हालांकि नए आर्डर में तेजी से वृद्धि के बावजूद कारोबारी विश्वास साढ़े तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) दिसंबर के दो साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर जनवरी में 55.4 रहा। पीएमआइ की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है।

एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा कि भारतीय विनिर्माण कंपनियों में जनवरी में सुधार देखा गया, जिसका कारण नए आर्डर, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि रही। कच्चे माल की लागत में मध्यम वृद्धि हुई, जबकि 'फैक्ट्री-गेट' कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ी जिससे मैन्यूफैक्चरर्स के मुनाफे पर हल्का दबाव पड़ा।' 'फैक्ट्री-गेट' कीमत का मतलब वह कीमत है जिस पर कोई उत्पाद उसके मैन्यूफैक्चरर के कारखाने या गोदाम से निकलता है।

बजट की गिरावट से उबरे शेयर बाजार, सेंसेक्स 943 अंक उछला

- तेल एवं गैस, बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से एनएसई निफ्टी ने भी लगाई 263 अंकों की छलांग
- कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज गिरावट और मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों में सुधार ने बाजार को दिया समर्थन

मुंबई, प्रेट्र: बजट के दिन भारी गिरावट का सामना करने वाले घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को जोरदार वापसी की। तेल एवं गैस, बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 943.52 अंक यानी 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,666.46 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,009.31 अंक चढ़कर 81,732.25 अंक के उच्चस्तर तक पहुंच गया था। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 262.95 अंक यानी 1.06 प्रतिशत बढ़कर 25,088.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह भी एक समय 282.65 अंक चढ़कर 25,108.10 अंक तक पहुंच गया था।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज गिरावट और बजट के दिन की भारी गिरावट से प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मूल्य-आधारित खरीदारी आने से घरेलू शेयर बाजारों को राहत मिली। जनवरी महीने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में हल्के सुधार के आंकड़ों ने भी बाजार धारणा को समर्थन दिया। पीएमआइ दिसंबर के दो साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर जनवरी में 55.4 रहा। हालांकि, कारोबारी भरोसा साढ़े तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले, रविवार को बजट 2026-27 पेश होने के दिन प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव से शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी। सेंसेक्स 1,546.84 अंक टूटकर 80,722.94 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर रहा था।

पावर ग्रिड में सर्वाधिक 7.61% की तेजी

सेंसेक्स की कंपनियों में से पावर ग्रिड में 7.61 प्रतिशत और अदाणी पोर्ट्स में 4.76 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इनके अलावा, भारत इलेक्ट्रानिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन (यानी इंडिगो), आइसीआइसीआइ बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट भी प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ट्रेंट और टाइटन के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए। क्षेत्रवार सूचकांकों में यूटिलिटी में सर्वाधिक 2.66 प्रतिशत, बिजली में 2.54 प्रतिशत, सेवा में 2.38 प्रतिशत और ऊर्जा में 1.98 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

एसटीटी में बढ़ोतरी और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की अधिक उधारी जुटाने की योजना से बाजार में अस्थिरता बढ़ी थी। हालांकि, बजट में नीतिगत निरंतरता, वृद्धि पर स्पष्ट जोर और राजकोषीय अनुशासन से मध्यम-से-दीर्घकालिक आय को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों से भी बाजार को सहारा मिला। - **विनोद नायर, रिसर्च हेड**, जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

रुपया 44 पैसे चढ़कर 91.49 प्रति डालर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: बजट के एक दिन बाद सोमवार को डालर के मुकाबले रुपया 44 पैसे की मजबूती के साथ 91.49 पर बंद हुआ। रुपये में यह बढ़त मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण देखी गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आरबीआइ 92 रुपये प्रति डालर के स्तर को बचाने के लिए पूरी मजबूती से सक्रिय नजर आया। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के 91.95 पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 91.45 का उच्चस्तर और 91.95 का निचला स्तर छुआ। अंत में रुपया 91.49 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर के मुकाबले 44 पैसे की बढ़त है। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 92.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद यह छह पैसे की मामूली बढ़त के साथ 91.93 पर बंद हुआ था। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बजट ने रुपये को भरोसा दिया है। हालांकि, सरकार की भारी उधारी योजना (17.2 लाख करोड़ रुपये) आने वाले समय में निवेशकों की धारणा पर दबाव डाल सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि निकट भविष्य में अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 91.10 से 91.85 के दायरे में रह सकता है।

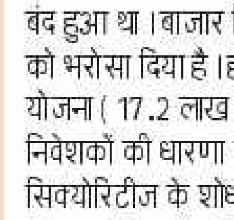

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

चिंतन

संसद की गरिमा बनाए रखना सबका दायित्व

लोकसभा में कांग्रेस सांसद एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी के हालिया भाषण के दौरान हुआ हंगामा केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि इसने संसद की गरिमा, नियमों की मर्यादा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की कथित अप्रकाशित पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के हवाले से चीन की घुसपैठ का जिक्र किए जाने पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद सदन में व्यवस्था बाधित हुई। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यहां सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल अपनी बात मजबूती से रखें, बल्कि स्थापित नियमों, गरिमा और परंपराओं का भी पालन करें। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा अत्यंत संवेदनशील होती है। ऐसे में किसी अप्रकाशित पुस्तक या लीक अंशों के आधार पर बयान देना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि अप्रकाशित सामग्री का हवाला देना सदन के नियमों के खिलाफ है, प्रक्रियात्मक दृष्टि से उचित माना जा सकता है। वहीं, दूसरी ओर, विपक्ष का तर्क भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रतिष्ठित पूर्व सैन्य अधिकारी के कथित अनुभवों के आधार पर सरकार की नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सवालों को सुनना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। अखिलेश यादव का यह कहना कि चीन से जुड़ा मामला देश की सुरक्षा से संबंधित है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्षी दृष्टिकोण को दर्शाता है। असल समस्या यहां "स्रोत की प्रमाणिकता" बनाम "मुद्दे की गंभीरता" की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार-बार नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को संयम बरतने की सलाह दी। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे जो भी तथ्य सदन में रखें, वे निर्विवाद और आधिकारिक हों। प्रियंका गांधी के उदाहरण का उल्लेख कर स्पीकर ने स्पष्ट संकेत दिया कि तथ्य यदि प्रमाणिक हों, तो उन्हें रखने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चीन की घुसपैठ, रेजांग ला, रेचिन ला की घटनाएं और 2020 के तनावपूर्ण हालात देश पहले ही देख चुका है। ऐसे में यदि कोई बयान सेना और सरकार के बीच संवाद को लेकर संदेह पैदा करता है, तो उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक भी हो सकता है। इसी कारण सत्ता पक्ष का यह आग्रह कि ऐसी बातों को सार्वजनिक मंच पर कहने से पहले पूरी तरह सत्यापित किया जाए, समझ में आता है। अग्निवीर योजना को लेकर नरवणे के कथित विचारों का जिक्र भी विवाद का एक अहम बिंदु रहा। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या ऐसे दावे आधिकारिक रूप से उपलब्ध हैं, या केवल लीक अंशों और लेखों पर आधारित हैं? संसद में बहस भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि संसद की गरिमा बनाए रखना केवल स्पीकर या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उसके साथ मर्यादा और नियमों का पालन अनिवार्य है। अंततः, संसद का उद्देश्य हंगामा नहीं, समाधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर, तथ्यपरक और जिम्मेदार चर्चा की आवश्यकता है। तभी संसद अपनी गरिमा बनाए रख सकेगी और लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।

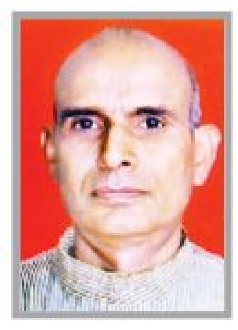

चर्चा
अखिलेश आर्येन्दु

वेनेजुएला-भारत संबंध नई ऊंचाई पर

नरेन्द्र मोदी द्वारा वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर हुई बातचीत चर्चा का विषय बन गई है। जाहिर तौर पर इस वार्ता के बाद सहमतियों को देखते हुए, यह माना जाने लगा है कि इसका परोक्ष असर भारत का रूस पर तेल निर्भरता कम होने के रूप में हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इससे अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में भारत को सहूलियत होगी। वहीं, इस वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी से एअर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

विश्व के बदलते परिदृश्य के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर हुई बातचीत चर्चा का विषय बन गई है। इसकी अधिक चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका द्वारा वहां के पूर्व राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिकी जेल में डालने (और दुनिया के तमाम देशों द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की इस दबंगई की निंदा) के बाद यह माना जा रहा था कि शायद ट्रंप का अगला कदम ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हो सकता है। अभी तक भारत इंतजार करो और देखो की नीति (भूमिका) अपनाए हुए था। ऐसे में अचानक वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से विस्तार से वार्ता पर अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों की निगाहें टिकी हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका को इस वार्ता के जरिए अपना रुख साफ कर दिया है। गौरतलब है कि इस टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

वार्ता मुख्यतः तेल और उसकी धार पर आधारित होने की वजह से भारत को तेल निर्यात करने वाले देश इस वार्ता के बाद भारत के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे हैं। खासकर रूस और अरब देश। यह वार्ता कई मायने में खास मानी जा रही है। जाहिर तौर पर इस वार्ता के बाद सहमतियों को देखते हुए, यह माना जाने लगा है कि इसका परोक्ष असर भारत का रूस पर तेल निर्भरता कम होने के रूप में हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इससे अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में भारत को सहूलियत होगी। वहीं, इस वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी से एअर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यह भी दावा किया कि अब भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। गौरतलब है भारत ने 2019 से वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। यह वह दौर था जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने सेकेंडरी सेंक्शंस भी लगा दिए थे, यानी जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से रोक दिया जाएगा। भारत भी वेनेजुएला से 2019 के पहले अपने तेल आयात का 6 प्रतिशत तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के जरिए वेनेजुएला पर लगाए प्रतिबंध के बाद उसे अपनी तेल आयात नीति में बदलाव करना पड़ा था। अब फिर दोनों देशों में संशोधित नीति के तरह भारत ने अपनी पुरानी नीति को आगे बढ़ाते हुए 30 जनवरी 2026 को तेल खरीदने पर एक नई सहमति बनी है। वैसे भारत ने 2024 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए प्रतिबंध कुछ ढीले किए तो 2023-24 में पुनः तेल खीदना शुरू किया था, लेकिन यह खरीदारी बहुत मामूली थी। तेल के आयात में लगातार वृद्धि होती रही, जो 2025 में बढ़कर तकरीबन 1.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह वह दौर था जब अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर तिरछी नहीं हुई थी। मई 2025 में अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला पर सख्ती बढ़ा दी, तब भारत ने वेनेजुएला से तेल का आयात कम कर दिया। भारत की तेल कंपनियां बगैर अमेरिका से अनुमति लिए वेनेजुएला से सीधे तेल नहीं

खरीद सकतीं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्मेंट और यूएस ट्रेजरी डिपार्मेंट से बातचीत करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 2025 में रिलायंस ने वेनेजुएला से 63,000 बेरल तेल खरीदा था। मार्च 2025 के बाद अमेरिका ने तेल खरीदने का मिला लाइसेंस रद्द कर दिया और वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी-भरकम टैरिफ थोपने की धमकी दी। इसका असर यह हुआ कि मई 2025 के बाद वेनेजुएला से कोई तेल का जहाज भारत के लिए रवाना नहीं हुआ।

अब अप्रत्यक्ष रूप से वेनेजुएला की तेल रिफाइनरियों पर अमेरिका का कब्जा है। ट्रंप अब खुलकर बोलने लगे हैं कि बगैर उसकी अनुमति के कोई भी देश वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा। यदि कोई देश वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो उसकी रकम अमेरिका ही वसूल करेगा। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौंपेंगी और उस तेल को अमेरिका दुनिया के बाजार भाव से बेचेगा। यानी तेल की हर बूंद पर अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। सवाल यह है कि क्या भारत-वेनेजुएला की ताजा सहमति (डील) तेल को लेकर बनी है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति की सहमति से हुई है? यह सवाल इसलिए वाजिब लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि 5 करोड़ बैरल तेल से हुई आय का इस्तेमाल वेनेजुएला-अमेरिका के लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। इसी के साथ सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे तय करेंगे कि वेनेजुएला के लोगों का कल्याण या जरूरत किस तरह की है? भारत वेनेजुएला से आयातित तेल का पैसा किसे सौंपेगा-वेनेजुएला को, या अमेरिका को? यदि अमेरिका को तेल की रकम भारत सौंपता है तो इसका मतलब वेनेजुएला से तेल के संबंध में मोदी और वेनेजुएला की राष्ट्रपति से बातचीत का कोई मायने समझ में नहीं आता है। इसलिए वेनेजुएला के हालात जब तक सामान्य न हो जाएं, तब तक वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, इस पर विचार करने की बेहद जरूरत है।

तेल आयात से निकल कर यदि हम वेनेजुएला से हुई बातचीत से निकले निष्कर्ष पर नज़र डालें तो पाएंगे कि दोनों देश के प्रमुखों ने ऊर्जा, कृषि, विज्ञान, प्रोद्योगिकी, तकनीक, उद्योग, माइनिंग, पर्यटन और आटोमोटिव सेक्टर्स पर विस्तार से चर्चा की। इन्हें 2026 में आगे बढ़ाने पर सहमति भी दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक ट्रंप की कूटनीति साफ नहीं होती और अचानक कुछ भी निर्णय लेने और जबरन भारत या वेनेजुएला पर थोपने का उनका संशय बना रहेगा, तब तक इन सहमतियों पर निर्भीकता के साथ क्या आगे बढ़ना आसान होगा? वेनेजुएला-भारत की हुई सहमतियों को खारिज कर अमेरिका अपनी धमकी वाली नीति लागू कर दे, कौन जानता है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने पर किस तरह ट्रंप टैरिफ सहित किस तरह की धमकियां भारत को देते रहे हैं। भारत की यह नई पहल मामूली नहीं है, ट्रंप यह क्यों चाहेंगे कि भारत सीधे वेनेजुएला से सभी सरह के व्यापारिक हित साधे और उसे नजरअंदाज करे। क्या भारत को वेनेजुएला से आपसी सामरिक हितों की बात करते हुए यह साफ करने की जरूरत नहीं है कि नई सहमतियों को आगे बढ़ाने में संभावित बाधाओं से कैसे पार पाया जाएगा? क्योंकि अमेरिका अभी तेल सहित तमाम मुद्दों पर भारत के हर कदम को अपने निजी हितों से जोड़कर देखेगा, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति को अधिकार देने और उक्त पद पर बिठाने की जैसी नीति अमेरिका की अभी तक रही है, वह तेल देखो और तेल की धार देखो के इर्द-गिर्द रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

सुनील कुमार महला

मीर तकी मीर : दर्द को गीत बनाने वाला शायर

साहित्यकार, उर्दू साहित्य के महानतम शायर मीर तकी मीर (1723–1810) का 3 फरवरी को जन्मदिन मनाया जाता है। मीर तकी मीर सिर्फ़ ग़ज़ल के शायर नहीं थे, वे अपने समय की टूटी हुई रूह की आवाज़ थे। मीर उर्दू ग़ज़ल को शिखर तक पहुंचाने वाले बड़े कवि थे। पाठकों को बताता चलूं कि उन्हें 'ख़ुदा-ए-सुख़न' यानी कि शायरी का ख़ुदा/ भगवान कहा जाता है। उनकी शायरी में दर्द, मोहब्बत, तन्हाई और मानवीय संवेदना गहराई से झलकती है। उर्दू ही नहीं, फ़ारसी भाषा पर भी उनकी मज़बूत पकड़ थी। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फ़ारसी और हिन्दुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य हो। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका जन्म आगरा में तथा मृत्यु लखनऊ में हुई।

मीर तक़ी मीर को उर्दू में शेर कहने का प्रोत्साहन अमरोहा के सैयद सआदत अली ने दिया। उनका मूल नाम मोहम्मद तकी था। उनकी प्रमुख कृतियों की यदि हम यहां पर बात करें तो इनमें क्रमशः ज़िक्र-ए-मीर (आत्मकथा), कुल्लीयते-मीर (उर्दू रचनाओं के छह दीवानों का संग्रह), कुल्लीयते-फ़ारसी (फ़ारसी रचनाओं का संग्रह), फ़ैज़-ए-मीर (पांच कहानियों का संग्रह), नुकत-उस-शूरा (फ़ारसी ज़बान में लिखी तत्कालीन उर्दु रचनाकारों की जीवनियां) आदि को शामिल किया जाता है। वैसे, वे 'दर्द के शायर' कहलाते हैं। दरअसल, मीर की ज़िंदगी मुफ़लिसी (गरीबी), अपनों को खोने के गम और दिल्ली की बर्बादी को देखने में गुजरी। यही वजह है कि उनकी शायरी में 'हूक' और 'टीस' महसूस होती है। उन्होंने खुद एक बार यह कहा था-'मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने, कितने ग़म जमा किए तो दीवान किया।' कहना ग़लत नहीं होगा कि दिल्ली के उजड़ने, परिवार की मौतों, गरीबी और बेघर होने ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। उनकी शायरी दरअसल आत्मकथा की पंक्तियां हैं। उनकी यह पंक्ति देखिए-'पत्थर की भीत क्या करूं, आंसू जो ढल गए।' गौरतलब है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद दिल्ली उजड़ चुकी थी। मीर ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाना तो स्वीकार किया, लेकिन वे वहां दिल से कभी बस नहीं पाए। मीर की सबसे बड़ी खूबी उनकी भाषा थी। वास्तव में, वे बहुत ही आसान शब्दों में दिल की गहरी बात कह देते थे। इसे तकनीकी भाषा में 'सहल़-ए-मुमतऩा' कहा जाता है-यानी ऐसी चीज़ जो देखने में आसान लगे, पर उसे दोबारा लिखना नामुमकिन हो। महान शायर मिर्जा ग़ालिब भी उनके कायल थे। सच तो यह है कि ग़ालिब ने मीर को अपना उस्ताद माना।

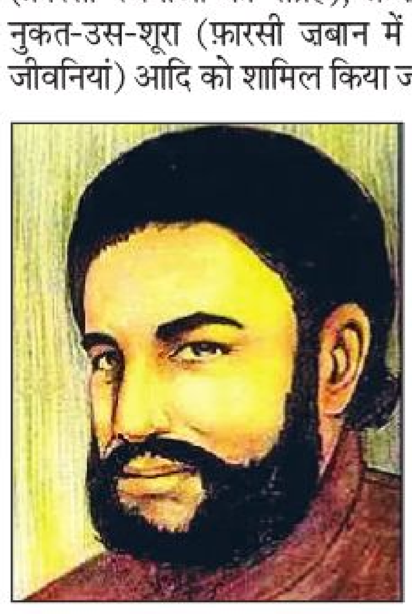

ग़ालिब जैसे आत्मविश्वासी शायर ने कहा-' रेख़्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो ग़ालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था।' वास्तव में यह मीर की श्रेष्ठता की सबसे बड़ी गवाही है। मोहब्बत की कैफियत को बयां करते हुए उन्होंने कहा था-'इब्तिदा-ए-इश्क़ है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।' 'हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है।', 'नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है।', 'मीर उन नीम-बाज़ आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है।' उनकी कुछ अमर पंक्तियों में से एक हैं। आत्म स्वीकृति के बारे में एक बार उन्होंने कहा था -'शायर मुझमें और भी हैं, पर मीर का मुक़ाबला कौन करे।' मीर सिर्फ़ उर्दू ग़ज़ल के शायर ही नहीं, बल्कि अपने समय के टूटे हुए समाज, उजड़ती दिल्ली और बिखरते इंसान की संवेदनाओं के सच्चे दस्तावेज़ हैं।

उनकी शायरी में बनावटी सौंदर्य नजर नहीं आता है। वास्तव में उनकी शायरी जीवन के गहरे ज़ख़्मों से निकली हुई सच्चाई है। अपने जीवन में निजी दुख, मानसिक पीड़ा, गरीबी और उपेक्षा के बावजूद मीर ने उर्दू और फ़ारसी भाषा को आम आदमी के दिल तक पहुंचाया और ग़ज़ल को आत्मा की आवाज़ बना दिया। उनका दर्द रचना है। अन्य शायरों की तरह वे कभी शोर नहीं करते, बल्कि रचनाओं में फुसफुसाते हैं और उनकी वही फुसफुसाहट सदियों बाद भी पाठकों के दिल में उतर जाती है। इसलिए मीर को पढ़ना सिर्फ़ साहित्य का अनुभव नहीं, बल्कि इंसान होने का अनुभव है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हड़बड़ी न करें, क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है!

संकलित
दर्शन

किसी गुरुकुल में गुरुदेव बालकों को बाण चलाना सिखा रहे थे। एक अतिउत्साही शिष्य ने धनुष को इतनी जोर से खींचा कि उसके दो टुकड़े हो गए। गुरुदेव ने शिष्य को ज्ञान दिया कि अधीरता से योग्यता अपव्यय हो जाती है। लक्ष्य को भेदने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे अधिक या कम ऊर्जा का प्रयोग करने पर लक्ष्य को साधना असंभव है। हमारा जीवन भी एक धनुष के समान है। यदि धैर्यपूर्वक ऊर्जा को धीरे-धीरे संचित करने के बाद नियंत्रण के साथ इसे व्यय करने की कला सीख ली जाए तो लक्ष्य कितनी ही दूरी पर क्यों न हो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। धैर्य का अर्थ मूक रहकर मात्र प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है उत्तेजनारहित होकर अपने कार्य में निरंतर संलग्न रहना। किसी कार्य के प्रति अतिउत्साह अथवा असंयम उक्त कार्य के फल को परिपक्व नहीं होने देता। चाक पर चढ़े कच्चे घड़े को यदि आतुरता में समय से पहले उतार लिया जाए तो उसका आकार विकृत हो जाता है। हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि जीवन में प्रगति इतनी धीमी गति से हो रही है कि कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हम परिवर्तन की चाह में धैर्य खो बैठते हैं और शीघ्र सफलता की आकांक्षा में हड़बड़ी में ऐसे निर्णय ले बैठते हैं, जिनसे हमारा भविष्य बिगड़ सकता है। युवाओं में ऊर्जा का अधिक भंडार होता है। यह ऊर्जा उन्हें कार्य को जल्द से जल्द संपादित करके फल प्राप्ति के लिए लालायित करती है। उन्हें इस ऊर्जा का सदुपयोग करना नहीं आता।

अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र है

संकलित
प्रेरणा

एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे धर्मराज उनके कर्मों का लेखा-जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। धर्मराज ने दोनों से कहाः मैं अवसर देता हूं, कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराजः मैंने जीवन भर पापकर्म किए जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे आप जो दंड दें, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला महाराजः मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी फिर डाकू से कहाः तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहाः महाराज! इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ वह क्षुब्ध होकर बोलेः निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मर कर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, और तप को पूर्ण करो।

शिव प्रतिमा

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में सोमवार को खिली धूप वाले में धौलाधार रेंज की बर्फ से ढकी चोटी पर भगवान शिव की बन रही मूर्ति।

आज की पाती

शादियों में लुप्त होती लोक संस्कृति

शादियों में अकसर जो लोकगीत महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, अब यह शादियों में कम ही सुनने को मिलते हैं। यही नहीं कुछ समय पहले तक तो शादी तीन-चार दिन तक चलती थी, सभी रिश्तेदार एक साथ मिल बैठते, इससे रिश्तों की डोर मजबूत होती थी। शादियों में ऐसे लोकगीत महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, जिनमें लोक सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की ख़ुशबू आती थी। लेकिन अफसोस अब हमारी शादियों पर भी पश्चिमी सभ्यता का रंग चढना शुरू हो गया, इस कारण न तो शादियों में वो पुराने लोकगीत सुनने को मिलते और न ही वो खान-पान। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को रिश्तों की कद्र करना सिखानी है, तो हमें अपनी लोक संस्कृति की विरासत को संभालकर रखना होगा।

- मिलींद जोशी, बिलासपुर

ट्रेंड

उल्लेखनीय बढ़ोतरी

दिल्ली में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं के बजट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हम इस बढ़े हुए प्रावधान का अधिकतम लाभ उठाकर हर योजना को तेज गति से जमीन पर उतारेंगे, ताकि दिल्लीवासियों तक पूरा लाभ पहुंचे और विकसित दिल्ली का निर्माण हो पाए।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

स्वास्थ्य सेवा मॉडल

गोवा को वास्तविक स्वास्थ्य सेवा और ईमानदार सरकार की ज़रूरत है जो इसे लागू कर सके। पोंडा टाउन हॉल में, मैंने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी का सिद्ध स्वास्थ्य सेवा मॉडल हर गोवावासी के लिए आशा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल ला सकता है।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

प्रदेश से सौतेलापन

देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई मेंशन न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है। कुल मिलाकर डबल इंजन के बावजूद यह बजट राजस्थान के लिए 'ऊंची दुकान फीका पकवान' साबित हुआ है।

-अशोक गहलौत, पूर्व सीएम, राजस्थान

बजट में नहीं समाधान

मोदी सरकार के पास अब सोच की कमी है, आईडिया खत्म हो गए हैं। आम बजट 2026 भारत की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता है।

-मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

रफाह सीमा क्रॉसिंग सीमित आवागमन के लिए फिर खुली

मिस्र और इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि गाजा की मिस्र से सटी रफाह सीमा क्रॉसिंग सीमित आवाजाही के लिए फिर से खोल दी गई है, जो हमास के साथ संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम है। मिस्र के एक अधिकारी ने बताया कि क्रॉसिंग को खोले जाने के पहले दिन 50 फलस्तीनी आ-जा सकेंगे, लेकिन इसके खुलने के पहले घंटे में किसी को भी वहां से गुजरते नहीं देखा गया। मिस्र के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले लगभग 20,000 फलस्तीनी बच्चे और वयस्क इस सीमा मार्ग से तबाह गाजा से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। क्षेत्र से बाहर रहने वाले हजारों अन्य फलस्तीनी भी इस सीमा मार्ग से प्रवेश करने और अपने घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। मिस्र के सरकारी मीडिया और एक इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने भी सीमा क्रॉसिंग दोबारा खुलने की पुष्टि की। अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर 'एसोसिएटेड प्रेस' को यह जानकारी दी। युद्ध से पहले, रफाह गाजा में आने-जाने वाले लोगों के लिए मुख्य मार्ग था। इस क्षेत्र के कुछ अन्य मार्ग भी हैं जो इजराइल के साथ जुड़ते हैं।

ऑफ बीट

एआई को लिखने और गिनने में क्यों होती है कठिनाई

एआई छवि जनरेटर क्या उत्पादन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, के बीच एक अजीब असमानता बनी हुई है। उदाहरण के लिए, ये उपकरण अक्सर वस्तुओं की गिनती और सटीक पाठ तैयार करने जैसे सरल दिखने वाले कार्यों के लिए संतोषजनक परिणाम नहीं देते हैं। यदि जनरेटिव एआई रचनात्मक अभिव्यक्ति में इतनी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, तो इसे उन कार्यों के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ता है जिन्हें एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी अच्छे से कर सकता है? अंतर्निहित कारणों की खोज से एआई की जटिल संख्यात्मक प्रकृति और इसकी क्षमताओं की बारीकियों पर प्रकाश डालने में मदद मिलती है। लेखन में एआई की सीमाएँ मनुष्य विभिन्न फ़ॉन्ट और लिखावट में लिखे गए पाठ प्रतीकों (जैसे अक्षर, संख्या और चिन्हों) को आसानी से पहचान सकते हैं। हम विभिन्न संदर्भों में भी पाठ तैयार कर सकते हैं, और समझ सकते हैं कि संदर्भ कैसे अर्थ बदल सकता है। वर्तमान एआई छवि जनरेटर में इस अंतर्निहित समझ का अभाव है। उन्हें इस बात की कोई सच्ची समझ नहीं है कि किसी पाठ प्रतीक का क्या मतलब है। ये जनरेटर बड़ी मात्रा में छवि डेटा पर प्रशिक्षित कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर बनाए गए हैं, जिससे वे संबंधों को 'सीखते हैं' और भविष्यवाणियां करते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

एसटीटी में वृद्धि को लेकर बोलीं सीतारमण

खुदरा निवेशकों के 90% से अधिक सट्टेबाजी वाले सौदों में नुकसान से बचाएंगे

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमने केवल वायदा एवं विकल्प व्यापार को ही छुआ है। जिसमें काफी सट्टेबाजी है। मुझे कई लोगों के फोन आए हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भारी नुकसान उठा रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। एफएंडओ में एसटीटी की वृद्धि लोगों के इस क्षेत्र में कदम रखने को हतोत्साहित करेगी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए निवेश को प्राथमिकता दी गई है और राजकोषीय घाटे की स्थिति से पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के एक दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव वैश्विक अनिश्चितता के कारण है और कई केंद्रीय बैंक पीली धातु में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि निवेशकों को किसी एक विशेष मुद्रा पर भरोसा नहीं है और इसीलिए सोने की खरीदारी में होड़ मची है।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव वैश्विक अनिश्चितता के कारण

सार्वजनिक कंपनियों के अधिक विनिवेश को प्रोत्साहित करेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सेबी ने भी सट्टेबाजी रोकने के लिए कदम उठाए

वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह सट्टेबाजी वाले वायदा एवं विकल्प कारोबार में कदम रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि सेबी के अध्ययन के अनुसार, वायदा एवं विकल्प खंड में खुदरा निवेशकों के 90 प्रतिशत से अधिक सौदों में नुकसान होता है। पूंजी बाजार नियामक ने अतीत में इस तरह के लेन-देन को कम करने के लिए कदम भी उठाए हैं। सीतारमण ने कहा कि हमने केवल वायदा एवं विकल्प व्यापार को ही छुआ है। जिसमें काफी सट्टेबाजी है। मुझे कई लोगों के फोन आए हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भारी नुकसान उठा रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे से संतुष्ट

सीतारमण ने कहा कि बजट में राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चलते हुए, अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जबकि मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए यह 4.4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है, इसलिए मैं 4.3 प्रतिशत के घाटे के लक्ष्य से संतुष्ट हूं।

आईडीबीआई बैंक का विनिवेश सही दिशा में

वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण की गति जारी रहेगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिक विनिवेश को प्रोत्साहित करेगी। आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश सही दिशा में है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिस्सेदारी की बिक्री की गति गैर-कर राजस्व की दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जीएसटी दर में कटौती और आयकर छूट सीमा में वृद्धि के कारण हाल ही में निजी उपभोग में जो वृद्धि हुई है, वह आगे भी जारी रहेगी।

आईबीसी संशोधन विधेयक बजट सत्र के दूसरे चरण में

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दिवाला कानून में प्रस्तावित संशोधन समयबद्धता और दक्षता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही भारत की ऋण शोधन व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम गतिविधियों के अनुरूप बनाएंगे।

खबर संक्षेप

पुणे पोर्श हादसे में तीन आरोपियों को जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पोर्श कार हादसा मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय होती है, क्योंकि वे अपने नाबालिग बच्चों पर सही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

4 जगहों पर शिंदे गुट की महिला प्रत्याशी मेयर

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर नगर निगमों में मेयर पद के लिए महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन पदों पर कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। एकनाथ शिंदे ने बयान में यह जानकारी दी है।

बिट्स पिलानी कैंपस में छात्रा ने की आत्महत्या

गोवा। दक्षिण गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में एक छात्रा के कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय छात्रा इंजीनियरिंग की तीसरे वर्ष की छात्रा थी। वह रविवार देर रात अपने हॉस्टल कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई। पुलिस को रात 11:00 बजे सूचना मिली।

जावेद बोले धर्म से नैतिक समाज नहीं बनता

नई दिल्ली। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मैं धार्मिक लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, जो आमतौर पर अच्छे इंसान भी होते हैं। हालांकि, धर्म अपने आप में जरूरी रूप से नैतिक समाज पैदा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ धर्म ही नैतिक व्यक्ति बनाता तो मिडिल ईस्ट ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया होता।

‘संघ यात्रा के 100 वर्ष - नए क्षितिज’ विषय पर एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉ. भागवत बोले

अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करना सरकार की ‘जिम्मेदारी’

आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए

एजेंसी ⏭ हैदराबाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना सरकार की जिम्मेदारी है। भागवत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देश अपने-अपने हितों से चलते हैं, भारत को भी बिना किसी समझौते के अपने हितों के अनुसार अपनी राह तय करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आरएसएस की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, भागवत ने शहर की अपनी यात्रा के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को आयोजित ‘संघ यात्रा के 100 वर्ष - नए क्षितिज’ विषय पर एक कार्यक्रम में शिरकत की और फिल्मी हस्तियों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों से मुलाकात की।

संघ का हिस्सा बनकर अनुभव प्राप्त करें

देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना सरकार की जिम्मेदारी है और नागरिक इसे अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं। भागवत ने कहा कि दुनिया में जारी ‘उथल-पुथल’ के परिणामों का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां की पारिवारिक व्यवस्था, सोने की बचत और आर्थिक गतिविधियां परिवार-उन्मुख हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए संघ का हिस्सा बनकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए।

खास बातें

- भारत बिना किसी समझौते के अपनी राह तय करें
- राष्ट्र के विकास में नागरिक अपनी भूमिका निभाएं

सतही तौर पर हमें गलत समझता जाता

उन्होंने कहा कि यदि कोई आरएसएस को सतही तौर पर समझता है, तो उसे गलत समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संघ इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्र के विकास में नागरिकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जबकि सरकारें, पार्टियां और नेता अपनी भूमिका निभाते हैं। विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है कि संघ का सिद्धांत उत्कृष्ट राष्ट्र-निर्माण के उद्देश्य के साथ व्यक्तिगत विकास है।

पंच परिवर्तन पर की चर्चा

डॉ. मोहन भागवत ने राष्ट्र की व्यापक प्रगति के लिए आरएसएस द्वारा परिकल्पित ‘पंच परिवर्तन’ के बारे में विस्तार से चर्चा की। भागवत ने इसके पांच घटकों - कुटुंब प्रबोधन (पारिवारिक जागरण), पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी।

कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरन बोले

बांग्लादेशियों को पता लगाकर वापस भेजने अभियान चलाएंगे

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि राज्य से बांग्लादेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। परमेश्वर ने विधानसभा में कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों को बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार जिम्मेदार

भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत में प्रवेश करते हैं और कोलकाता से फैल जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा की देखरेख कौन करता है? हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)। वे इतनी आसानी से देश में प्रवेश कैसे कर लेते हैं? क्या यह सबसे बुनियादी सवाल नहीं है?

8 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गयाः हिमंत

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कछार जिले से आठ घुसपैठियों को वापस पड़ोसी देश बांग्लादेश भेज दिया गया है। सीएम ने कहा कि प्रत्येक अवैध प्रवासी की पहचान कर उसे उसके देश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि किसी भी अवैध घुसपैठिये को बख्शा नहीं जाएगा, हर किसी को हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना होगा और उन्हें बिना किसी औपचारिकता के उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कछार से आठ घुसपैठियों को वापस भेजा गया। कोई समझौता नहीं, त्वरित कार्रवाई।

एलन मस्क की पोस्ट का जिक्र कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा दावा...भारत को नंबर 1 बनाएंगे

दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की ‘धाक’ बढ़ी, ग्लोबल जीडीपी में भारत का 17% योगदान

ग्लोबल जीडीपी के विकास में भारत का योगदान अमेरिका से ज्यादा

निर्मला सीतारमण

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

ग्लोबल जीडीपी में भारत और अन्य देशों के योगदान की चर्चा हो रही है। 31 जनवरी को वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी-भारत समेत कई देशों के ग्लोबल जीडीपी में योगदान के आंकड़े बताए गए। लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर हैं और ग्लोबल जीडीपी में भारत का योगदान 17 प्रतिशत है।

वहीं पहले नंबर पर चीन है, जिसका योगदान 26.6 प्रतिशत है, वहीं अमेरिका तीसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट को एलन मस्क ने री-ट्वीट किया और कैप्शन लिखा कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के बारे में बताते हुए इसे और मजबूत करने एवं भारत को नंबर एक योगदानकर्ता बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है।

26-17 का गैप है और इस गैप को जल्दी ही पाटकर दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे. विपक्ष को देश की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स ने अपनी पोस्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) को क्रेडिट देते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जीडीपी के विकास में भारत का योगदान अमेरिका से ज्यादा है और चीन का योगदार भारत से ज्यादा है, यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मिलकर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 43.6% योगदान दे रही हैं।

सत्ता का संतुलन बदल रहा

स्पेसएक्स सीईओ और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स की पोस्ट को अपने एक्स हैंडल पर री-शेयर किया और कैप्शन लिखा कि सत्ता का संतुलन बदल रहा है। आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ में योगदान देने वाले टॉप-10 देशों में चीन का योगदान 26.6, भारत का योगदान 17, अमेरिका का योगदान 9.9, इंडोनेशिया का योगदान 3.8, तुर्किये का योगदान 2.2,सऊदी अरब का योगदान 1.7, वियतनाम का योगदान 1.6, नाइजीरिया का योगदान 1.5, ब्राजील सत्ता का संतुलन बदल रहा का योगदान 1.5, जर्मनी का योगदान 0.9 प्रतिशत है।

आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान

पूर्व मंत्रियों के घरों पर लगाई आग, भागकर बचाई ‘जान’

एजेंसी ⏭ हैदराबाद

आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान अब हिंसक हो गया है। दो दिन में दो पूर्व मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ। कृष्णा जिले के इब्राहिमपटनम में रविवार को वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हमले के वक्त पूर्व मंत्री की पत्नी और पिता घर के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना से पूरे आंध्र प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। विवाद की मुख्य वजह आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश के खिलाफ की गई टिप्पणी है। इससे एक दिन पहले पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू के घर और दफ्तर पर भी हमला हुआ था। आरोप है कि टीडीपी कार्यकर्ताओं ने उनके घर में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस बीच अंबाती रामबाबू को सीएम नायडू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कर्नाटक में गर्मायी सियासत

बदला उर्दू स्कूलों का समय, भाजपा बोली-हिंदू त्योहरों में क्या दी थी छूट?

एजेंसी ⏭ बेंगलुरु

मदरसे में बच्चे पढ़ाई करते

रमजान में प्रदेश के उर्दू स्कूलों का टाइम टेबल बदलने और जल्दी स्कूल बंद करने को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिस पर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की तरफ से कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकार पर सवाल उठाए गए और ये पूछा गया कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों में सरकार द्वारा इस तरह की छूट क्यों नहीं दी जाती है? कर्नाटक में उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक भाषा विद्यालयों के निदेशालय के एक निर्देश के अनुसार, रमज़ान के महीने में राज्य के उर्दू माध्यम के प्राथमिक और माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का समय रमज़ान के महीने की शुरुआत से एक महीने के लिए सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक बढ़ा दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लेकिन क्या आपने किसी हिंदू त्योहार के दौरान ऐसी कोई छूट दी है?

सीएम सैनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के साथ सरकार की विकास योजनाओं और राज्य में पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

लोकसभा में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अग्रवाल ने बताया

छग के युवाओं के लिये ‘गुड न्यूज’: रायपुर में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। राजधानी रायपुर में राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी लोकसभा में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में बताया कि रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना के अंतर्गत देशभर में आईटीआई और एनएसटीआई को आधुनिक, उद्योग-अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगार से सीधे जोड़ना है।

एनएसटीआई की स्थापना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, उन्नत तकनीकी ट्रेड, प्रशिक्षकों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और उद्योग आधारित कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी। सांसद के अनुसार छत्तीसगढ़ में पहले से ही आईटीआई के आधुनिकीकरण और उद्योग सहभागिता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मॉडल आईटीआई योजना के अंतर्गत भिलाई के शासकीय आईटीआई का उन्नयन किया गया है।

राज्यसभा में भाजपा सांसद सदानंद मास्टर ने सुनाई अपनी आपबीती

कृत्रिम पैर मेज पर रख बोले- 31 साल पहले मुझ पर किया हमला

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

राज्यसभा में सोमवार को भाजपा के मनोनीत सांसद सी. सदानंदन मास्टर के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, जब भाजपा नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने कृत्रिम पैर मेज पर रख दिए और 31 साल पहले जानलेवा हमले की कहानी सुनाई।

सदानंदन मास्टर ने सीपीएम पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज संसद में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने 31 साल पहले मुझ पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है बल्कि राजनीतिक हिंसा में है। सी. सदानंदन मास्टर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। 1994 में उन्हें आरएसएस का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर लेफ्ट समर्थकों ने सबक सिखाने के लिए उनके पैर काट दिए थे।

ऐसी पार्टियों की प्रतिबद्धता राजनीतिक हिंसा में

1994 में लेफ्ट समर्थकों ने उनके पैर काटे थे

राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर

सीपीएम सांसद ने जताई आपत्ति

राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जब उन्होंने अपने कृत्रिम पैर मेज पर रखकर बोलना शुरू तो केरल के सीपीएम सांसद जॉन ब्रिट्टस ने तुरंत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए सदन में कृत्रिम अंग दिखाने पर आपत्ति जताई। तब आसन पर बैठे सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आश्वासन दिया कि वह सांसद से अपने कृत्रिम अंग नीचे रखने का निर्देश देंगे।

पैर ऐसे काटे दोबारा जोड़े नहीं जा सके

सी. सदानंदन ने 31 साल पुरानी घटना के बारे में बताया कि उनकी बहन की शादी होने वाली थी। वह अपने चाचा से मिलकर घर लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ मारपीट की गई और फिर जमीन पर गिराकर घुटनों के नीचे उनके दोनों पैर काट दिए थे। भाजपा सांसद ने कहा कि पैर काटने के बाद हमलावरों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस हमले में उनके पैर ऐसे काटे गए थे, जिसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र किए गए अमृत काल, विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 3 फरवरी, 2026

कल्पमेधा

हम सब में ऐसी ताकत है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन-सी ताकत अपनाते हैं।
- प्लेटो

संतुलन की राह

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करना एक चुनौती भरा काम है, जो संतुलित हो और जिसमें लोकलुभावन प्रस्तावों से बचने की कोशिश की जाए। सरकार का मानना है कि देश अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है और 2026-27 का आम बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। मगर किसी भी बजट की उपादेयता इससे साबित होती है कि वह देश की आर्थिक मजबूती में कितना सहायक साबित हुआ और उसका आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ा। इस लिहाज से देखें तो रविवार को पेश बजट को व्यापार और पूंजी के क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों के साथ-साथ भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ तालमेल बिठाते हुए अधिक निर्यात और स्थिर दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने वाला कहा जा सकता है।

यों इस बजट को गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के संदर्भ में उम्मीद जगाने वाले प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है, मगर कोई लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। युवा वर्ग के सशक्तीकरण के मकसद से शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पचास नए आइआइटी और मेडिकल कालेज खोले जाने की बात कही गई है। साथ ही कौशल के विकास के उद्देश्य से 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए दो लाख करोड़ रुपए और प्रशिक्षु योजना से पांच करोड़ युवाओं को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के क्षेत्र में मदद के साथ ही रोजगार केंद्रित विकास को प्रमुखता दी जाएगी। दरअसल, देश में आज भी विकास के सारे सवाल बढ़ती बेरोजगारी के सामने चुनौती की तरह लगने लगते हैं। इसके मद्देनजर बजट में बेरोजगारी दर को आठ फीसद से नीचे लाने का संकल्प जाहिर किया गया है। मगर सारे निवेश और कार्यक्रम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि शहरों-महानगरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए और उसमें हिस्सेदारी करने के लिए कौशल की कसौटी पर कितनी प्रशिक्षित युवा आबादी तैयार हुई।

इसी तरह, लक्ष्मी वंदना योजना को विस्तार दिया गया है और स्वरोजगार ऋण के नियम शिथिल किए गए, ताकि महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस नतीजे हासिल किए जा सकें। मगर यह देखने की बात होगी कि इससे जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता की स्थितियों को सशक्त बनाने में कितनी मदद मिलेगी। पांच 'विश्वविद्यालय शहर' के निर्माण, डिजिटल नालेज ग्रिड की स्थापना और देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोलना युवा सशक्तीकरण की राह को मजबूती दे सकती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से विनिर्माण, पर्यटन, दुर्लभ खनिजों के खनन और नई बुनियादी ढांचा परियोजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। बदलते दौर में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में मजबूती के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मददगार होगी, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि गरीब और अमीर आबादी के बीच डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके, क्योंकि आने वाले वर्षों में अगर देश को दुनिया में एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसमें समावेशी विकास के सिद्धांत को वास्तव में जमीन पर उतारना होगा।

सियासत का खेल

बांग्लादेश के नाहक ही अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण उसे क्रिकेट टी20 विश्व कप से बाहर कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ मुकाबला न खेलने के एलान को खेल के राजनीतिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने इस निर्णय के पीछे स्पष्ट रूप से कोई वजह भी नहीं बताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान ने सोची-समझी रणनीति के तहत यह फैसला किया है। यह एक ऐसा कदम है, जिससे न केवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख को नुकसान होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भी इसका दूरगामी असर पड़ सकता है। इससे खेल भावना की गरिमा को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि इस तरह के खेलों का आयोजन राष्ट्रों के बीच एकता, शांति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। इसलिए खेलों को भू-राजनीतिक तनाव और सियासत के दायरे से परे रखा जाना चाहिए।

दरअसल, इस गतिरोध की शुरुआत आइसीसी के उस फैसले से हुई थी, जिसमें सुरक्षा आश्वासनों को मानने से इनकार करने और अपने सभी मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की जिद के बाद बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया था। आइसीसी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलीं थी। पाकिस्तान ने भले ही भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन उसके मंसूबों को साफ समझा जा सकता है। इसमें दोराय नहीं कि भारत-पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी आइसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रोमांचकारी माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है। इसलिए आइसीसी के सामने भी वित्तीय और नियामकीय चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है। इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में आइसीसी को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में खेल भावना के साथ कोई खिलवाड़ न हो।

चुनौतियों के बीच उम्मीदों का बजट

देश की विकास दर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सात फीसद से ज्यादा माना है। मगर उसके बाद सरकार का ध्यान मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने और विदेशी पूंजी निवेश की तरफ चला गया और इस बजट पर उसकी छाया दिखती है।

पीएस वोहरा

देश का वर्ष 2026-2027 का आम बजट कुछ सुधारों की दूरगामी सोच की तस्वीर पेश करता है। हालांकि सरकार की पिछली सोच से यह बजट काफी धीमी रफ्तार में दिखा है। कारण साफ है कि अमेरिकी शुल्क का दबाव बना हुआ है। सरकार ने शुरुआती स्तर पर इस दबाव से बचने के लिए जीएसटी दरों में पहले ही कटौती कर दी थी, ताकि घरेलू बाजार में तेजी बनी रहे। इससे तीसरी तिमाही के परिणाम भी आकर्षक रहे। देश की विकास दर को खुद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने सात फीसद से ज्यादा माना है। मगर उसके बाद सरकार का सारा ध्यान मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने और विदेशी पूंजी निवेश की तरफ चला गया और यह बजट उसी की छाया में बना दिख रहा है। इसलिए पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी के संबंध में भी कोई बहुत तेजी वाली घोषणा नहीं हुई, जो बीते कई वर्षों में सरकार की एक बहुत बड़ी ताकत रही है। इसी कारण बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की गई।

बीते कुछ महीनों में विभिन्न देशों और यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सरकार ने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भरोसा जताया और वित्तीय सीमा को तीन सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके माध्यम से आने वाले समय में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं में भी सरलीकरण देखने को मिलेगा और उनकी लागत में कमी आएगी। इससे कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और तेजी से बढ़ेगी। सोलहवें वित्त आयोग की ओर से अपनी रपट 17 दिसंबर 2025 को संसद में प्रस्तुत की गई थी, मगर उसे शीत सत्र के अंतर्गत सरकार ने संसद के पटल पर नहीं रखा था। ये बड़ा अचंभित करने वाला था, क्योंकि कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसका कारण मुफ्त की योजनाएं हो सकती हैं।

इस बजट में वित्त आयोग की ओर से 41 फीसद राजस्व का बंटवारा राज्यों को करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके अंतर्गत तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक आबंटन राज्यों को किया जाएगा। एक सकारात्मक बात राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित करने की है। इस संबंध में वर्ष 2021-22 में आगामी पांच वर्षों के लिए की गई घोषणा के तहत राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसद से नीचे लाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। सरकार ने इस पक्ष पर अपनी पीठ भी थपथपाई है और आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को 4.3 फीसद पर लाने के उद्देश्य को प्रमुखता के साथ रखा है। बजट में बाहरी ऋण के संबंध में हुई कमी का आंकड़ा भी काफी सकारात्मक नजर आता है।

बजट में निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की पहल दवा क्षेत्र के लिए बहुत उत्साहजनक है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बहुत सकारात्मक है। इससे छोटे शहरों का विकास और 'मेक इन इंडिया' में प्रगति भी संभव हो पाएगी। एमएसएमई को पूंजी सहायता के लिए दस हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, इसके अतिरिक्त जोखिम से निपटने के लिए दो हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष की भी घोषणा की गई है। छोटे शहरों में एमएसएमई को विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को छोटे उद्योगों के साथ

> **बजट में निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की पहल दवा क्षेत्र के लिए बहुत उत्साहजनक है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बहुत सकारात्मक है। इससे छोटे शहरों का विकास और 'मेक इन इंडिया' में प्रगति भी संभव हो पाएगी। एमएसएमई को पूंजी सहायता के लिए दस हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, इसके अतिरिक्त जोखिम से निपटने के लिए दो हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष की भी घोषणा की गई है। छोटे शहरों में एमएसएमई को विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को छोटे उद्योगों के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई है।**

एकीकृत करने की योजना बनाई है। इसके तहत बैंकिंग क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों में और विस्तार एवं आधुनिकीकरण के वास्ते एक उच्चस्तरीय समिति बनाने की बात रखी गई है। इससे बैंकिंग क्षेत्र विकसित भारत के उद्देश्य की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ते हुए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने के उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच, आवश्यक देखभाल और मरीज की पुनर्वास योजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होने की काफी संभावना है। कैंसर की 17 दवाओं के दाम कम करने को भी एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा सकता है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बजट में सेवा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की गई है। मगर प्राथमिक स्तर पर अभी सिर्फ एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर संभावनाएं ज्यादा हैं। मगर इसके परिणाम भी अभी भविष्य की गर्त में ही है। शोध एवं अनुसंधान के मामले में भारत वैश्विक औसत से बहुत पीछे है। इस पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए पांच विश्वविद्यालय कारिडोर बनाए जाएंगे, जो निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ मिलकर इस पर कार्य करेंगे। कर से संबंधित घोषणाओं के अंतर्गत कंपनियों में अल्पसंख्यक अंशधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए 'बायबैक' योजना के अंतर्गत अब प्रवर्तकों को बाईस फीसद, जबकि अन्यों को तीस फीसद कर देना होगा।

वैश्विक स्तर पर कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत को तेजी से आगे बढ़ना होगा और इसके लिए सरकार ने सभी विदेशी कंपनियों को जो भारत में क्लाउड सेवा के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, उनके लिए वर्ष 2047 तक सौ फीसद कर छूट देने की घोषणा की है। मगर कृत्रिम मेधा से जुड़े वे भारतीय नवउद्यम, जो देश छोड़कर अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें वापस आकर्षित करने के प्रयासों पर बजट में चुप्पी अखरती है। इसी तरह किसानों की आय को दोगुना करने का दावा करने वाली सरकार इस बजट में पूर्ण रूप से शांत दिखी। मात्र कुछ घोषणाएं काजू और नारियल की खेती के संबंध में की गई है, ताकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनकर निर्यात की तरफ तेजी से आगे बढ़े। इसके अलावा किसानों के ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि पर कोई बात नहीं रखी गई है, जो बहुत निराशाजनक है। बजट में ढांचागत विकास में सात रेल गलियारों के अलावा कोई बड़ी घोषणा नहीं दिखी, जो हतप्रभ करती है।

इन सब के बीच एक निराशा यह भी है कि सोने और चांदी के मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मामले में सरकार की ओर से बजट में किसी भी प्रकार का शुल्क कम नहीं किया गया है। चांदी के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि, जिसने असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर असर डाला है, उस पर सरकार का मौन रहना समझ से परे है। हालांकि सोने के मूल्य में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से कहा जाता रहा है कि ये सब केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही खरीदारी की वजह से है। यह खरीदारी इसलिए जरूरी है, ताकि भविष्य में डालर के मूल्य में हो रही वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि यह पक्ष भी आम जनता की समझ से बाहर है। इसके अलावा, इस बात से सभी परिचित हैं कि चीन बड़ी तेजी से एआइ, हरित प्रौद्योगिकी और दुर्लभ खनिज पर अपनी बढ़त बना रहा है। इस चुनौती से पार पाने के लिए भी देश के निर्माण क्षेत्र को कोई बड़ा प्रोत्साहन बजट में नहीं दिखा।

आत्मबोध का बल

मेघा राठी

दुनिया मेरे आगे

आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना व्यस्त है, भीतर से उतना ही खाली और थका हुआ महसूस करता है। सुबह से रात तक भागदौड़ है काम की, जिम्मेदारियों की, अपेक्षाओं की। हर कोई कुछ न कुछ साबित करने में लगा है- अच्छा कर्मचारी, अच्छी पत्नी, अच्छी मां, अच्छा पति या पिता या फिर बेटा या फिर सफल व्यक्ति। इस कोशिश में आदमी धीरे-धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी कीमत उसके पद, उसकी सफलता, दूसरों की स्वीकृति से तय होती है। ऐसे समय में एक सूत्र वाक्य 'अहम् ब्रह्मास्मि' एक पुराने ग्रंथ का वाक्य नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए गहरी और जरूरी समझ बन सकता है। इसका सीधा और सरल अर्थ है, मैं केवल यह शरीर, यह नाम या यह पहचान नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं, जो इन सबको जान रही है। अक्सर लोग इस वाक्य को गलत अर्थों में लेते हैं, मानो यह अहंकार को बढ़ाने वाली बात हो। जबकि सच्चाई यह है कि यह अहंकार को गलाने वाला सूत्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि 'मैं सबसे बड़ा हूं या भगवान हूं', बल्कि यह कहता है कि 'मैं खुद को जितना छोटा समझ रहा हूं, उससे कहीं अधिक व्यापक हूं।'

आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को बहुत सीमित दायरों में बांध लेते हैं। कोई बात बिगड़ जाए, तो लगता है कि मैं ही गलत हूं। कोई असफलता मिले तो लगता है कि मैं ही नाकाम हूं। कोई रिश्ता टूटे, तो लगता है कि मेरी ही कमी है। अहम् ब्रह्मास्मि की समझ धीरे-धीरे यह सिखाती है कि जीवन में घटने वाली हर घटना 'मैं नहीं हूं'। मैं वह हूं, जो इन घटनाओं को देख रहा है, झेल रहा है, उनसे सीख रहा है। यह छोटा-सा फर्क मन को बहुत हल्का कर देता है।

जब व्यक्ति यह समझने लगता है, तो उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। आज हम छोटी-छोटी बातों पर बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। कोई ऊंची आवाज में बोल दे, कोई अनदेखा कर दे, कोई अपेक्षा पूरी न करे, तो भीतर उथल-पुथल मच जाती है। अहम् ब्रह्मास्मि का भाव यह सिखाता है कि हर बात को सीधे अपने अस्तित्व से मत जोड़ो। जो कहा गया, जो किया गया, वह सामने वाले की स्थिति और समझ का परिणाम भी हो सकता है। यह सोच व्यक्ति को हर समय लड़ने की हालत से बाहर निकालती है।

यह सूत्र असफलता और सफलता दोनों को देखने का नजरिया बदल देता है। आज सफलता को ही जीवन का मापदंड बना लिया गया है। सफल हो, तो सम्मान, असफल हो तो तिरस्कार- दूसरों की ही नहीं, अक्सर खुद की नजरों में भी। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि मैं अपनी उपलब्धियों से बड़ा हूं, तो सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है। वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन खुद को परिणाम से पूरी तरह नहीं बांधता। इससे जीवन में स्थिरता आती है। रिश्तों में यह समझ और भी जरूरी हो जाती है। बहुत से रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमें खुश रखे, समझे, पूरा करे। जब ऐसा नहीं होता, तो शिकायतें बढ़ती हैं, दूरी आती है। यह समझने की जरूरत है कि हमारी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। जब व्यक्ति भीतर से थोड़ा संतुलित होता है, तो वह रिश्तों में कम मांगता है और ज्यादा समझता है। इससे रिश्तों में सहजता आती है।

कामकाजी जीवन में भी यह दृष्टि बहुत काम आती है। कार्यालय में तुलना, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा आज आम बात है। हर कोई किसी से आगे निकलने की होड़ में है। जब व्यक्ति खुद को केवल पद या पहचान से नहीं जोड़ता, तो आलोचना उसे भीतर तक नहीं हिला पाती। वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, बिना लगातार डर में जिए। इससे न सिर्फ मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

> **हर कोई किसी से आगे निकलने की होड़ में है। जब व्यक्ति खुद को केवल पद या पहचान से नहीं जोड़ता, तो आलोचना उसे भीतर तक नहीं हिला पाती। वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, बिना लगातार डर में जिए। इससे न सिर्फ मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।**

अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या यह सोच व्यवहार में सचमुच काम करती है या सिर्फ किताबों तक सीमित है। सच यह है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि धीरे-धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है, वैसे ही मन के लिए भी अभ्यास चाहिए। दिन में कुछ पल खुद को याद दिलाना कि मैं इस भावना, इस डर, इस परिस्थिति से बड़ा हूं। यही अभ्यास है। धीरे-धीरे मन इस दिशा में ढलने लगता है। यह सोच जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती। न ही यह कहती है कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाओ। यह कहती है कि जीवन में रहा जाए, हम जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भीतर से खुद को उनसे पूरी तरह बांधें नहीं। दुख आए तो उसे महसूस करें, लेकिन उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दें। यही आंतरिक स्वतंत्रता है।

आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब केवल बाहरी समाधान पर्याप्त नहीं है। हमें भीतर की दिशा में भी देखना होगा। खुद को सही संदर्भ में समझने की सीख भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं, बल्कि वह चेतना हैं जो हर परिस्थिति को समझ सकती है। वास्तव में यह सीख जीवन को देखने का एक गहरा और मानवीय तरीका है। यह व्यक्ति को विनम्र बनाती है, क्योंकि इससे अहंकार कम होता है और यह मजबूत भी बनाता है, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार मिल जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में यदि यह भाव थोड़ा-सा भी उतर जाए, तो जीवन बोझ नहीं, बल्कि समझ के साथ जिया गया अनुभव बन सकता है।

समाज का दायित्व

'बालिका सुरक्षा के समांतर संघर्ष के मोर्चे' (आलेख, 30 जनवरी) पढ़ा। आज के दौर में जब हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का दावा करते हैं, तब भी बेटियों की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बन कर खड़ी है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि कड़े कानून बना देने से समाज सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। लड़कियों की सुरक्षा केवल पुलिस या अदालतों का विषय नहीं है। यह प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सामाजिक दायित्व का मिला-जुला परिणाम है। जब तक समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक अच्छी योजनाएं भी कागजों तक ही सीमित रहेंगी। कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब एक बेटी को बोलने की आजादी मिलती है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है। यही आत्मविश्वास उसे समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। सुरक्षा केवल बाहरी पहरे से नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती और समाज के व्यवहार से सुनिश्चित होती है।

- प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

बच्चों की खातिर

बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत पर लगाम लगाना आज एक चुनौती बन गई है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि बच्चों में डिजिटल लत छुड़ाने के लिए माता-पिता को अहम भूमिका निभानी होगी। डिजिटल कंपनियां भी ऐसी सामग्री हटाएं, जिनका बुरा प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ सकता है। आस्ट्रेलिया और फिनलैंड ने पंद्रह वर्ष तक के बच्चों के लिए इंटरनेट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। देश-विदेश में बच्चों पर मोबाइल फोन की लत से पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर जागरूकता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर मौजूद सामग्रियों का बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई, दिनचर्या और मानसिक सोच पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकार को भी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट और स्मार्ट फोन के अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीति बनानी चाहिए।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सहभागिता का सवाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों पर हालांकि रोक लग गई है, मगर इन नियमों ने सामान्य वर्ग को उपेक्षित रखा। एक ओर हम शिक्षा और नवाचार में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। समरसता और सद्भावना से लेकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बातें करते हैं, दूसरी तरफ विसंगतियों को बनाए रखते हैं। क्या यह उचित है? समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आयोग के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध हुआ। जिस तरह अन्य वर्गों की लोकतंत्र में सहभागिता होती है, उसी तरह सामान्य वर्ग की भी होती है। सवाल है कि नियमों को बनाते समय दूसरे पक्ष को भी क्यों नहीं सुना गया। किसी भी नियम को लागू करते हुए अगर सभी पक्षों की राय पर बात हो, तो एक समावेशी नीति बनाई जा सकती है। अन्यथा कई विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। वैसे बेहतर होगा कि अभी शिक्षा और शोध पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- योगेश जोशी, कंवर कालोनी, बड़वाह

जोखिम में पर्यटन

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हाल के दिनों में हुई भारी बर्फबारी ने जहां प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा दिया है, वहीं पर्यटकों के लिए गंभीर समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। सड़कें बंद हो जाने से समस्या तो बढ़ी ही है, वहीं होटलों में भीड़ बढ़ने तथा आपात सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई जैसी स्थितियां आम हो गई हैं। एक समय था जब पर्यटक मुख्य रूप से गर्मियों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए इन पहाड़ी राज्यों की ओर रुख करते थे, लेकिन अब सर्दियों में बर्फ देखने का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी के दौरान यहां पहुंचते हैं। कई बार पर्याप्त तैयारी न होने के कारण जोखिम भरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

संवाद
जनसत्ता | 3 फरवरी, 2026

बद्रीनाथ धाम

चमोली : हिमालयी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। सोमवार को बर्फ से ढका भगवान बद्रीनाथ का मंदिर।

बोल

*मैं कैसे बताऊं कि हमने मित्र देशों से कर्ज के लिए किस तरह अनुरोध किया? आपको अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। अनुचित मांगें सामने आ सकती हैं और उन्हें पूरा करना पड़ सकता है। – **शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री***

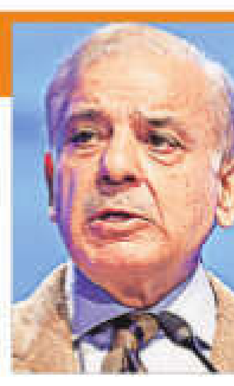

बोल

*यदि समावेशी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, तो बांग्लादेश को अस्थिरता झेलनी पड़ेगी। जब भी देश की बड़ी आबादी को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है, तो असंतोष बढ़ जाता है। – **शेख हसीना, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री***

सम-सामयिक

कूटनीति : अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला

जनसत्ता संवाद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति से जो भी हासिल करने निकले हों, नतीजा उल्टा दिख रहा है।

यूरोपीय समुदाय और भारत के बीच रक्षा और मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। हाल तक एक-दूसरे के लिए आक्रामक रहे कनाडा और चीन हाथ मिला रहे हैं और करीब आठ साल बाद ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री चीन पहुंच गया है। कभी अमेरिकी खेमे का अनिवार्य अंग रहे पश्चिमी देश अपने हितों की तलाश में एशिया का रुख कर रहे हैं। इस श्रृंखला में ताजा नाम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर। चीन के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का मकसद लिए स्टार्मर 28 जनवरी को बेजिंग पहुंचे और शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक कवायद तेज हो गई है।

ट्रंप चाहते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है। इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति का मनमाना और एकतरफा रवैया बढ़ गया है। विश्लेषकों के मुताबिक, पश्चिमी गठबंधन की हालत डांवाडोल है और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी वक्त गंवाए बिना अपने लिए विकल्प खोज रहे हैं। अब ट्रंप की नीतियों के कारण बातचीत को रफ्तार मिली और करार हो गया।

ब्रिटेन और अमेरिका करीबी दोस्त रहे हैं। ब्रिटेन अब भी अमेरिका को अपना सबसे प्राथमिक सहयोगी मानता है। पहले यह भावना साझा थी। ट्रंप के आने के बाद, खासतौर पर ट्रंप 2.0 में ब्रिटेन इस दोस्ती पर आश्वस्त रहने की हालत में नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में किअर स्टार्मर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार चीन पहुंचे हैं। आठ साल में यह पहली बार है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन गए हैं। पिछली बार मई 2018 में थेरेसा मे चीन गई थीं।

अपनी यात्रा का आशय स्पष्ट करते हुए स्टार्मर ने कहा कि चीन जिस तरह के आर्थिक मौके दे रहा है, उसकी अनदेखी कर पाना ब्रिटेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। बेजिंग जाते हुए पत्रकारों से बात करते हुए स्टार्मर ने शुतुरमुर्ग के रेत में सिर घुसाने वाली कहावत दोहराई और कहा कि चीन से बातचीत करना हमारे हित में है।

औपनिवेशिक अतीत और सम-सामयिक रिश्तों का भार चीन और ब्रिटेन के रिश्तों का स्वभाव तय करता आया है। इसमें हांगकांग भी एक कारक है, जो कभी ब्रिटेन के नियंत्रण में था। यहां राजनीतिक आजादी का दमन और मानवाधिकार-लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति, दोनों देशों के बीच रुखेपन की वजह रही। उसपर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए चीन के समर्थन ने दोनों के हितों को विरोधाभासी बनाया।

ट्रंप का रुख और यूरोपीय देशों के प्रति बहुत हद तक उनका अपमानजनक रवैया, स्टार्मर की चीन यात्रा का प्रमुख कारक माना जा रहा है। स्टार्मर की छवि ऐसे नेता की रही है, जो गहरे तनाव के बीच भी अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखते हैं। कई झटकों और सार्वजनिक फब्तियों के बावजूद वह ट्रंप पर पतौल कर बोलते आए हैं।

बदलता परिदृश्य

ब्रिटेन की सुरक्षा चिंताओं का बड़ा हिस्सा रही है 5जी नेटवर्क देने वाली चीनी कंपनियों पर गहरा अविश्वास। वह चीन को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम मानता रहा है। ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं का आरोप है कि चीन उनके अधिकारियों और नेताओं की जासूसी करवाता है, ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में दखल देने और आलोचकों-विरोधियों को डराने की कोशिश करता है। ऐसे में स्टार्मर की यात्रा चीन और ब्रिटेन के आपसी रिश्तों में गर्माहट लाने का एक अहम बिंदु बन सकती है।

शोध

डेल्टा क्षेत्र : सुंदरबन से बैंकाक तक धंस रही है धरती

जनसत्ता संवाद

गंगा के डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन के समुद्र में समा जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां समुद्र का स्तर हर साल लगभग 3.9 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। इसके मुकाबले कुछ हिस्सों में जमीन सालाना करीब तीन सेंटीमीटर नीचे जा रही है। 'नेचर जर्नल' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, हर डेल्टा का कम-से-कम एक फीसद हिस्सा ऐसा है, जहां जमीन का धंसना समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तेज है।

नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जमीन तेजी से धंस रही है। विश्व के 34 बड़े शहरों में से 10 डेल्टा क्षेत्रों में बसे हैं। हालात ये हैं कि फिजी और जकार्ता ने ऐसे इलाकों में रह रहे अपने निवासियों को कहीं और बसाने की योजना तैयार की है। भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन, गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा का हिस्सा है। यहां करीब 45 लाख लोगों की बसावट है। सुंदरबन पर भी समुद्र में समा जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां समुद्र का स्तर हर साल लगभग 3.9 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। इसके मुकाबले कुछ हिस्सों में जमीन सालाना करीब तीन सेंटीमीटर नीचे जा रही है।

डेल्टा वहां बनता है जहां नदी समुद्र, झील या महासागर में मिलती है। समुद्र के पास पहुंचकर यह धीमी होने लगती है और अपने साथ लाई मिट्टी, गाद व रेत वहीं जमा कर देती है। यही मिट्टी धीरे-धीरे नई जमीन का रूप लेने लगती है। इसे डेल्टा कहते हैं। दुनियाभर में 50 करोड़ लोग डेल्टा पर निर्भर हैं। एक अध्ययन में 40 बड़े नदी डेल्टा क्षेत्रों में जमीन की बदलती ऊंचाई को जांचा गया। यह अंतरराष्ट्रीय 'नेचर जर्नल' में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार घटते भूमिगत जल, मिट्टी की कमी और शहरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। ये इलाके भविष्य में बाढ़ और पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहद संवेदनशील हैं।

यह अध्ययन साल 2014 से 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि हर डेल्टा का कम-से-कम एक फीसद हिस्सा ऐसा है, जहां जमीन का धंसना समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तेज है। भारत के पूर्वी तट पर ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा दुनिया के सबसे तेजी से धंसने वाले डेल्टा में शामिल हैं। इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा हर साल पांच मिलीमीटर से भी अधिक नीचे जा रहा है। थाईलैंड का चाओ फ्राया, इंडोनेशिया का ब्रांतास और चीन का येलो रिवर डेल्टा भी तेजी से धंस रहे हैं।

(फाइल फोटो)

भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र, कावेरी और कृष्णा जैसे डेल्टा हैं। इन इलाकों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसे खेती और मछली पालन के लिए अच्छा माना जाता है। कई बड़े शहर व बंदरगाह भी इन इलाकों में बसे हैं। शंघाई यांग्त्से डेल्टा और बैंककाक चाओ फ्राया डेल्टा पर विकसित हुए। भारत में कोलकाता और हावड़ा गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बसे हैं।

डेल्टा क्षेत्रों की कुल मिलाकर लगभग 4,60,000 वर्ग किलोमीटर भूमि इस समय खतरे में है। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के डेल्टा सबसे अधिक प्रभावित हैं। केवल सात सबसे बड़े डेल्टा को देखें तो गंगा-ब्रह्मपुत्र, नील, मेकोंग, यांग्त्जी, अमेजान, इरवाडी और मिसिसिपी का 57 फीसद क्षेत्र धंस चुका है। इसके चलते अलेक्जेंड्रिया, बैंकाक, ढाका, कोलकाता, शंघाई, जकार्ता और सुराबाया जैसे तटीय शहर संकट में हैं।

बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंजीनियरिंग के कामकाज और भूमिगत जल व तेल का अत्यधिक दोहन इसके प्रमुख कारण हैं। अनुमान है कि साल 2050 से 2100 तक डेल्टा क्षेत्र, समुद्र का स्तर बढ़ने की दर से पहले ही धंस जाएंगे। भोपाल के 'स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' में प्रोफेसर सौरभ पोपली के मुताबिक, नदी अपने साथ मिट्टी, गाद और रेत लाती थी, लेकिन अब ये मात्रा बहुत कम हो गई है। बांधों और पनबिजली परियोजनाओं के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना नदियों के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर रहा है।

विश्व परिक्रमा

चीन : सैन्य अधिकारियों की बर्खास्तगी से खड़े हुए सवाल

जनसत्ता संवाद

चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते देश के दो सबसे वरिष्ठ जनरलों झांग योउशिया और लियू झेनली को पद से हटाने की घोषणा की थी और कहा था कि गंभीर अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। झांग अक्तूबर 2022 से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सबसे वरिष्ठ जनरल थे। वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के पोलित ब्यूरो के सर्वोच्च रैंकिंग वाले सैन्य सदस्य थे। झांग केंद्रीय सैन्य आयोग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे, जो सशस्त्र बलों को नियंत्रित करता है।

लियू पीएलए की ग्राउंड फोर्स के पूर्व कमांडर थे और हाल में केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रभारी थे।

झांग योउशिया और लियू झेनली।

20 जनवरी 2026 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की बैठक में दोनों शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल नहीं हुए। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया कि दोनों अधिकारी वास्तव में पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच के दायरे में थे। इस घटनाक्रम ने चीन में नागरिक-सैन्य संबंधों की स्थिति को लेकर अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के भीतर शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान अब सैन्य कमान संरचना के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है।

ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से, पीएलए सीसीपी का एक संगठन है। ये दोनों संगठन शी जिनपिंग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते हैं। झांग और लियू को हटाए जाने से अस्थायी रूप से सैन्य नेतृत्व केवल शी और जनरल झांग शेंगमिन के हाथों में रह गया है। केंद्रीय सैन्य आयोग के तीन अन्य सदस्य 2024 से अपने पद खो चुके हैं तथा उनकी जगह किसी और को नियुक्त नहीं किया गया है।

जानें-समझें

भारत का रक्षा खर्च

बढ़ा बजट, कितनी मजबूत होगी सेना

जनसत्ता संवाद

बजट में सभी की नजरें सैन्य बलों के लिए आबंटन की घोषणा पर टिकी थीं। आपरेशन सिंदूर के बाद नए और उन्नत आयुधों के साथ भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में रक्षा बजट को बढ़ाकर दस लाख करोड़ तक किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। वित्त मंत्रालय ने रक्षा बजट में 14.8 फीसद का इजाफा किया है। आबंटन बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचा है। दरअसल, तेजी से बदलती भू-राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सैन्य शक्ति पर विशेष ध्यान दे रहा है। सैन्य ताकत के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा महाशक्ति देश है। हालांकि सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष के तीन देशों – अमेरिका, रूस, चीन की तुलना में जमीन-आसमान का अंतर नजर आता है।

वैश्विक तनाव और तैयारियां

बजट में आधुनिकीकरण के लिए खर्च 1.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए किया गया है। यह रकम नई खरीद, हथियार, उपकरण और तकनीक पर खर्च होगी। घरेलू उत्पादन (आत्मनिर्भर भारत), स्वदेशी हथियार उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर है। रक्षा उत्पादन पहले से ही रिकार्ड स्तर पर है। यह बढ़ोतरी इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं – रूस-यूक्रेन, मध्य पूर्व, भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमा पर चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है– ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमानों के बेड़े और साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी तकनीक खरीदना जरूरी माना जा रहा है।

प्रमुख परियोजनाएं

रक्षा मंत्रालय ने कई अहम परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। नौसेना के लिए अतिरिक्त रफाल (26 या ज्यादा) खरीदे जाने हैं। वायुसेना में 36 रफाल हैं, और खरीदने की योजना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत छह नई स्टील्थ पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इनमें अत्याधुनिक तकनीक होगी। यह बड़ा सौदा है। एमक्यू-9बी जैसे ऊंचाई पर उड़ने लायक ड्रोन, स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणाली हासिल करने पर जोर है। हाल के संघर्षों में ड्रोन की अहमियत बढ़ी है। इनके अलावा हल्के लड़ाकू विमान एमके तेजस, प्रचंड हेलिकाप्टर, ब्रह्मोस, एस-400 वायु रक्षा और नई मिसाइल प्रणालियों को हासिल किया जाएगा। इन परियोजनाओं से सेना की ताकत बढ़ेगी। बजट में घरेलू कंपनियों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा।

अहम कदम

वैश्विक खतरे बढ़े हैं। ऐसे में आपरेशन सिंदूर से सबक लिया गया। रक्षा विशेषज्ञों ने 20% बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसपर नीति निर्माताओं ने काम किया। निर्यात का लक्ष्य बढ़ाया गया। वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कच्चे माल पर आयात शुल्क माफ कर दिया गया है। इससे लड़ाकू विमानों के पुर्जे देश में बनेंगे। इससे रखरखाव व मरम्मत की सुविधा बढ़ेगी। यह छूट रक्षा क्षेत्र की इकाइयों को मिलेगी, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी।

आधुनिकता पर जोर

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने बीते महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल इंटरनेट-केंद्रित से डेटा-केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा एक महत्त्वपूर्ण ढांचे के रूप में उभर रहा है। इससे युद्ध के मैदान में पारदर्शिता आ रही है और जीत के लिए तकनीकी श्रेष्ठता जरूरी हो गई है। आधुनिकीकरण के लिए क्या सिर्फ लड़ाकू विमान या पनडुब्बियों की खरीद काफी है? आज के समय में हेलिकाप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के साथ-साथ ड्रोन और साइबर युद्ध की अहमियत बढ़ गई है। इस समय पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की कमी है। भारतीय वायु सेना में 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की मंजूरी है, जबकि आज की तारीख में सिर्फ 29-30 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 20 विमान होते हैं। जाहिर है, 250-300 विमानों की जरूरत है।

(फाइल फोटो)

सिर्फ आधुनिक तकनीक का होना ही काफी नहीं है। सैन्य नेतृत्व को भी बौद्धिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जब से आपरेशन सिंदूर हुआ है तब से सेना के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि सेना को तकनीकी रूप से आधुनिक किया जाएगा। इस लिहाज से बजट में 15 फीसद की बढ़ोतरी कम लगती है। – ***एअर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) सूर्यकांत चाफेकर***

चीन का बजट हमारे मुकाबले बहुत आगे है। पाकिस्तान के बजट को कम करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के कई पड़ोसी देशों की मदद की नीति अख्तियार की है। कई कारक हैं, जिन पर सोचना होगा। आपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर जोर है।– ***लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राज शुक्ला***

शीर्ष तीन देशों का रक्षा खर्च

अमेरिका का सैन्य खर्च करीब 84.5 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा है। कुछ सालों में चीन ने सैन्य खर्च तेजी से बढ़ाया है। चीन का रक्षा बजट करीब 20.8 लाख करोड़ रुपए है। रूस का रक्षा बजट 167 बिलियन डालर है, जो करीब 14 लाख करोड़ है। चीन का रक्षा खर्च रूस से करीब दोगुना है। इसकी वजह रूस पर लगे प्रतिबंध और यूक्रेन के साथ जंग है। अगर रूस के सुरक्षा खर्चों को भी जोड़ लिया जाए तो बजट काफी बढ़ जाएगा। ब्रिटेन को दुनिया का पांचवां शक्तिशाली देश माना जाता है। हालांकि जर्मनी यूरोप का ऐसा देश है, जिसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 11 अरब डालर (भारतीय मुद्रा में करीब 72-73 हजार करोड़ रुपए) है। उसकी अर्थव्यवस्था की हालत को देखें तो यह बड़ा बोझ है। महंगाई और कर्ज संकट के बावजूद रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है।

व्यक्तित्व

प्रवीण : पैरालंपिक में कमाल किया, महज 23 की उम्र में शीर्ष सम्मान

जनसत्ता संवाद

पैरालंपिक में दो बार पदक जीतने वाले 23 वर्षीय पैरा हाई जंप खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने अपने करिअर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। जेवर के इस एथलीट को खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह नागरिक सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के पैरा एथलीट बन गए हैं। प्रवीण ने पिछले पांच वर्षों में तीन प्रमुख खेल सम्मान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 2021 के तोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुषों की टी64 ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता, और फिर 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में 2.08 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण जीतने में कामयाब रहे। तोकियो पैरालंपिक्स में सफलता के लिए उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि पेरिस पैरालंपिक्स में मिली जीत के लिए उन्हें जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मिला। पद्मश्री मिलना प्रवीण के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मैं दिल्ली में प्रशिक्षण कर रहा था, तभी मुझे खेल मंत्रालय के एक अधिकारी का फोन आया। मैंने तुरंत अपने पिता को बताया। यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सबके लिए बहुत मायने रखता है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। यह सम्मान प्रेरित करने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ाते हैं।

खेल रत्न जीतने के बाद प्रवीण ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया था, जिसका परिणाम पिछले साल सितंबर-अक्तूबर में दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में देखने को मिला। उन्होंने टी64 ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था। प्रवीण का लक्ष्य अब इस साल के अंत में जापान में होने वाले एशियाई खेलों और 2028 के लास एंजिलिस पैरालंपिक खेलों पर केंद्रित है।

दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन- क में रहने वाले प्रवीण जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में रोजाना सात से आठ घंटे तक अभ्यास करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी खेल करिअर की शुरुआत ग्रेटर नोएडा के प्रज्ञान स्कूल में हुई, जहां वे वालीबाल खेलते थे और स्वस्थ एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। बाद में, 2016 में एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान, उन्होंने ऊंची कूद में हाथ आजमाया। इसके बाद 2018 में, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कोच सत्यपाल सिंह से मिलने के बाद उन्होंने पैरा-एथलेटिक्स में कदम रखा। पद्मश्री मिलने पर सिंचाई विभाग में कार्यरत प्रवीण के पिता अमरपाल सिंह ने कहा, 'मुझे ढेरों बधाई संदेश और फोन आए। हम अपने बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं, जिसने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित किया है।'

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा

राहुल गांधी ने संसद की गरिमा कम की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

बलूनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने न केवल संसद की गरिमा को कम किया, बल्कि अपने लगातार झूठे आरोपों और गुमराह करने वाले बयानों से बहादुर भारतीय सैनिकों का मनोबल भी गिराया। भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि उस किताब में क्या लिखा है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है? इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मना किए जाने के बावजूद, सदन में बार-बार उसी निराधार दावे को दोहराना न केवल आसन का अपमान है, बल्कि देश और सशस्त्र बलों का भी अपमान है। बलूनी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद गांधी बिना किसी सबूत के सदन के पटल से देश को गुमराह कर रहे थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले की अवहेलना करते हुए सदन में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर अपने झूठे आरोपों से संसद की गरिमा को कम किया और भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के बावजूद इस मुद्दे पर बोलने पर अड़े रहने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स लिखा कि यह इन जिद्दी राहुल गांधी के वैचारिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती से देश और भारतीय सेना की छवि खराब करने के बाद, राहुल गांधी ने अब संसद के अंदर भी देश को बदनाम करना और भारत के बहादुर सैनिकों का अपमान करना शुरू कर दिया है।

बलूनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने न केवल संसद की गरिमा को कम किया, बल्कि अपने लगातार झूठे आरोपों और गुमराह करने वाले बयानों से बहादुर भारतीय सैनिकों का मनोबल भी गिराया।

भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि उस किताब में क्या लिखा है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है? इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मना किए जाने के बावजूद, सदन में बार-बार उसी निराधार दावे को दोहराना न केवल आसन का अपमान है, बल्कि देश और सशस्त्र बलों का भी अपमान है। बलूनी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद गांधी बिना किसी सबूत के सदन के पटल से देश को गुमराह कर रहे थे।

भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कई मंचों पर बताया है कि कैसे हमारे बहादुर सैनिकों ने डोकलाम में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राहुल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संसद में दुश्मनों की भाषा बोल रहे थे।

राहुल ने सदन का समय बर्बाद किया : रिजीजू

नई दिल्ली, 2 फरवरी (ब्यूरो)।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लोकसभा में अध्यक्ष के फैसले की अवहेलना करने और एक पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण के अंश उद्धृत करने की कोशिश करके लोकसभा का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। रिजीजू ने कहा कि ओम बिरला ने सदन में व्यवस्था दी थी कि केवल प्रमाणित दस्तावेजों को ही उद्धृत किया जा सकता है। सदन के नियमों का हवाला देते हुए, रिजीजू ने यह भी कहा कि चर्चा के दौरान किताबों, पत्रिकाओं और समाचार कतरनों को उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर उनका कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष के फैसले की अवहेलना करके वही गलती बार-बार दोहराई और सदन का समय बर्बाद किया।

लोकतंत्र की आत्मा को क्यों रौंद रही है सरकार : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

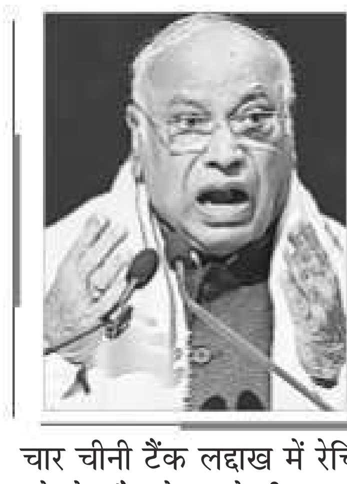

खरगे ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक आधारशिला तथ्यों को छिपाने पर टिकी है। यह आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मोदी सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों से बच रही है। खरगे ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या संसद में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर देश को विश्वास में नहीं लिया गया है और पूछा कि मदर आफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग लोकतंत्र की आत्मा को क्यों रौंद रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने से डर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे, पैदल सेना के समर्थन के साथ चार चीनी टैंक लद्दाख में रेचिन ला की ओर बढ़ रहे थे और वे पहले ही भारतीय ठिकानों से कुछ सौ मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को तत्काल फोन किए और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है? उन्हें निर्देश दिया गया कि 'ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक' गोली न चलाई जाए। खेड़ा ने लिखा कि जैसे-जैसे चीनी सेना आगे बढ़ती रही थी, रक्षा मंत्री को उनके बार-बार किए गए व्याकुल फोन काल जारी रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने

जाति जनगणना पर सुनवाई से किया इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

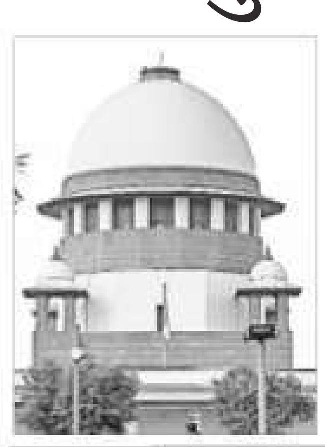

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करते हुए कहा कि सैद्धांतिक रूप से वह इन चिंताओं से सहमत है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की सामान्य जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जनहित याचिका दायर करने वाले शिक्षाविद् आकाश गोयल द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क को 'प्रासंगिक' बताया कि आगामी जनगणना 2027 में जाति गणना केवल जातिगत स्थिति की स्व-घोषणा पर आधारित नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को इस चिंता पर गौर करने के लिए कहा। गोयल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने किया। गुप्ता ने कहा कि नागरिकों के जाति संबंधी विवरण को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक पारदर्शी प्रश्नपत्र को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाति संबंधी आंकड़ों की पहचान के लिए 'पहले से तय कोई आंकड़ा' नहीं है। कहा कि जनगणना की प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए 1990 के नियमों के अनुसार संचालित होती है जो प्रतिवादी प्राधिकारियों को जनगणना करने के विवरण और तौर-तरीके तय करने का अधिकार देते हैं। पीठ ने कहा कि प्राधिकारी कानूनी नोटिस एवं याचिका में उठाए गए सुझावों पर विचार कर सकते हैं और इसी के साथ उसने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

बजट सत्र

लोकसभा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य।

धर्मांतरणरोधी कानून

केंद्र व 12 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरणरोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 'नैशनल काउंसिल आफ चर्चेज इन इंडिया' (एनसीसीआइ) की नई याचिका पर सोमवार को केंद्र के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों को नोटिस जारी किया।

एनसीसीआइ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के जरिए दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण रोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने एनसीसीआइ की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र तथा 12 राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश ने नई जनहित याचिका को इसी मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए पीठ के समक्ष उपस्थित हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा।

अरोड़ा ने दलील दी कि ओड़ीशा और राजस्थान ने भीअलग-अलग कानून बनाए हैं जिन्हें पूर्व में दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अन्य अधिनियमों में भी संशोधन किया गया है जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है। मैं सभी स्थायी अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहती हूं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नोटिस जारी करें। प्रत्येक नोटिस की एक प्रति राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए। केंद्र और 12 राज्यों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट : केंद्र एक माह में जल विवाद अधिकरण का गठन करे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच पैन्नैयार नदी के जल बंटवारे से जुड़े लंबित विवाद के समाधान का मामला।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच पैन्नैयार नदी के जल बंटवारे से जुड़े लंबित विवाद के समाधान के लिए सोमवार को जल विवाद अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के गठन का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर जल विवाद अधिकरण का गठन करे। पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय पिछले वर्ष दिसंबर में सुरक्षित रखा था।

सितंबर 2025 में न्यायालय को बताया गया था कि इस विवाद के समाधान के लिए अधिकरण का गठन आवश्यक है। यह विवाद तमिलनाडु राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कर्नाटक राज्य और भारत संघ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष लाया गया था। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि दोनों राज्यों के बीच बातचीत के माध्यम से कोई समाधान नहीं निकल पाया।

भाजपा ने विपक्षी दलों से कहा

राष्ट्रीय हितों पर समान रुख अपनाया जाए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

राजग संसदीय दल की बैठक आज

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मंगलवार को संसद भवन परिसर में राजग संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को विभिन्न विषयों पर संबोधित कर सकते हैं। संसदीय दल की इस तरह की बैठकों में आमतौर पर प्रधानमंत्री राजनीतिक और शासन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं जो उस समय संसद में सरकार के एजंडे से भी जुड़े होते हैं।

राज्यसभा में सोमवार को भाजपा सांसद सदानंदन मास्टर ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध न करें और उनसे राष्ट्रीय हितों पर एक समान रुख अपनाने का आग्रह किया। सदानंदन ने उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह बात कही।

उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। वहीं, अपने-अपने राज्यों की समस्याओं के अनसुलझे रहने का दावा करते हुए विपक्ष शासित राज्यों के नेताओं से कहा कि सरकार को सभी राज्यों का बिना किसी भेदभाव के ध्यान रखना चाहिए।भाजपा सांसद सदानंदन ने आसन की अनुमति से अपनी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपने सामने वाली मेज पर अपने कृत्रिम पैर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नारा लगाने वालों ने 31 साल पहले केरल में मुझ पर हमला किया था। मैं घर लौट रहा था जब संगठित अपराधियों ने मुझे पीछे से पकड़ा, सड़क पर गिरा दिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मेरे पैर काट दिए। भाजपा सांसद जब अपनी यह बात कह रहे थे तो माकपा के सदस्य जान ब्रिटास ने सदन में कृत्रिम अंग को प्रदर्शित किए जाने का विरोध करते हुए आसन के समक्ष व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

पेज 1 का बाकी

अमेरिका ने भारत पर शुल्क 50% से घटाकर 18% किया

करने के बारे में घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने की। यह घोषणा महीनों से चल रहे शुल्क संबंधी तनाव के बाद भारत-अमेरिका व्यापार नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। पिछले साल वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया था। इसके बाद नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त 25 फीसद शुल्क लगाया था, जिससे भारत सबसे अधिक शुल्क वाले देशों में शामिल हो गया था। रूसी तेल की खरीद पर लगाया गया अतिरिक्त 25 शुल्क खत्म कर दिया गया है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता व उनके प्रति सम्मान के मद्देनजर तथा उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका जवाबी शुल्क 25 फीसद से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।' मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मोदी ने कहा, 'मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं।' उन्होंने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप के अनुसार, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें 500 अरब अमेरिकी डालर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद शामिल है। ट्रंप ने कहा, 'भारत के साथ हमारे पहले से शानदार संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं काम करके दिखाते हैं। अधिकतर लोगों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।'

ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने (मोदी ने) रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तेल खरीदने, तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी खरीद पर सहमति जताई है।'

राहुल ने कहा, पर्दाफाश से डरे; सरकार ने कहा, गुमराह न करें

प्रमुख थे। राहुल गांधी की ओर से कई बार यह मुद्दा उठाए जाने की कोशिश करने पर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में गतिरोध बने रहने पर सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद शाम चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया, 'नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक पंक्ति से डरी हुई है। वो पंक्ति लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।'बाद में राहुल ने 'एक्स' पर लिखा, 'पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि देश के नेतृत्व ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वे मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे।' कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की पुस्तक 'फोर स्टार्स आफ डेस्टिनी' के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे, जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा, 'आप (राहुल) देश को नीचा दिखाकर क्या कहना चाहते हैं...आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई स्रोत नहीं है...आप ऐसी कोई बात मत बोलिए, जिससे सेना का मनोबल गिरे।' रिजीजू ने कहा, 'भारत विरोधी तत्वों की भाषा बोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।'राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के चरित्र के बारे में भी बताया है। इस विषय पर कार्यवाही पहली बार स्थगित होने से पहले जब लोकसभा में गतिरोध जारी था तब प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे।जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा, 'आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं...।' राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने नियमों का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना था कि राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं वो एक पुस्तक में है और उसके अंश एक पत्रिका में छपे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों डर रही है।

जेएनयू में तोड़फोड़ः छात्र संघ के चार पदाधिकारी निलंबित

पत्र की विस्तृत सामग्री पर टिप्पणी करने से इनकार किया गया। प्राक्टोरियल जांच में सामने आया कि छात्रों के समूह ने सुरक्षा कर्मियों की अपीलों की अनदेखी करते हुए लाइब्रेरी में लगे एफआरटी सिस्टम के कैमरे और स्टैंड जबरन उखाड़ दिए। जांच रपट के अनुसार, जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष गोपिका बाबू ने तोड़फोड़ का नेतृत्व किया, जबकि संयुक्त सचिव दानिश अली और नितीश कुमार ने लाइब्रेरी के पैनल्स को नुकसान पहुंचाया।

गोपिका बाबू पर आरोप है कि उन्होंने क्षतिग्रस्त पैनलों पर खड़े होकर उकसाऊ भाषण दिया और नारेबाजी की, जिससे पुस्तकालय का सामान्य कामकाज बाधित हुआ।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि घटना के दौरान दो महिला सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से घायल हो गईं थीं। निलंबन पत्र में कहा गया है कि पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त एफआरटी प्रणाली लगभग 20 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई थी। प्रशासन के अनुसार, छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान का दोषी पाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि किसी छात्र को छात्रावास में आश्रय दिया गया तो संबंधित के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि वर्ष 2026 के शीत और मानसून सेमेस्टर तक प्रभावी रहेगी। छात्रों को 10 दिनों के भीतर जुर्माना जमा कर रसीद मुख्य प्राक्टर कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

झूठे व अहंकारी हैं आयोग के अधिकारी

मांग कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, सीईसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि रहेगा और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुख्यालय से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आयोग के खिलाफ एक बार फिर तीखा हमला बोलते हुए उस पर भाजपा के दलाल के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने आरोप लगाया, इतने सारे लोग मारे गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने कहा कि हमें अफसोस है, हम न्याय के लिए यहां आए थे, हमें न्याय नहीं मिला, और आप झूठ बोल रहे हैं। वह बहुत बड़ा झूठा है...। उन्होंने आरोप लगाया, 'हमने कहा कि हम जमीनी स्तर पर इसका मुकाबला करेंगे। आपके पास भाजपा की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। हमने बैठक का बहिष्कार किया और बाहर आ गए। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें बेइज्जत किया... मैंने इस तरह का निर्वाचन आयोग पहले कभी नहीं देखा, वे बहुत अहंकारी हैं... वे ऐसे बात करते हैं जैसे वे जमींदार हों और हम नौकर हों।'

अधिकारी के अनुसार, सीईसी ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ आयोग की शक्तियों और कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि सीईसी कुमार ने तृणमूल नेताओं से कहा कि पार्टी के विधायक आयोग और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ खुले तौर पर अपमानजनक व धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'सीईसी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि एसआइआर में लगे अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उनके काम में बाधा या हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को देय मानदेय बिना किसी देरी के समय पर जारी किया जाना चाहिए।' पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित लगभग 100 लोगों को राष्ट्रीय राजधानी लाया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें वे लोग शामिल हैं, जिन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया और उन लोगों के परिजनों के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी कथित तौर पर 'एसआईआर के कारण' मृत्यु हो गई। पिछले हफ्ते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने बनर्जी को सोमवार को मुलाकात के लिए समय दिया था। टीएमसी प्रमुख और उनकी पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है और इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया है। इससे पहले नई दिल्ली में बंग भवन के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों से ममता बनर्जी की बहस हो गई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया किय बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के लोगों को धमकी दी जा रही है और उन्होंने भारी पुलिस तैनाती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल से लोग न्याय के लिए आए हैं। आए हुए पीड़ित लोगों में परिवार के 150 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जिंदा है लेकिन उन्हें मरा हुआ बताकर उनका नाम काट दिया गया है। ममता ने कहा कि दिल्ली में मैं जहां भी जहां रही हूं वहां दिल्ली पुलिस को भेजा जा रहा है।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

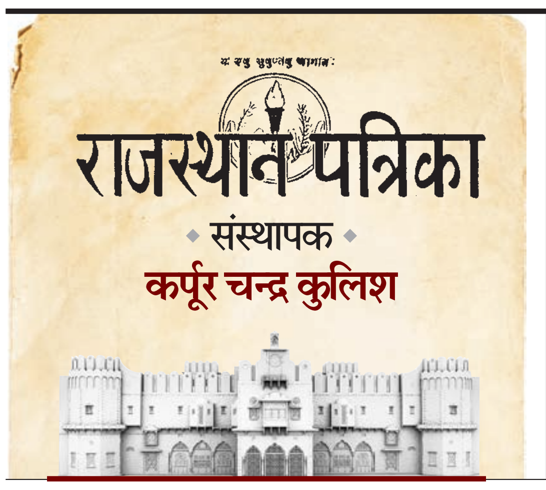

बलूचिस्तान को न संभाल पाने की पाक की खीज

बलूचिस्तान में अपने ही द्वारा ही पैदा किए गए संकट से निपटने के बजाय पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने में जुट गया है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने कुछ समय पूर्व एक रेल का ही अपहरण कर लिया था। ताजा घटना में इन विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाकर धमाके किए हैं। इनमें महिला आत्मघाती सदस्यों तक का इस्तेमाल कर विद्रोहियों ने अब मर मिटने को तैयार रहने वाले अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इन हमलों के पीछे भारत का हाथ बताकर पाकिस्तान अपने भारत-विरोधी नैरेटिव को हवा देने में जुट गया है। इस मामले में भारत की लिप्तता के आरोप पाक की खीज दर्शाते हैं जो बलूचिस्तानी विद्रोहियों से निपट पाने में अक्षमता के कारण उपजी है।

भारत के प्रति पाकिस्तान का रुख जगजाहिर है और यह भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान न सिर्फ गलत है बल्कि दोषी और षड्यंत्रकारी भी है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए वह अपनी नापाक हरकतों की तमाम सीमाएं लांघने को हर समय तत्पर रहता है। इसके बावजूद कि हर बार उसे करारा जवाब मिला है और यह अहसास भी दिलाया गया है कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के उसके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। सब जानते हैं कि चकनाचूर होती अर्थव्यवस्था के चलते पाकिस्तान ने अपने यहां आंतरिक अशांति को खुद न्यौता दिया है। वहां गरीबी सुरसा की तरह मुंह खोलती जा रही है, लोगों के खाने-पीने के लाले पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से सटे उसके सीमावर्ती इलाके लंबे समय से आतंकवाद की गिरफ्त में रहे हैं। बलूचिस्तान का मुद्दा तो उसके लिए नासूर बनता जा रहा है। हमेशा की तरह उससे इस बार भी पाकिस्तान को करारा धक्का लगा है क्योंकि विश्व मंच पर इस घटनाक्रम को लेकर भी किसी ने भी उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द नहीं कहे। भारत के खिलाफ उसने जो आरोप लगाए हैं उसकी तरफ किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। सच तो यह है कि भारत हमेशा न सिर्फ पाकिस्तान को उसके हथकंडों का करारा जवाब देता रहा है बल्कि विश्व समुदाय को भी उसकी कारगुजारियों की जानकारी देता है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी भारत ने अपना रुख कड़ाई के साथ स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को भारत पर न थोपे। साथ ही यह भी कहा है कि हर बार किसी हिंसक घटना के बाद अपने निरर्थक दावे दोहराने के बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने पर ध्यान देना चाहिए।

पाकिस्तान को भारत के इस जवाब से समझ जाना चाहिए कि भारत को किसी भी स्तर पर नुकसान पहुंचाने की उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। खुद के हालात पर ध्यान देने से ही वह अपना कुछ भला कर पाएगा। भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप से तो एक तरह से उसका ही नुकसान बढ़ता जाएगा।

डेट ट्रैप: क्या हम ऐसे चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां नया कर्ज सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जाएगा

कर्ज के चक्रव्यूह में फंसती राज्यों की अर्थव्यवस्था

विजय गर्ग
आर्थिक विशेषज्ञ, भारतीय एवं विदेशी कर प्रणाली के जानकार
@patrika.com

केंद्र सरकार को 'छिपी हुई उधारी' पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना होगा और राजकोषीय पारदर्शिता को अनिवार्य बनाना होगा। जीएसटी काउंसिल को कर संरचना को और सरल बनाकर कर आधार का वास्तविक विस्तार करना होगा।

आधुनिक भारत के आर्थिक क्षितिज पर आज दो विपरीत चित्र एक साथ उभर रहे हैं। एक ओर, भारत सरकार का यह गौरवपूर्ण दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हर महीने रिकॉर्ड तोड़ता जीएसटी कलेक्शन है। दूसरी ओर, राज्यों के बजट दस्तावेजों को पलटते ही एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। देश के अधिकांश राज्य कर्ज के गहरे दलदल में धंसते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान और केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, उधारी की सीमाएं लांघी जा रही हैं। ऐसे में यह यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि यदि देश का कर संग्रह बढ़ रहा है तो फिर राज्य वित्तीय रूप से कंगाल क्यों हो रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण यह कि इस 'कर्ज के चक्रव्यूह' में फंसी भारत की नैय्या पार कैसे होगी?

यह विरोधाभास केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति-दृष्टि का भी है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ी दिखाई देती है, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। दूसरी ओर, राज्यों की वित्तीय स्थिति धीरे-धीरे एक संरचनात्मक संकट का रूप लेती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि भारत विकास कर रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या यह विकास संतुलित है? क्या यह विकास केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए समान रूप से टिकाऊ है? विगत एक दशक के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि केंद्र और राज्यों, दोनों पर ऋण का बोझ तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार पर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है और कर्ज-जीडीपी अनुपात लगभग 56 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। लक्ष्य इसे वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 50 प्रतिशत तक लाने का है। यह दिशा सही है, पर प्रश्न यह है कि क्या केवल लक्ष्य घोषित कर देने से वास्तविकता बदल जाती है? क्या राजकोषीय अनुशासन दस्तावेजों और भाषणों तक सीमित रह गया है?

राज्यों की स्थिति और अधिक चिंताजनक है। महाराष्ट्र पर लगभग 9.3 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसका कर्ज-जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) अनुपात लगभग 18.7 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल पर लगभग 7.90 लाख करोड़ का कर्ज है और कर्ज-जीएसडीपी अनुपात लगभग 38.4 प्रतिशत के आसपास है, जो इसे उच्च जोखिम वाले राज्यों की श्रेणी में रखता है। कर्नाटक पर लगभग 7.64 लाख करोड़ का कर्ज है और कर्ज-जीएसडीपी अनुपात लगभग 24.9 प्रतिशत है। राजस्थान पर लगभग 6.30 से 6.50 लाख करोड़ का कर्ज है, जहां कर्ज-जीएसडीपी अनुपात लगभग 37.2 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यह केवल भावनात्मक विमर्श नहीं, बल्कि एक ठोस आर्थिक वास्तविकता है, जिसके सामने देश खड़ा है। यह केवल वित्तीय गणित का सवाल नहीं है, यह शासन-प्रणाली, नीति-प्राथमिकताओं और राजनीतिक संस्कृति का सवाल है। क्या राज्य अपनी वास्तविक आय क्षमता के अनुसार खर्च कर रहे हैं? क्या वे भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ डालकर आज की राजनीति चला रहे हैं? क्या विकास की परिभाषा केवल योजनाओं की संख्या और घोषणाओं की चमक तक सीमित हो गई है?

राज्यों के इस संकट के पीछे कई परतें हैं। कोविड महामारी ने राज्यों के राजस्व स्रोतों को लगभग ठप कर दिया था, जबकि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च कई गुना बढ़ गया। बिजली वितरण कंपनियों के घाटे, सब्सिडी आधारित राजनीति, सामाजिक कल्याण योजनाओं का अनियंत्रित विस्तार और प्रशासनिक अक्षमताएं, इन सबने मिलकर राज्यों की वित्तीय रीढ़ को कमजोर कर दिया। जून 2022 में जीएसटी मुआवजा समाप्त होना इस संकट का निर्णायक मोड़ बना। कई राज्य इस व्यवस्था पर इतने निर्भर हो चुके थे कि इसके समाप्त होते ही उनका राजकोषीय संतुलन चरमरा गया। आरबीआइ बार-बार चेतावनी दे चुका है कि राज्य यदि अपने अनुत्पादक व्ययों को नियंत्रित नहीं करते तो वे 'डेट ट्रैप' में फंस सकते हैं, जहां नया कर्ज केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जाएगा। क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या भारत धीरे-धीरे एक ऐसे आर्थिक चक्र में प्रवेश कर रहा है, जहां विकास का अधिकांश लाभ केवल ब्याज भुगतान में चला जाएगा?

इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि सोच के परिवर्तन से निकलेगा। 'सहयोगी वित्तीय अनुशासन' केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक संस्कृति होना चाहिए। केंद्र और राज्यों को यह समझना होगा कि कर्ज केवल तभी लिया जाए, जब उससे प्रोडक्टिव एसेट्स का निर्माण हो, जैसे सड़कें, बंदरगाह, उद्योग, ऊर्जा संरचना, शिक्षा संस्थान, जो भविष्य में राजस्व पैदा करें।

राज्यों को अपनी बिजली कंपनियों, परिवहन संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर व्यावसायिक दक्षता की ओर ले जाना होगा। केंद्र सरकार को 'छिपी हुई उधारी' पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना होगा और राजकोषीय पारदर्शिता को अनिवार्य बनाना होगा। जीएसटी काउंसिल को कर संरचना को और सरल बनाकर, कर आधार का वास्तविक विस्तार करना होगा। डिजिटल शासन को केवल सुविधा नहीं, राजस्व सुधार का माध्यम बनाना होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। कर्ज में डूबता भारत, अभी एक चेतावनी है, वास्तविकता नहीं, लेकिन चेतावनियां तभी उपयोगी होती हैं, जब उनसे सीख ली जाए। देश की नैय्या तभी पार होगी, जब केंद्र और राज्य प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि 'टीम इंडिया' बनकर कार्य करेंगे, जब राजकोषीय ईमानदारी राजनीति का मूल मूल्य बनेगी।

प्रसंगवश

न सड़कें दुरुस्त और न ही सुविधाएं पर्याप्त फिर भी मनमानी टोल वसूली

महज 60-70 किलोमीटर के सफर में तीन बार टोल न्यायसंगत कतई नहीं

राजमार्गों के जाल से आवागमन सुगम और समय बचाने वाला हुआ है इसमें दो राय नहीं है। सड़कों के निर्माण व इसके बाद रखरखाव में आने वाली लागत को देखते हुए ही राष्ट्रीय व राज्य स्तर के राजमार्गों पर टोल वसूलने की व्यवस्था की गई थी, पर सड़क की लागत वसूलने के बावजूद लंबे समय से टोल वसूली जारी है जो मनमानी ही कही जाएगी। चिंता की बात यह भी है कि भारी-भरकम टोल वसूली के बावजूद कई मार्गों की हालत बद से बदतर है। राजस्थान में महुआ-हिंडौन मार्ग हो या अन्य कई स्टेट हाईवे, यहां डामर से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। राज्य मार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा तय मानकों पर खरे नहीं उतरते। एक तरह से वसूली में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती लेकिन सुविधाओं के मामले में छलावा ही मिलता है। सवाल यह है कि आखिर टोल के रूप में वाहनों से वसूली क्यों की जाती है।

संसद में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होगी और इससे कम दूरी होने पर एक टोल हटाया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। राजस्थान में 30 से 50 किलोमीटर के भीतर ही दो-दो टोल प्लाजा खड़े हैं और जनता से जमकर वसूली हो रही है। महज 60-70 किलोमीटर के सफर में तीन बार टोल देना न्यायसंगत कतई नहीं कहा जा सकता। टोल वसूली होती है तो फिर नागरिकों का यह अधिकार भी बनता है कि उन्हें सड़कें आरामदायक सफर वाली और सुरक्षित मिलें। मार्ग में बेहतर सुविधाएं हों। लेकिन सड़कों पर न तो पर्याप्त संकेतक ही होते हैं और न ही जरूरी सुविधाएं नजर आती। केंद्र सरकार ने टोल वसूली के जो नियम-कायदे तय कर रखे हैं उसकी भी पूरी तरह पालना नहीं होती। सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जानी चाहिए। अवैध तौर पर संचालित टोल प्लाजा को तत्काल हटाया जाए और जहां भी नियमों का उल्लंघन कर कम दूरी पर टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाने का काम होना चाहिए। जो मामले अदालतों में लंबित हैं, उन्हें भी शीघ्र निस्तारित करने के प्रयास होने चाहिए।

- **अभिषेक श्रीवास्तव**
abhishek.srivastava@in.patrika.com

बुक इनसाइट

ब्लैक डहलिया : शोधपरक कृति

विलियम जे. मैन की पुस्तक 'ब्लैक डहलिया' अपराध की एक गंभीर और शोधपरक कृति है। यह एक गंभीर, संतुलित और जिम्मेदार पुस्तक है, जो बताती है कि किसी हत्या की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं होती, बल्कि उस समाज की भी होती है जो उसे देखता और गढ़ता है।

यह किताब 1947 में लॉस एंजेलिस में हुई एलिजाबेथ बेट्टी शॉर्ट की जघन्य हत्या पर आधारित है। किताब में पीड़िता को केवल अपराध कथा की पात्र के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक युवा महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसकी अपनी इच्छाएं, कमजोरियां और सीमाएं थीं। किताब उस दौर के समाज, मीडिया और पुलिस व्यवस्था की भूमिका को भी परखती है। यह किताब इस हत्या से जुड़े वर्षों पुराने प्रचार, अफवाहों व कल्पनाओं की परतें हटाने का प्रयास करती है। विलियम जे. मैन की लेखन-शैली इस किताब की ताकत है। वे तथ्यात्मक विवरण से पीछे नहीं हटते, पर अनावश्यक हिंसा-वर्णन से बचते हैं। उनकी भाषा संतुलित, संवेदनशील और पाठक-केन्द्रित है। यह मीडिया, इतिहास और समाज में रुचि रखने वालों के लिए अहम है।

फैक्ट फ्रंट

गुआनाको : सतर्क और फुर्तीला जीव

गुआनाको दक्षिण अमरीका में पाया जाने वाला एक जंगली स्तनधारी है, जो ऊंट के ही परिवार कैमेलिडे से संबंधित है। ऊंट जहां अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, वहीं गुआनाको पूरी तरह दक्षिण अमरीका तक सीमित है। गुआनाको का शरीर पतला और मजबूत होता है। इसकी पीठ हल्के भूरे रंग की और पेट का भाग सफेद होता है। इसके कान बड़े और नुकीले, गर्दन लंबी तथा पूंछ छोटी होती है। यह बनावट इसे पहाड़ी और खुले क्षेत्रों में

तेजी से चलने और खतरे से बचने में मदद करती है। यह जीव अत्यंत सतर्क और फुर्तीला माना जाता है। खतरा महसूस होने पर, गुआनाको एक तीखी आवाज में मिमियाकर झुंड के बाकी सदस्यों को सचेत करता है, जो एक छोटी, तीखी हंसी जैसी लगती है। गुआनाको सामान्यत: छोटे समूहों में रहता है। एक समूह में एक प्रमुख वयस्क नर, कई मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। मादा गुआनाको के बच्चे को चुलेंगो कहा जाता है, जो जन्म के कुछ ही समय बाद चलने लगता है और तुरंत झुंड के साथ चलने में सक्षम होता है।

करेंसी संकट राजकोषीय स्थिति चिंताजनक

डॉलर की गिरावट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

हर्ष काबरा
स्वतंत्र पत्रकार एवं विश्लेषक
@patrika.com

अमरीकी डॉलर की बादशाहत ढलान पर है। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की घटती कीमत और निवेशकों का इससे मोहभंग न केवल अमरीका, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। यह संकट राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के विवादास्पद बयानों तक सीमित नहीं है। इसके तार गहरे संरचनात्मक आर्थिक दोषों से भी जुड़े हैं। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े गर्व से कहा कि वह डॉलर को एक 'यो-यो' की तरह ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। उन्होंने हाल के महीनों में डॉलर के कमजोर होने को 'बेहतरीन' करार दिया। उनके इस बयान का असर तुरंत बाजार पर दिखा और यूरो के मुकाबले डॉलर पिछले पांच वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

जानकारों का मानना है कि यह एक खतरनाक गिरावट चक्र की शुरुआत है। डॉलर की इस दुर्दशा के पीछे सिर्फ ट्रंप का अड़ियल और गैरजिम्मेदाराना रवैया ही नहीं, बल्कि कई अन्य तनावपूर्ण कारक भी काम कर रहे हैं। खतरा इस बात का है कि यह गिरावट एक ऐसे बिंदु की ओर बढ़ रही है, जहां से डॉलर की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना और भी प्रबल हो सकती है। इसके परिणाम अल्पकाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी और दीर्घकाल में अप्रत्याशित होंगे। ट्रंप अक्सर डॉलर के प्रति भरोसे को कमजोर करने वाले बयान देते ही रहते हैं। केवल ट्रंप के शब्द ही निवेशकों को नहीं डरा रहे हैं। व्यापारिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, अमरीका की अविश्वसनीय छवि और जेरोम पॉवेल के जाने के बाद अमरीकी फेडरल रिजर्व की साख पर उठते सवालों ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने अपने वफादार केविन वार्श को पॉवेल का उत्तराधिकारी घोषित किया है, जो उनकी इच्छा के अनुसार ब्याज दरों में भारी कटौती करेंगे।

अमरीका की राजकोषीय स्थिति भी चिंताजनक है। देश का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद के 120 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है और बजट घाटा लगभग 6 प्रतिशत है। यदि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित करता है, तो अमरीका से राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी छिन जाएगा। इन सब परिस्थितियों का नतीजा यह है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक अब अमरीकी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने से कतरा रहे हैं। यदि डॉलर का इसी तरह अवमूल्यन होता रहा, तो विदेशी निवेशकों की डॉलर-संपत्तियों की कीमत मिट्टी में मिल जाएगी। अन्य देशों से अमरीका को होने वाला निर्यात इतना महंगा हो जाएगा कि अमरीकी ग्राहकों के लिए उसे खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। डॉलर का यह पतन वित्तीय बाजारों को तो धराशायी करेगा ही, एक ऐसी वैश्विक मंदी को भी जन्म दे सकता है जिससे उबरने में एक लंबा समय लग जाएगा।

सदियों से अगरबत्ती बनाने की कला संजोए हनोई का क्वांग फू काउ

***वियतनाम** की राजधानी हनोई के सांस्कृतिक परिदृश्य में बसे क्वांग फू काउ इंसेंस विलेज की पहचान केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि जीवित परंपरा के रूप में है। सभ्यता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हनोई, बाट ट्रांग पोट्री विलेज और हा डोंग सिल्क विलेज जैसी सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं का गवाह रहा है और उन्हीं परंपराओं को क्वांग फू काउ आज भी संजोए हुए है। अगरबत्ती बनाने की कला यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।*

दृष्टिकोण सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए

हेल्थ सेक्टर में निजी इक्विटी पर पुनर्विचार का समय

जगदीश रत्तनानी
वरिष्ठ पत्रकार (द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र दोहरी मार झेलता रहा है। एक ओर सार्वजनिक निवेश की कमी रही है और दूसरी ओर निजी क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य-सेवा के मूल उद्देश्यों से समुचित रूप से नहीं जुड़ पाया। इस स्थिति से निपटने के लिए देश ने एक रास्ता यह चुना कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी इक्विटी के निवेश को अनुमति दी जाए, ताकि पूंजी आए और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो। निजी इक्विटी सेक्टर की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में इन निवेशों में तेज उछाल आया है।

यह नीति बीते लगभग दो दशकों से लागू है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 से नया बल मिला- जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए निजी क्षेत्र को रणनीतिक साझेदार कहा गया। नीति आयोग ने भी निवेश अवसर रेखांकित कर इसे और मजबूत किया। लेकिन नागरिकों की जरूरतों के प्रति स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक संवेदनशील बनाने के बजाय, निजी इक्विटी के लिए प्रशस्त किए मार्ग ने पुराने ढांचागत बोझों में नई जटिलताएं जोड़ दी हैं।

वैश्विक परामर्श फर्म बेन एंड कंपनी के अनुसार, 2023 में स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल्स में कुल निजी इक्विटी निवेश 5.5 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। बेन की ही रिपोर्ट बताती है कि 2024 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की कुल हेल्थकेयर निजी इक्विटी डील्स में भारत की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही, जिससे वह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार बन गया।

बड़ी चिंता यह है कि निजी इक्विटी की सोच अब पूरे स्वास्थ्य तंत्र को प्रभावित करने लगी है, यहां तक कि उन अस्पतालों को भी, जो सीधे इसके नियंत्रण में नहीं हैं। कारण साफ है- मुनाफा कमाने और समय पर बाहर निकलने की होड़ में इलाज का रुख महंगे पैकेजों, मेडिकल टूरिज्म और जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रहा है, जहां कमाई ज्यादा है। नतीजतन, साधारण और कम लागत वाले उपचार पीछे छूटते जा रहे हैं। यह अक्सर सुना जाता है कि स्वास्थ्य सेवा में कारोबारी नजरिया इतना हावी हो गया है कि पहले जिन तरीकों को गलत माना जाता था, वे अब सामान्य हो रहे हैं।

सरकार की ओर से सुधारों को लेकर दिखाई देने वाली चुप्पी संकेत देती है कि नीति आज ऐसे संरचनात्मक जाल में फंस चुकी है, जहां दिशा बदलना सहज नहीं रहा। मौजूदा हालात से निकलने का साफ रास्ता यही है कि स्वास्थ्य को फिर से प्राथमिकता बनाया जाए, सार्वजनिक निवेश तेजी से बढ़ाया जाए और मजबूत नियामक ढांचा और कड़ी नियमावली हो। साथ ही, डॉक्टरों के साथ भरोसा बहाल करना, उन्हें सशक्त करना और सेवा-संस्कृति को सम्मान देना भी जरूरी है।

आपकी बात

चाइल्ड केयर लीव बेहद जरूरी

चाइल्ड केयर लीव निजी क्षेत्र में भी महिलाकर्मियों के लिए जरूरी है। मातृत्व के बाद कई बार उन्हें नौकरी छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। शिशु की भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में भी यह दिया जाना चाहिए। - **मनवीर चन्द कटोच**, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'सरकारी की तरह निजी क्षेत्र में भी चाइल्ड केयर लीव को लेकर आपके क्या विचार हैं?' ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/WVVGi

आज का सवाल

आम बजट आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

आधी आबादी 'शी मार्ट' होगा आत्मनिर्भरता की नई राह, उत्पादों की बिक्री के लिए मिलेगा संगठित व स्थायी मंच

महिलाओं की आर्थिक भूमिका को केंद्र में रखता हुआ बजट

ऋतु सारस्वत
समाजशास्त्री
@patrika.com

केंद्रीय बजट 2026 के बजटीय भाषण में वित्त मंत्री ने उस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है कि महिलाएं अब केवल योजनाओं की प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि देश की आर्थिक संरचना की सक्रिय सहभागी हैं। अब तक जिस बजट को करों और अनुदानों तक सीमित माना जाता रहा है, वह दस्तावेज इस बार महिलाओं की आर्थिक भूमिका को केंद्र में रखता हुआ दिखाई देता है।

इस वर्ष के प्रस्तुत बजट को महिलाओं के संदर्भ में केवल एक ऐतिहासिक पहल कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह सरकार की नीति-दृष्टि में आए एक बड़े परिवर्तन को भी दर्शाता है। देश की आधी आबादी की आर्थिक सुदृढ़ता केंद्र सरकार की विचारधारा की आधार भूमि है, जिसे विगत वर्षों के बजटीय घोषणाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह प्रवाह बजट में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था- इन चार आधारों पर खड़ा यह बजट आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में बदलने की क्षमता रखता है।

इसका प्रभाव न सिर्फ महिला सशक्तीकरण तक सीमित रहेगा, बल्कि यह देश की समग्र आर्थिक मजबूती को भी नई दिशा देने वाला सिद्ध हो सकता है। बजट में सरकार द्वारा 'शी-मार्ट' की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। शी-मार्ट योजना के माध्यम से सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक संगठित और स्थायी मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सशक्त और संगठित व्यापारिक व्यवस्था विकसित करना है। इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विशेष खुदरा केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

शी-मार्ट योजना महिलाओं के छोटे व्यवसायों को टिकाऊ बनाने और उनकी नियमित आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डिजिटल शी-मार्ट को राष्ट्रीय डिजिटल व्यापार मंच और ऑनलाइन विपणन प्रणालियों से जोड़ने की तैयारी के माध्यम से महिलाओं के लिए केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव परिवार, समाज और देश की समग्र आर्थिक स्थिति पर दिखाई देगा।

केंद्रीय बजट में 'लखपति दीदी' पहल का उल्लेख ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में किया गया है। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका से आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की व्यवधानों को दूर करने के लिए उन व्यावहारिक चुनौतियों को समग्र रूप से संबोधित करने का प्रयास किया है जिनका सामना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को करना पड़ता है। कार्यस्थल की सुरक्षा, रात्रिकालीन परिवहन सुविधा और शिशु देखभाल केंद्रों की व्यवस्था को एक साथ जोड़कर देखा जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि केंद्रीय बजट में व्यावहार्यता (वायबिलिटी) अंतर वित्तपोषण और पूंजी सहायता के माध्यम से देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य छात्राओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा छोड़ने की दर को कम करना है।

निश्चित रूप से देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणाएं स्वागत योग्य है परंतु यक्ष प्रश्न यह है कि यह वास्तविकता के धरातल पर कितनी चरितार्थ होती है क्योंकि घोषणाओं और उनके पालन के बीच एक लंबा रास्ता तय करना होता है।

अगर लोग आपको 'ना' कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका आइडिया गलत है, बस अभी वे उसे नहीं समझ पाए हैं। हर 'रिजेक्शन' आपको लक्ष्य के और करीब ले जाता है।

मेलानी पर्किन्स, को-फाउंडर, कैनवा

पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

इन्वेस्टमेंट मीटर...

इन स्मॉलकैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स की बड़ी हिस्सेदारी

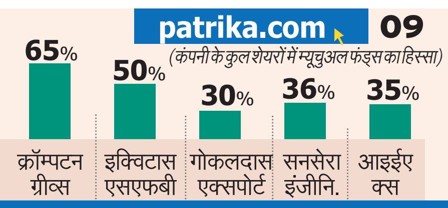

पीएमआइ बढ़ा

नए ऑर्डर में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी

नई दिल्ली@ पत्रिका. जनवरी में देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में हल्का सुधार देखा गया। यह सुधार नए ऑर्डर्स में तेजी के चलते हुआ। हालांकि, बिजनेस कॉन्फिडेंस पिछले साढ़े तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआइ दिसंबर के दो साल के निचले स्तर 55 से बढ़ जनवरी में 55.4 पर रहा। एचएसबीसी के मुताबिक, नए ऑर्डर्स, उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी हुई। इनपुट लागत में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि फैक्ट्री-गेट कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ा। बिक्री को सबसे ज्यादा सहारा घरेलू बाजार से मिला। निर्यात ऑर्डर्स भी बढ़े।

विनिवेश

एलआइसी में हिस्सा एफपीओ के जरिए बेचने की तैयारी

नई दिल्ली@ पत्रिका. केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में एफपीओ के माध्यम से बीमा कंपनी एलआइसी में अपनी हिस्सेदारी और घटाने पर विचार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को कहा, यदि सभी मंजूरियां मिल जाती हैं और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है, तो अगले वित्त वर्ष में एलआइसी का एफपीओ आ सकता है। अभी एलआइसी में सरकार की 96.5% हिस्सेदारी है। सरकार ने मई, 2022 में आइपीओ के माध्यम से 902-949 रुपए प्रति शेयर मूल्य दायरे में कंपनी में 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। सरकार को मई 2027 तक कंपनी में 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5% हिस्सेदारी और बेचनी होगी।

ओरेकल

30,000 कमियों की होगी छंटनी

नई दिल्ली@ पत्रिका. एआइ डेटा सेंटर्स के विस्तार के लिए भारी-भरकम पैसों के दबाव के बीच टेक दिग्गज ओरेकल 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका के बड़े बैंक ओरेकल के एआइ डेटा सेंटर विस्तार योजनाओं को लोन देने से धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं। इस वजह से ओरेकल अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने पर विचार कर रही है। साथ ही कंपनी अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी कर सकती है। छंटनी के जरिए ओरेकल का लक्ष्य 8 से 10 अरब डॉलर का कैश फ्लो फ्री करना है।

भारत-अमरीका ट्रेड डील से शेयर बाजार में जोश हाई टैरिफ घटने की घोषणा के बाद सोमवार की रात गिफ्ट निफ्टी करीब 700 अंक चढ़ा

टैरिफ घटकर 18% होने से आज 3% तक चढ़ सकता है भारतीय बाजार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर प्रभावी टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा से सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसका सीधा असर गिफ्ट निफ्टी पर दिखा जो 680 अंक यानी 2.7% चढ़ गया। इससे संकेत मिलता है कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी में 3% तक की तेजी आ सकती है। शेयर बाजार सोमवार के भी बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी में आई इस तेजी का मतलब है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी मजबूत गैप-अप ओपनिंग हो सकती है।

इन सेक्टरों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी (एडीआर उछला)

सेक्टर	तेजी
आइटी	04%
फार्मा	03%
मेटल	3.5%
ऑटो	03%
बैंकिंग	02%
कैपिटल गुड्स	03%

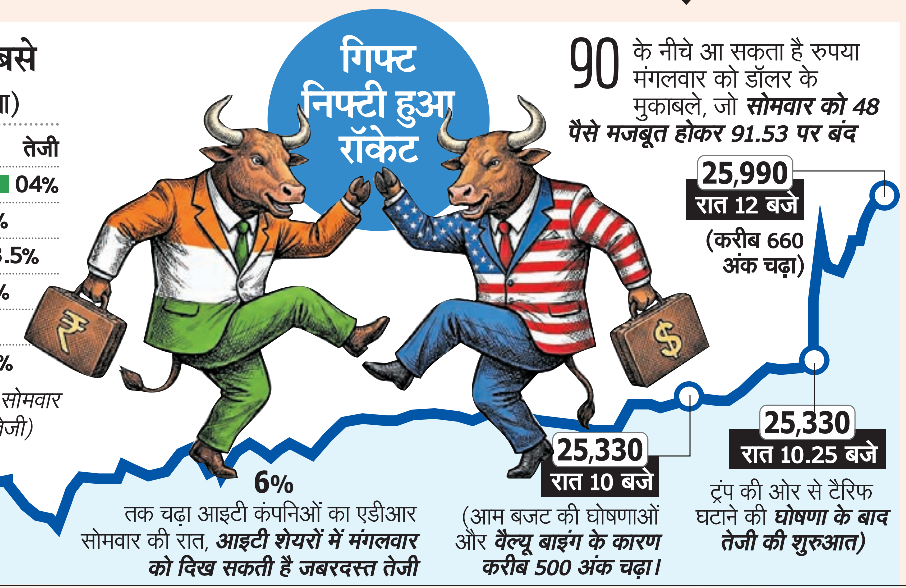

विदेशी निवेशकों के लौटने की उम्मीद बढ़ी

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत-अमरीका ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई थी। विदेशी निवेशक सतर्क थे और बाजार पर दबाव बना हुआ था। जैसे ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की खबर आई, निवेशकों का भरोसा लौटा और जोखिम लेने की धारणा मजबूत हुई। इस समझौते के तहत टैरिफ (आयात शुल्क) में कटौती और व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने की बात सामने आई है। इससे आइटी, फार्मा, ऑटो और मेटल जैसे निर्यात-आधारित सेक्टरों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बाजार जानकारों का मानना है कि यह डील भारतीय कंपनियों के लिए अमरीकी बाजार में पहुंच को आसान बना सकती है।

करेंसी-शेयर बाजारों को मिलेगी बड़ी राहत

इस समझौते के कुछ बारीक पहलू अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन इसने वित्तीय बाजारों को बड़ी राहत दी है। असली बात विवरण में छिपी होती है, पर यह समझौता रुपए, शेयर बाजार व ब्याज दर पर लटकी अनिश्चितता की तलवार को हटा देगा। इसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से लागू किया गया, तो यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'विन-विन' डील होगी। **- निलेश शाह,** एमडी, कोटक महिंद्रा एएमसी

टैक्सपेयर्स के लिए बजट में क्या बदला? छोटी गलती पड़ेगी भारी, ऑडिट न कराने पर ₹1.5 लाख जुर्माना

अधूरे मकान के होम लोन पर भी टैक्स छूट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव खासतौर पर शेयर बाजार की ट्रेडिंग, विदेशी संपत्ति, रेमिटेंस और टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़े हैं। बजट में कोई नई छूट या इनसेंटिव नहीं दिए गए, बल्कि पुराने कानूनों को फिर से लिखा गया है। ये नियम 1 अप्रेल 2026 से लागू हो जाएंगे, जो अगले साल के असेसमेंट और मौजूदा फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे। निर्माणाधीन (अंडर-कंस्ट्रक्शन) घर खरीदने वालों को बजट 2026 ने बड़ी राहत दी है। बजट में साफ कर दिया गया है कि 2 लाख तक का होम लोन ब्याज पर टैक्स डिडक्शन पहले की तरह मिलता रहेगा, भले ही घर अभी पूरा न हुआ हो। नए इनकम टैक्स कानून में पहले यह आशंका थी कि घर बनने से पहले चुकाए गए ब्याज (प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट) पर टैक्स छूट का फायदा खत्म हो सकता है। इससे उन लोगों की चिंता बढ़ गई थी जिन्होंने अभी फ्लैट का पजेशन नहीं लिया है, लेकिन ईएमआइ या ब्याज चुका रहे हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टैक्स को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी करना महंगा साबित हो सकता है। नए नियमों के तहत छोटी सी चूक पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये बदलाव कारोबारियों, पेशेवरों और आम टैक्सपेयर्स सभी के लिए अहम हैं। यदि किसी व्यक्ति को टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है और वह समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो अब उस पर सीधा जुर्माना लगेगा। एक महीने तक की देरी पर 75000 रुपए की फीस देनी होगी। अगर देरी एक महीने से अधिक होती है तो जुर्माना बढ़कर 1.50 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा।

एक लॉट निफ्टी पर टैक्स

चार्ज	मौजूदा फीस	नई फीस
ब्रोकरेज	20.00	20.00
एक्सचेंज ट्रांजैक्शन	27.88	27.88
जीएसटी	7.11	7.11
एसटीटी	322.29	805.73
सेबी टर्नओवर चार्ज	1.61	1.61
कुल चार्ज	380.50	863.94

(यानी एक लॉट पर 127% बढ़ गया शुल्क)

एसटीटी बढ़ने का क्या है मतलब

01 फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़ा

पहले	0.02%
अब	0.05%

असर: अगर आपने ₹10 लाख का सौदा किया

पहले टैक्स	₹200
अब टैक्स	500

02 ऑप्शंस पर बढ़ा एसटीटी

पहले	0.10%
अब	0.15%

ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर

पहले टैक्स	0.125%
अब टैक्स	0.15%

असर: यानी ऑप्शन खरीदने, बेचने और एक्सरसाइज करने तीनों हालात में ज्यादा टैक्स देना होगा।

निवेशकों को लगा इन फैसलों से झटका

1 अब डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड इनकम के खिलाफ ब्याज खर्च पर टैक्स कटौती नहीं मिलेगी। इसका असर उन निवेशकों पर पड़ेगा, ***जो उधार लेकर या मार्जिन फाइनेंसिंग के जरिए निवेश करते हैं। इससे टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी।***

2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने बॉन्ड ओरिजिनल इश्यू में खरीदे हों और उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो। ***इससे 10 लाख के मुनाफे पर कम से कम 1.25 लाख रुपए टैक्स देना होगा।***

3 डेरिवेटिव्स (फ्यूचर एंड ऑप्शंस) पर सिक्योरिटी ***ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ने से एफएंडओ ट्रेडिंग की लागत करीब 3 गुना तक बढ़ेगी। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी गिरावट की आशंका है।***

■ ***गलती और जानबूझकर टैक्स चोरी में फर्क:*** अंडर-रिपोर्टिंग और मिस-रिपोर्टिंग के बीच साफ अंतर किया गया है। अगर इनकम कम दिखाना गलती, चूक या अनजाने में हुआ है, तो पेनल्टी टैक्स की रकम का 50% होगी। लेकिन अगर गलत जानकारी जानबूझकर दी गई है या इनकम छुपाई गई है, तो पेनल्टी बढ़कर टैक्स की रकम का 200% तक हो सकती है।

■ ***रिवाइज्ड आइटीआर:*** अब तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर होती थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च किया जाएगा, वह भी नाममात्र फीस के साथ।

■ ***लेट आइटीआर पर टीडीएस रिफंड:*** अब टैक्सपेयर्स देर से आइटीआर फाइल करने पर भी टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे। सिर्फ रिफंड लेने के लिए लेट फाइलिंग पर पेनल्टी नहीं लगेगी।

■ ***अपील के दौरान ब्याज नहीं:*** अगर किसी टैक्स मामले में पेनल्टी लगी है और मामला पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास लंबित है, तो उस अवधि में पेनल्टी की रकम पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।

■ ***छोटा, पर असरदार बदलाव:*** बजट में कई छोटे लेकिन अहम टैक्स राहत कदम भी शामिल हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड्स को टैक्स फ्री किया गया है। एलआरएस के तहत एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया है। इसके अलावा, विदेश टूर पैकेज पर भी घटाकर 2% कर दिया गया है।

■ ***मैट में राहत:*** मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (मैट) को लेकर भी राहत दी है। प्रेजम्पटिव टैक्स देने वाले नॉन-रेजिडेंट्स को मैट से छूट दी जाएगी। मैट को फाइनल टैक्स माना जाएगा और इसकी दर 15% से घटाकर 14% होगी। इससे बिजनेस और विदेशी टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

■ ***टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट:*** अब असेसमेंट ईयर- फाइनेंशियल ईयर जैसे जटिल शब्द नहीं होंगे। इनकी जगह सिर्फ एक शब्द होगा टैक्स ईयर। इसका मतलब होगा 1 अप्रेल से शुरू होने वाला 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ईयर का मतलब होगा 1 अप्रेल से शुरू होने वाला फाइनेंशियल ईयर। अगर नया बिजनेस शुरू होता है, इनकम का नया सोर्स बनता है, तो उसी तारीख से टैक्स ईयर माना जाएगा।

कितना लगेगा जुर्माना

तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। कुल आय 5 लाख तक है तो 1000 रुपए और इनकम 5,00,000 से अधिक है तो 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। जरूरी टैक्स स्टेटमेंट तय समय पर जमा नहीं करने पर हर दिन 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना तब तक जोड़ा जाएगा जब तक स्टेटमेंट जमा नहीं हो जाती। यदि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या रिपोर्टेबल अकाउंट की जानकारी समय पर नहीं दी जाती है तो भी प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना अधिकतम 1,00,000 रुपए तक सीमित रहेगा।

भारत-अमरीका व्यापार समझौता...

ट्रेड डील के बावजूद 8.3 अरब डॉलर के निर्यात पर रहेगा 25% से ज्यादा टैरिफ!

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत-अमरीका व्यापार समझौता लागू होने के बावजूद भारत के अमरीका को होने वाले करीब 10.4% निर्यात पर अब भी 25% या इससे अधिक का ऊंचा टैरिफ लगेगा। इन निर्यातों की कुल कीमत लगभग 8.3 अरब डॉलर है। इस ट्रेड डील में रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18% हो गया है, लेकिन 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लगाए गए शुल्क पहले की तरह ही लागू रहेंगे, जैसा कि अमरीका के अन्य व्यापार समझौतों में भी देखा गया है। यही वजह है कि कई अहम भारतीय उत्पादों को अभी भी ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ेगा। धारा 232 के तहत आने वाले उत्पाद जैसे स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, लकड़ी, तांबा और कुछ मशीनरी पर टैरिफ पहले की तरह लागू रह सकते हैं।

इन उत्पादों पर रह सकता है ऊंचा टैरिफ

उत्पाद	टैरिफ	निर्यात
स्टील	50	2.5
एल्युमिनियम-तांबा	50	1.8
फर्नीचर	50	1.50
ऑटोमोबाइल-पार्ट्स	25	3.9

(इन पर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लगा है टैरिफ, 2024-25 में हुआ निर्यात अरब डॉलर में)

अमरीकी पर इनकी ज्यादा निर्भरता

सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा। इस श्रेणी में भारत का 3.9 अरब डॉलर का निर्यात जोखिम में है। इसके बाद स्टील का 2.5 अरब डॉलर और एल्युमिनियम का करीब 80 करोड़ डॉलर का निर्यात शामिल है। ये तीनों सेक्टर मिलकर कुल प्रभावित निर्यात का 85% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। चिंता की बात यह है कि इन उत्पादों में भारत की अमरीकी बाजार पर निर्भरता काफी ज्यादा है। 2024 में भारत के लकड़ी निर्यात का 39%, एल्युमिनियम का 37% और स्टील का 34% हिस्सा अमरीका गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, इतनी ज्यादा निर्भरता के चलते टैरिफ में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी भारतीय कंपनियों के मुनाफे, प्रतिस्पर्धा और निवेश योजनाओं पर बड़ा असर डाल सकती है। नजरें अब डील की डिटेल्स पर हैं।

इन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस डील का सबसे ज्यादा फायदा आइटी सेवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और इंजीनियरिंग सामान बनाने वाली कंपनियों को होगा। इससे भारतीय कंपनियों के लिए अमरीकी बाजार में अपने उत्पाद और सेवाएं बेचना आसान होगा। खासतौर पर आइटी और एआइ सेवाओं में भारत पहले से मजबूत स्थिति में है, ऐसे में अमरीकी कंपनियों से नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी। इंजीनियरिंग सामान जैसे और औद्योगिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी इस समझौते से फायदा हो सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल, सी-फूड, ऑटो एंसिलियरी और केमिकल कंपनियों को लाभ होगा।

लोकसभा: नरवणे की 'किताब' के हवाले से हुआ हंगामा

राहुल ने उठाया डोकलाम मुद्दा, राजनाथ-शाह का जोरदार विरोध

नरवणे ने ऐसा नहीं कहा...

नरवणे ने ऐसा नहीं कहा है। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती है। जब राहुल ने खुद कह दिया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। बात ही खत्म हो जाती है। जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है उसका जिक्र कैसे कर सकते हैं।' **- अमित शाह,** गृह मंत्री

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. लोकसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक (मेमॉयर) के हवाले से कथित तौर पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का जिक्र करने पर जोरदार हंगामा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के कथन का यह कहकर विरोध किया कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है उसके हवाले से सदन में नहीं बोला जा सकता।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल को बार-बार समझाया कि सदन में केवल अखबार में प्रकाशित समाचार का ही हवाला दिया जा सकता है। राहुल के नहीं मानने पर स्पीकर बिरला ने दूसरे वक्ता का नाम भी पुकारा लेकिन सदन में हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले दो बार और बाद में मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

राहुल किताब लाएं, वह छपी ही नहीं...

राहुल जिस किताब के बारे में बोल रहे हैं वह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। वह किताब ले आएं मैं देखना चाहता हूं। मैं दावे से कह रहा हूं कि वह किताब पब्लिश ही नहीं है।'

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

किताब छपने नहीं दी, उसमें ऐसा क्या

यह सब नरवणे ने कहा है। उनकी किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया गया है। जब हम टेररिज्म से लड़ते हैं, लेकिन एक तथ्य से डरते हैं। उसमें ऐसा क्या है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते।'

- राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

सदन तय नियमों से ही चलेगा

(राहुल से) सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सदन नियमों से चलेगा। आसन व्यवस्था दे चुका है, इसके बाद भी आप लगातार अवहेलना कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित के विषय पर हम सेना की आलोचना करेंगे, तो ये उचित नहीं होगा। **- ओम बिरला,** स्पीकर, लोकसभा

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी बात ध्यान से सुनें तो पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं? राहुल ने पूर्व जनरल नरवणे के मेमॉयर के हवाले से एक मैग्जीन के लेख को उद्धरित करते हुए कहा कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा तक पहुंच गए थे, वह 100 मीटर दूर थे।

पेनियार नदी विवाद

ट्रेंडिंग न्यूज

अंतरराज्यीय ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश

नई दिल्ली@ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेनियार नदी के जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के निपटारे के लिए जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करे। केंद्र को एक माह में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है।

आय से अधिक संपत्ति

मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

नई दिल्ली@ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री और शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। उन पर 540 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप है। पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

■ गोविंदा, शक्ति कपूर पर एफआइआर दर्ज

गाजियाबाद@ पत्रिका. निवेश धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी का प्रचार करने के लिए अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडे और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के नाम एफआआर दर्ज हुई है। कोर्ट में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोप है कि मोटे रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा दिया गया।

■ जाति जनगणना के खिलाफ सुनवाई नहीं

नई दिल्ली@ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की प्रस्तावित जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल करने के तरीकों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत विषय है और तरीका तय करना सरकार का काम है, न कि अदालत का।

पेज वन का शेष...

मोदी से ...

ट्रेड डील टाइमलाइन: संकट से राहत तक

फरवरी 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन का दौरा किया। दोनों देशों ने 2025 के अंत तक सीमित व्यापार समझौते और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने अमरीका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने का भरोसा दिया।

मार्च 2025: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन में अमरीकी अधिकारियों से मुलाकात की। अमरीका ने भारत के ऊंचे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं पर चिंता जताई, पर बातचीत आगे बढ़ी।

अप्रेल 2025: अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के दौरान वार्ता की शर्तें तय हुईं। जुलाई 9 से पहले समझौते की उम्मीद जगी।

मई 2025: गोयल और मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल फिर वाशिंगटन पहुंचे। भारत ने समझौता नजदीक होने का संकेत दिया।

जून 2025: अमरीका ने प्रगति की बात कही, लेकिन कृषि आयात शुल्क पर अड़चन सामने आई। मोदी ने ट्रंप का अमरीका आने का निमंत्रण ठुकराया।

जुलाई 2025: बातचीत बिना नतीजे लौटी। 31 जुलाई को ट्रंप ने 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीद पर चेतावनी दी।

अगस्त 2025: रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% जुर्माने के साथ कुल टैरिफ 50% कर दिया गया।

सितंबर 2025: दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने और समझौते को लेकर आशावाद जताया।

अक्टूबर 2025: ट्रंप ने मोदी से फोन कॉल का दावा किया, भारत ने खंडन किया।

नवंबर 2025: वार्ता जारी रही, कोई औपचारिक घोषणा नहीं।

दिसंबर 2025: मोदी-ट्रंप की वास्तविक फोन बातचीत हुई, चर्चा आगे बढ़ी।

जनवरी 2026: अमरीकी दूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश समझौते के करीब हैं।

फरवरी 2026: ट्रेड डील पर सहमति। भारत पर अमरीकी टैरिफ घटकर 18% हुआ।

बच्चों को...

पुणे में नशे में लग्जरी गाड़ी चला रहे कार नाबालिग कार चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर घसीटा था, जिसमें मध्यप्रदेश के दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। बाद में कार में बैठे नाबालिगों के रक्त के नमूने बदलने पर धोखाधड़ी व सबूत मिटाने के आरोप में तीन जनों को गिरफ्तार किया गया था। बेंच ने आरोपियों के 18 महीने जेल में रहने के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली लेकिन हालात पर कड़ी टिप्पणियां कीं।

सरपंच बनने...

पुलिस ने शव को बाहर निकालकर तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कीं।

इस पर एक ग्रामीण ने प्राची कर पहचान कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम केरूर गांव पहुंची। पहले पांडुरंग ने झूठ बोला कि बच्ची इलाज के लिए बाहर है, लेकिन सख्त पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पांडुरंग पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं गांव के मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे को भी सह-आरोपी बनाया गया है।

लद्दाख को ...

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने याचिका दायर कर उनकी हिरासत को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 32 के तहत अदालत हिरासत आदेशों पर अपील की तरह विचार नहीं करती। उसका मुख्य सवाल यह होता है कि हिरासत आदेश के कारण, आधार और सामग्री का नेशनल सिक्योरिटी से कोई संबंध है या नहीं? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि वांगचुक के भाषण युवाओं को भड़काने वाले हैं और सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने हालात को देखते हुए गिरफ्तारी का सही फैसला लिया। मामले की अब मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वे जोधपुर जेल में हैं।

दलाई लामा...

बैंड बनी ने कुल तीन पुरस्कार जीते। उधर, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने ग्रैमी जीतकर अपना 'ईगोट' (एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी अवॉर्ड)पूरा कर लिया। समारोह में लेडी गागा, जस्टिन बीबर, फैरेल विलियम्स और सबरीना कारपेंटर सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। ट्रेवर नोआ ने समारोह को होस्ट किया।

अनुष्का शंकर अवॉर्ड पाने से चूकी...पंडित रविशंकर की पुत्री और भारतीय मूल की विश्वविख्यात सितार वादक अनुष्का शंकर इस बार दो श्रेणियों में नामांकित होने के बावजूद पुरस्कार जीतने से चूक गईं। इन प्रोजेक्ट्स में अनुष्का के साथ आलम खान और सारथी कोरवार भी शामिल थे।

फ्यूजन बैंड शक्ति भी जीत से पीछे रह गया। इंडो-अमरीकी जैज पियानोवादक चारु सूरी को 'शयन' के लिए आधुनिक वाद्य संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला था, जो पुरस्कार में नहीं बदल पाया। सिद्धांत भाटिया का 'साउंड्स ऑफ कुंभ' भी खाली हाथ लौटा।

प्रेरणा

जीवन छोटे-छोटे पलों का संग्रह है। इन पलों को संजोइए और जीवन को उत्सव बनाइए। -मदर टेरेसा

संपादकीय

एआई और रिसर्च के लिए और फंडिंग की दरकार है

बजट भाषण के चंद मिनटों बाद सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स तक गिरा, फिर कुछ उठा, लेकिन निराशा से उबरा नहीं। यह स्थिति अर्थशास्त्रियों के एक बड़े वर्ग की ही नहीं, आम जनता की भी है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव, ट्रम्प टैरिफ का दंश और दुनिया में क्रांति का सबब बनने जा रहे एआई के दौर में इस आम बजट से अपेक्षा कुछ अलग थी। उम्मीदें थीं कि रक्षा पर खर्च असाधारण रूप से बढ़े, एमएसएमई सेक्टर को बूस्टर डोज मिले और एआई के क्षेत्र में स्वदेशी मॉडल विकसित करने के लिए रिसर्च पर आशातीत फंडिंग हो। भारत में रिसर्च को हमेशा गौण रखा गया है और इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। बजट इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। लेकिन अगर सरकार की स्थिति पर गौर करें तो पिछले आठ साल में राजस्व दूना बढ़ा है, जबकि टैक्स छूट तीन गुनी। नॉमिनल जीडीपी विकास दर लगातार पिछले कुछ वर्षों में 19% से घटकर 8% हो गई है। वित्तीय घाटा कम करने के लिए खर्च कम करना मजबूरी थी। यही कारण है कि रक्षा बजट मात्र 15% बढ़ा, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता गया है और वैश्विक महंगाई भी बढ़ी है। हथियार खरीदने में अब ज्यादा रुपयों की जरूरत होगी। निराशा का एक अन्य कारण है एआई पर शोध के लिए अलग से आवंटन न होना और सेमी-कंडक्टर निर्माण के लिए जरूरी ऊर्जा उत्पादन के लिए मिशन मोड में न जाना।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

आश्रम किसी गतिविधि के नहीं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं

हम मनुष्यों के जीवन में तीन जगहें ऐसी हैं, जहां हमारा आना-जाना-रहना बना ही रहता है। घर हमारा आसरा है, दफ्तर हमारा कार्यस्थल, और बाजार। लेकिन एक चौथी जगह भी तुलसीदास जी ने बताई है। पक्षीराज गरुड़ ने काकभुशुंडि जी के पास पहुंचकर कहा- यहां आते ही मेरे सब काम हो गए। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संसय नाना भ्रम। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम- सब जाते रहे। तो चौथी जगह आश्रम है, जिसमें मंदिर समाया हुआ रहता है। गरुड़ जी कहते हैं कि मेरा मोह, संदेह और भ्रम तीनों मिट गए। घर में हमको मोह पैदा होता है, दफ्तर में हम संदेह से गुजरते हैं और बाजार तो भ्रम पैदा करते ही हैं। इन तीनों को मिटाने के लिए हमें प्रतिदिन किसी न किसी आश्रम, या कहें मंदिर आते-जाते रहना चाहिए। ये किसी गतिविधि के केंद्र नहीं होते, ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। आश्रम पद्धति भारतीय ऋषि-मुनियों की मौलिक गतिविधि है, जिससे हम आज भी जुड़े रहें तो हमें लाभ मिलेगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • मौजूदा दौर में दोहरी रणनीति जरूरी है

हम केवल 'आत्मनिर्भरता' पर ही भरोसा नहीं कर सकते

इकोनॉमी

आशुतोष वार्ष्णेय

ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर

भारत को बदलती हुई विश्व-व्यवस्था का जवाब कैसे देना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले एक बड़े सवाल का जवाब देना जरूरी है। यह कि आज दुनिया में भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था का क्या रिश्ता है?

वैश्वीकरण के हालिया दौर में- जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जिसे मजबूती मिली- आम तौर पर भू-राजनीति अर्थव्यवस्था के पीछे चलती थी और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बाजार-आधारित थी। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संबंध आर्थिक हितों के आसपास बने थे। दुनिया के मंच पर चीन का उभार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2002 में पश्चिम के समर्थन से, चीन- जो राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट था, लेकिन आर्थिक रूप से कम्युनिस्ट नहीं रह गया था- को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शामिल किया गया।

यह याद रखना जरूरी है कि 1972 में चीन-अमेरिका के बीच हुआ शुरुआती मेल-मिलाप पूरी तरह रणनीतिक था, आर्थिक नहीं। उस समय चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा था और दुनिया को देने के लिए उसके पास कोई खास उत्पाद नहीं थे। उसका व्यापार/जीडीपी अनुपात सिर्फ 5% था। न ही वह विदेशी निवेश का स्वागत कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन को साझेदार के रूप में देखा था, लेकिन 1991 के बाद भी अमेरिका ने चीन से दूरी नहीं बनाई। इसके बजाय, जैसे-जैसे चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोले, अर्थव्यवस्था चीन-अमेरिका रिश्ते की बुनियाद बनती गई। बड़े आर्थिक अवसरों ने चीन के अमेरिका और पश्चिम के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया। देश और कंपनियां तेजी से चीन की ओर दौड़ीं।

आज स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था भू-राजनीति के पीछे चलने लगी है, हालांकि वह अभी पूरी तरह से उसके अधीन नहीं हुई है। अगर चीन का डब्ल्यूटीओ में शामिल होना इसका सबसे बड़ा संकेत था कि पहले अर्थव्यवस्था भू-राजनीति पर भारी थी, तो अब ट्रम्प द्वारा टैरिफ को भू-राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना नए दौर का सबसे बड़ा इशारा है। कभी टैरिफ एक आर्थिक औजार हुआ करता था और वैश्वीकरण के दौर में ज्यादातर देश इन्हें न्यूनतम स्तर तक कम करना चाहते थे, लेकिन पिछले एक साल में अमेरिका ने अपने पुराने सहयोगियों पर भी टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि अब वह उन्हें ज्यादा काम का नहीं मानता।

1949 में अमेरिका के संरक्षण में पश्चिमी यूरोप को सोवियत संघ से बचाने के लिए बनाए गए नाटो के साथ ट्रम्प का व्यवहार नई भू-राजनीति का अहम उदाहरण है। ग्रीनलैंड से जुड़ी अपनी योजनाओं के लिए ट्रम्प उन नाटो देशों को दंडित करने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल करने को तैयार थे, जिन्होंने उनका विरोध किया। हालांकि बाद में उन्होंने कदम पीछे खींच लिए।

2028 से 2030 के बीच भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन क्या यह रफ्तार आगे भी बनी रह पाएगी? ट्रम्प द्वारा भारत के अमेरिका जाने वाले निर्यात पर ऊंचे टैरिफ लगाना इस समस्या का बड़ा हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनाया है और चीन पर उतने कड़े टैरिफ नहीं लगाए, जबकि चीन भी भारत का एक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है।

ऐसे माहौल में आत्मनिर्भरता की बात करना आकर्षक लगता है, लेकिन यह व्यावहारिक विचार नहीं है। भारत का व्यापार/जीडीपी अनुपात अब बहुत छोटा नहीं है, जैसा कि 1970 के दशक तक था। अब यह 40% से ज्यादा है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है। आज भारत अचानक अपने

आत्मनिर्भरता की बात करना आकर्षक लगता है, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। भारत का व्यापार/जीडीपी अनुपात अब बहुत छोटा नहीं है, जैसा कि 1970 के दशक तक था। आज भारत अचानक अपने अंदर ही सिमट नहीं सकता।

अंदर ही सिमट नहीं सकता, क्योंकि इससे उसे भारी आर्थिक नुकसान होगा। यह देखते हुए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आत्मनिर्भर देशों ने खुद को कितना नुकसान पहुंचाया- जबकि व्यापार पर निर्भर देश (जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और 1980 के दशक के बाद चीन) आगे बढ़े- आत्मनिर्भरता की लंबी अवधि की उपयोगिता पर भी सवाल उठते हैं।

भारत की आर्थिक रणनीति दो हिस्सों वाली होनी चाहिए : बाहर की ओर संतुलन और अंदरूनी नियामक ढांचे को सरल बनाना। भले ही अमेरिका ने कुछ दूरी बना ली हो, भारत को उसके साथ कारोबार करने का रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही, दूसरे बड़े बाजारों की तलाश करनी चाहिए, जैसे ईयू और चीन। ईयू के साथ ट्रेड डील सही दिशा में कदम है। रणनीतिक उलझनों के बावजूद चीन को भी छोड़ा नहीं जा सकता। अंदरूनी नियामक ढांचे को सरल बनाना भी इतना ही जरूरी है, मुख्य रूप से कर प्रणाली, जमीन और श्रम बाजार से जुड़े मामलों में। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

नजरिया • बलूचों और तालिबान से टकराव जारी

पाक खुद ही आतंक की जड़ को खत्म नहीं करना चाहता

आस-पड़ोस

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी उथलपुथल के दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। यों यह अतीत के परिचित पैटर्न को ही दोहराता है, लेकिन इस बार यह हमारे लिए कहीं कठिन क्षेत्रीय व आर्थिक परिस्थितियों के दौरान सामने आ रहा है। बीते दिनों बलूच विद्रोहियों और इस्लामवादी उग्रवादियों से जुड़े टकरावों में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है। इस तरह की घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं।

एक ओर, बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के साथ सीधे संघर्षों के जरिये अपने विद्रोही अभियान को फिर से तेज किया है। दूसरी ओर, हरनाई और पंजगुर में हालिया सैन्य छापे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ प्रतीत होते हैं। दोहरे मोर्चे की यह आंतरिक चुनौती- अलगाववादी विद्रोह और वैचारिक आतंकवाद- वैसी ही है, जिसने अतीत में भी पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है।

पाकिस्तान सेना की तैनाती अभी ऑपरेशन जर्ब-ए-अज्ब जैसे स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन अतीत का अनुभव बताता है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अकसर उसी दिशा में धकेल देता है। बड़े पैमाने पर फौजों की आंतरिक तैनाती अपने साथ जोखिम भी लाती है- जैसे नागरिक क्षेत्रों का सैन्यीकरण, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी मोर्चों से सेनाओं को हटाना।

16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले की स्मृति आज भी पाकिस्तान की रणनीतिक चेतना में गहराई से अंकित है। जिन परिस्थितियों ने उसे जन्म दिया था, उन्हें मूल रूप से आज तक समाप्त नहीं किया गया है। यहीं पाकिस्तान का स्थायी विरोधाभास स्पष्ट होता है। इस्लामवादी आतंकवाद को अब भी एक सुरक्षागत समस्या के रूप में देखा जाता है, न कि एक वैचारिक समस्या के रूप में। कट्टरपंथीकरण के नेटवर्क को तोड़ने, धार्मिक विमर्श में सुधार लाने या समाज के भीतर चरमपंथी नैरेटिव को चुनौती देने के लिए कोई सतत प्रयास नहीं किया गया है। वहीं बलूच विद्रोह का सामना लगभग पूरी तरह बल प्रयोग के जरिये ही किया जा रहा है। ये दो बिलकुल अलग प्रकार के संघर्ष हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों से एक ही घिसे-पिटे तरीके से निपट रहा है।

क्षेत्रीय आयाम इस समस्या को और जटिल बना देता है। आज का अफगानिस्तान केवल पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं, बल्कि ऐसा क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान को कमजोर करने वाली गतिविधिया संभव हैं। काबुल पर पाकिस्तान का प्रभाव अपेक्षा से कहीं कमजोर साबित हुआ है। अमेरिका- जो अब फिर से पाकिस्तान का सहयोगी बन गया है- ने दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सऊदी अरब, तुर्किये और अन्य प्रभावशाली इस्लामी देशों ने भी पाकिस्तान में कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए धार्मिक या वैचारिक पहल करने में बहुत कम रुचि दिखाई है।

पाकिस्तान आतंकवाद से इसलिए प्रभावित नहीं है कि उसके पास सैन्य क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने उन वैचारिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय विरोधाभासों को कभी सुलझाया ही नहीं, जो हिंसा को बनाए रखते हैं। लेकिन यह हम जैसे पड़ोसियों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब-जब पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा चक्र हिंसक मोड़ ले लेता है, तो उसके परिणाम उसकी सीमाओं के बाहर तक फैल जाते हैं।

जैसा कि अकसर होता आया है, पाकिस्तान हिंसा की इस लहर के लिए किसी बाहरी साजिश को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेगा, और हमेशा की

पाकिस्तान आतंकवाद से इसलिए प्रभावित नहीं है कि उसके पास सैन्य क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने उन वैचारिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय विरोधाभासों को सुलझाया ही नहीं, जो हिंसा को बनाए रखते हैं।

तरह वह भारत की ओर अंगुली उठाएगा। लेकिन इस तरह के आरोपों से वह सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता। दशकों तक आतंकी गुटों को जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल करने के लिए पालना-पोसना उसके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना साबित हो सकता है।

आतंकी इको-सिस्टम अपने लिए तय सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। एक नीतिगत औजार के रूप में हिंसा को सामान्य बना देने की प्रक्रिया से समाज भी प्रभावित होता है, जिसमें धार्मिक, जातीय या राजनीतिक- हर तरह के कारणों के लिए बल प्रयोग को जायज ठहराया जाने लगता है। जब तक इसके खिलाफ संगठित सामाजिक प्रतिरोध नहीं होता, तब तक सार्थक बदलाव की संभावना कम है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल **DB एप** पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

एजुकेशन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकल कराने संबंधी विज्ञापन, 187 देशों के छात्रों पर पड़ेगा इसका असर

दुनियाभर के छात्रों के अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन हेतु जरूरी टेस्ट में नकल, सोशल मीडिया पर बिक रहे सवाल

स्टीफेनी साउल

दुनियाभर के छात्रों का सपना होता है कि उन्हें अमेरिका के कॉलेजों में एडमिशन मिले। लेकिन अब दाखिले के लिए होने वाले स्टैंडर्ड एडमिशन टेस्ट (एसएटी) में नकल होने के मामले सामने आए हैं। एसएटी साल में सात से आठ बार होता है। अमेरिकी कॉलेज बोर्ड के नेटवर्क में 187 देशों की 1700 टेस्टिंग साइट हैं। छात्र इन साइट पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं।

तीन साल पहले कॉलेज बोर्ड ने रिटन टेस्ट की जगह डिजिटल एसएटी शुरू किया था। बोर्ड का कहना था इससे चीटिंग कम होगी, क्योंकि टेस्ट में हर छात्र के लिए सवाल अलग होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टेस्ट के सवाल इंटरनेट, सोशल मीडिया और चीनी वेबसाइट्स पर पोस्ट किए गए हैं। इससे दुनियाभर के ऐसे बच्चे, जो अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए खतरा खड़ा हो गया है। नवंबर में एक एसएटी ट्यूटर ने कॉलेज बोर्ड को चीटिंग की जानकारी दी थी। टेस्ट के कुछ माह पहले इंटरनेट पर पूरा पेपर आ गया।

चीन की एक साइट ब्लूबुक डॉटप्लस एसएटी का प्रैक्टिस टेस्ट लेती है। लेकिन उसके कुछ सवाल असल पेपर जैसे लगते हैं। छात्र पैसा देकर इनमें शामिल हो सकते हैं। यहां चौंकाने वाली बात ये है कि कॉलेज बोर्ड के अधिकृत प्लेटफॉर्म का नाम भी ब्लूबुक है। वेब ट्रैफिक साइट सिमिलर वेब के अनुसार नवंबर में ब्लू बुक डॉट प्लस पर 8 लाख 75 हजार विजिटर आए।

धोखेबाजों ने लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जैसे डिजिटल टेस्ट में भी सेंध लगाई है। ऐसे में एसएटी की सिक्योरिटी पर चिंता बढ़ी है। कॉलेज बोर्ड ने माना है कि एसएटी में चीटिंग से 1% टेस्ट स्कोर प्रभावित होते हैं। बोर्ड ने ये भी स्वीकारा कि कुछ देशों में धोखेबाजों ने परीक्षा से जुड़ा कंटेंट शेयर करने के प्रयास किए हैं। कई एसएटी प्रेप वेबसाइट ब्लूबुक की सिक्योरिटी में सेंध लगाने के तरीके बताती हैं। ऑनलाइन विज्ञापनों में छात्रों के कंप्यूटर रिमोट पर लेकर टेस्ट देने की जानकारी रहती है। हैं। चीन की सरकार ने देश में एसएटी पर रोक लगा दी है। © The New York Times

लॉ कॉलेजों के डिजिटल टेस्ट में भी गड़बड़ी

एसएटी में गड़बड़ी से पहले लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए डिजिटल एलएसएटी और जीआरई टेस्ट में चीटिंग होती रही है। ये टेस्ट किसी सेंटर पर नहीं बल्कि रिमोट होते थे। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी सहित कई ग्रेजुएट बिजनेस कॉलेजों ने घाना और नाइजीरिया के छात्रों द्वारा जीआरई में चीटिंग के आरोपों के बाद एडमिशन के ऑफर रद्द कर दिए थे।

चीनी छात्र ने टेस्ट में हो रही धांधली का खुलासा किया

अगस्त में एलएसएटी टेस्ट लेने वाली लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल ने चीन में टेस्टिंग बंद कर दी। काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट सुसान क्रिंस्की का कहना है कि हम चीन में टेस्ट में गड़बड़ी के प्रयासों से चिंतित हैं। अमेरिका में एक चीनी छात्र ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडनोट पर चीटिंग सेवाओं का एड देखने के बाद लॉ कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में धांधली का खुलासा किया था।

टेलीग्राम, गूगल डॉक पर भी अपलोडेड हैं टेस्ट पेपर

दुबई स्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर टेस्ट के सवाल बेचे गए हैं। इन्हें डेटा स्टोरेज स्क्रिब्ड पर पोस्ट किया गया है। एक यूरोपीय ट्यूटर ने बताया कि छात्रों ने गूगल डॉक्स पर भी सवाल पोस्ट किए हैं। अमेरिकी कॉलेज बोर्ड के आग्रह पर स्क्रिब्ड से कई टेस्ट हटा लिए गए हैं। लेकिन बोर्ड चीन से सक्रिय साइट ब्लू बुक डॉट प्लस से नहीं निपट सका है।

ओपिनियन कंपनियों पर मुकदमों से भी आमदनी

ट्रम्प के लिए 'फैमिली फर्स्ट', एक साल में 12 हजार करोड़ रुपए कमाए

एडिटोरियल बोर्ड

दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रम्प ने निजी तौर पर खूब पैसा कमाया है। कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी। इस फिल्म के लिए ट्रम्प परिवार को अमेजन से 256 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अमेजन ने ऐसे ही अन्य प्रोजेक्ट के मुकाबले इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे अमेजन के जेफ बेजोस के पास कई कारण हैं। जैसे कि स्पेस, डिफेन्स प्रोजेक्ट और एकाधिकार विरोधी एंटी ट्रस्ट कानून।

ट्रम्प को मुकदमों से भी खूब आय हो रही है। एबीसी न्यूज, मेटा, पैरामाउंट और यूट्यूब आदि ने ट्रम्प को अरबों रुपए देने पर सहमति जताई है। मस्क भी करीब 90 करोड़ दे रहे हैं। गुणदोष के आधार पर इन मुकदमों को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल बदला लेने वाले राष्ट्रपति का अदालत में सामना करने के बजाय इन कंपनियों ने समझौता कर लिया है और इससे ट्रम्प ने 823 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है।

दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग पेंटागन का कहना है, उसने कतर से बोइंग 747 जेट विमान स्वीकार कर लिया है। उसने कहा कि वे हमें जेट विमान मुफ्त दे रहे हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रम्प कतर से मिलेइस 3660 करोड़ रुपएकेबेशकीमती तोहफे को अपने साथ ले जाने का विचार कर रहे हैं।

ट्रम्प परिवार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्रिप्टो करेंसी है। सरकार की नीति को प्रभावित करने की आशा रखने वाले लोग ट्रम्प परिवार के कॉइन खरीदकर ट्रम्प को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि ये करार अकसर गुप्त ही रहते हैं। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष संयुक्त अरब अमीरात की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ट्रम्प की कंपनी से 18 हजार करोड़ रुपए की डील की है। दो सप्ताह बाद राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात को एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स दे दी। © The New York Times

क्रिप्टो से हुई खूब कमाई

ट्रम्प ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी से 7029 करोड़ रुपए कमाए हैं। कुल मिलाकर ट्रम्प सालभर में अबतक 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक कमा चुके हैं। यह अमेरिका में मध्यमवर्गीय परिवार की आय से 16822 गुना अधिक है। यह अनुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड से लगाया है। इसलिए आंकड़ा न्यूनतम है। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का कथन है कि यह मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया है। पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं।

बदलाव टूरिज्म कंपनियां जमा रहीं डेरा

खाली पड़े यूरोपीय गांवों की तकदीर बदली, 9 करोड़ तक में बिक रहे हैं

ब्रेंटक्रेन

रोजगार की तलाश में लोगों के बाहर चले जाने से यूरोप में हजारों गांव खाली हो चुके हैं। स्पेन, पुर्तगाल और इटली में गांवों के खाली होने की समस्या राजनीतिक मसला बन चुकी है। इन देशों में लोग अब गांव खरीद सकते हैं। कुछ तो नौ करोड़ रुपए में मिल सकते हैं। अमीरों और टूरिज्म कंपनियों ने ऐसे गांव खरीदने की शुरुआत कर दी है। कुछ गांवों को किसी एक व्यक्ति या परिवार ने बेच दिया है। वहीं कुछ गांवों में लोगों ने अलग-अलग संपत्तियां खरीदी हैं।

अमीर खरीदार और टूरिज्म आंत्रप्रेन्योर ने खाली पड़े गांवों का चेहरा बदल दिया है। कुछ गांव तो अब कंपनियों के लिए छुट्टियां बिताने की जगह बन गए हैं। एफोर्ड होम कंपनी की टिमुर नेग्रू का कहना है, पिछले कुछ माहों में गांव खरीदने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़ी है। स्टारलिंक जैसे प्लेटफॉर्म के कारण इंटरनेट की आसान पहुंच, फ्लोरेंस, बार्सीलोना जैसे भीड़ वाली जगहों से दूर जाने की इच्छा और अमेरिका में संपत्ति के ऊंचे मूल्यों की वजह से लोग आकर्षित हो रहे हैं। जर्मन उद्यमी जोहांस होयोस की कंपनी कैम्पफायर ने डेल, गूगल और नेटफ्लिक्स सहित कई कंपनियों के लिए दक्षिण यूरोप के गांवों में रिट्रीट आयोजित किए हैं।

© The New York Times

बिजनेस चिप कंपनियां मुनाफे के चलते महंगी चिप डेटा सेंटर्स को दे रहीं

एआई में उछाल से पर्सनल कम्प्यूटर, स्मार्टफोन महंगे होंगे

डॉन क्लार्क

ओपनएआई, मेटा, गूगल और अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच एआई में जीतने की होड़ जारी है। उन्हें डेटा सेंटरों के लिए मेमोरी चिप्स की जरूरत पड़ती है। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य कंपोनेंट्स पर पड़ने लगा है। नतीजतन कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट भी प्रभावित होंगे।

चिप बनाने वाली कंपनियां कम्प्यूटर और स्मार्टफोन कंपनियों की तुलना में महंगी चिप एआई डेटा सेंटरों को बेचकर अधिक पैसा कमा सकती हैं। इससे कंज्यूमर ग्रेड चिप्स की सप्लाई धीमी पड़ गई है। उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका बोझ कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च फर्म टेक इनसाइट्स का अनुमान है, मेमोरी चिप्स की ज्यादा कीमतों से अमेरिका में सितंबर से सामान्य पर्सनल कम्प्यूटर के मूल्य 23% बढ़ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ फाइनेंशियल अधिकारी एमी हुड का कहना है, मेमोरी चिप्स के मूल्यों में वृद्धि का पीसी मार्केट पर असर पड़ेगा। इससे पीसी से आय कम होने की संभावना है।

मेमोरी चिप्स को लंबे समय से सामरिक महत्व की वस्तु माना जाता है। इससे अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। द. कोरिया की सैमसंग, एसके हाइनिक्स की अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी से होड़ है। अभी हाल में कुछ चीनी कंपनियां बाजार में आई हैं। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन चिप्स की जमकर बिक्री हो रही है।

पिछले साल सितंबर में आरएएम चिप्स के पीसी किट का मूल्य 9611 रु. था। ये दिसंबर में 22885 रु. हो गया। एप्पल, डेल जैसी कंपनियां चिप सप्लायरों से लंबे समय के सौदे करती हैं। इससे मूल्यों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता है। फिर भी 3 जनवरी को स्टैंडर्ड लैपटॉप के मूल्य 7% बढ़ गए थे। © The New York Times

चिप इंडस्ट्री की आय 91 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी

मेमोरी चिप बूम से समूची चिप इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। इस साल चिप इंडस्ट्री की कुल आय 28 फीसदी बढ़कर 91 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में कई ट्रेंड शुरू करने वाली एनवीडिया बड़े पैमाने पर मेमोरी चिप एचबीएम खरीदती है। ये आरएएम से अधिक तेजी से डेटा ट्रांसफर करती हैं।

नया ट्रेंड

चीन: गलती से बने खिलौने की भारी मांग, ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे

जॉयडॉंग

फैक्ट्री की गलती से बना एक टॉय चीन के लोगों के मूड की तस्वीर बन गया है। इस टॉय को क्राइंग हॉर्स के नाम से पुकारा जा रहा है। यह पिछले साल पूर्व चीन में एक दुकान में देखा गया था। टॉय के पांव छोटे और मोटे हैं। बगल में लिखा है, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैन्युफैक्चरिंग की भूल के कारण उसका मुंह सिला हुआ है। चेहरे पर मुस्कान के बजाय उदासी दिखाई पड़ती है। 17 फरवरी से शुरू होने वाले लुनार वर्ष से पहले टॉय ऑनलाइन सनसनी बन गया है। क्राइंग हॉर्स हैशटैग टिकटॉक के चीनी संस्करण डाउविन एप पर 19 करोड़ बार आया है। टॉय को लेकर चुटकुला चल रहा है कि मुस्कान घर पर छोड़कर रोते हुए चेहरे के साथ काम पर जाइए। पहली बार टॉय बेचने वाली झांग हुओकिंग मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। वे हर दिन लगभग 15 हजार टॉय बेचती हैं। झांग की दुकान यिवू में दुनिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में है। © The New York Times

शेयर मार्केट • मोमेंटम इंडिकेटर्स मजबूती की ओर झुके, निफ्टी 25,200 का स्तर टूटने पर 25,350 की ओर बढ़ेगा

एसटीटी के डर से उबरे, निफ्टी 25 हजार पार

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

बजट झटकों (एसटीटी टैक्स) को पीछे छोड़ते हुए घरेलू बाजार ने सोमवार को कमबैक किया। सेंसेक्स 943 अंक उछलकर 81,666 पर बंद हुआ। निफ्टी ने इंट्राडे में 25,100 का स्तर छुआ और 263 अंकों की मजबूती के साथ 25,088 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.96% और स्मॉलकैप 100 में 0.84% की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 500 यूनिवर्स के 310 शेयर सकारात्मक दायरे में बंद हुए। सेक्टर के लिहाज से बाजार का रुख सकारात्मक रहा, जिसमें निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे आगे रहे।

एसबीआई सिक्युरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट सुदीप शाह के मुताबिक बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स ने 24,679 के शुरुआती निचले स्तर तक फिसलने के बाद इंट्राडे में शानदार रिकवरी दिखाई। डेली टाइमफ्रेम पर, निफ्टी ने 'बुलिश कैंडल' बनाई जिसके साथ 'लोअर शैडो' भी दिखी, जो निचले स्तरों पर खरीदारी को दिखाती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आरएसआई बाउंस बैक कर 30.93 के निचले स्तर से 39.20 पर आ गया। यह गिरावट के दबाव के कम होने और रिकवरी की ओर बढ़ने की संभावना को दिखाता है। निफ्टी के लिए 24,930-24,900 का क्षेत्र तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। वहीं, 25,200 के ऊपर किसी भी टिकाऊ बढ़त से शार्ट टर्म में निफ्टी 25,350 के स्तर तक बढ़ सकता है।

बजट इम्पैक्टः दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने चुने टॉप स्टॉक्स; इन्फ्रा और डिफेंस शेयरों में 113% तक रिटर्न की उम्मीद

एसबीआई सिक्युरिटीजः बैंकिंग से लेकर सीमेंट शेयर 17% तक रिटर्न दे सकते हैं

कंपनी का नाम	मौजूदा मूल्य	लक्ष्य	बढ़त
ICICI बैंक	1,334	1,535	15%
अल्ट्राटेक सीमेंट	12,285	14,378	17%
360 वन वाम	1,117	1,296	16%
बेलराइज इंडस्ट्रीज	165	191	16%
टीडी पावर सिस्टम्स	740	855	16%

- एसबीआई सिक्युरिटीज के मुताबिक बजट सरकार की 'पूंजीगत व्यय से विकास' की रणनीति को जारी रखता है। फोकस सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, क्लाउड और इलेक्ट्रॉनिक्स पर है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो।
- निवेशकों का ध्यान अच्छे शेयरों, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते व डॉलर पर होना चाहिए।
- **पसंदीदा सेक्टरः** ऑटो, डिफेंस, सीमेंट, फार्मा, ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स), माइनिंग, बैंकिंग।

पीएल कैपिटलः अदाणी पोर्ट्स, एचएएल जैसे शेयर दिला सकते हैं 40% तक रिटर्न

कंपनी का नाम	मौजूदा मूल्य	लक्ष्य	बढ़त
अदानी पोर्ट्स	1,345	1,876	39.5%
भारती एयरटेल	1,949	2,259	15.9%
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	5,758	6,761	17.4%
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स	4,377	5,507	25.8%
ICICI प्रूडेंशियल एएमसी	2,927	3,300	12.7%

- पीएल कैपिटल के मुताबिक बजट में बुनियादी ढांचे, रक्षा उत्पादन, ग्रामीण व शहरी विकास पर जोर है।
- **फायदेमंद सेक्टर्सः** बैंकिंग, एनबीएफसी, अस्पताल, ऑटो, रक्षा, पोर्ट्स व टेलीकॉम सेक्टर को लंबी अवधि में बजट घोषणाओं का लाभ मिलने की संभावना है।
- बाजार बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित नीतियों से खुश। कमोडिटी की घटते दाम, सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

इलारा कैपिटलः इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स लंबी अवधि में 113% तक रिटर्न दे सकते हैं

कंपनी का नाम	मौजूदा मूल्य	लक्ष्य	बढ़त
एचजी इन्फ्रा	625	1,330	113%
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन	19	35	81%
एनबीसीसी इंडिया	95	165	73%
एफकॉन्स इन्फ्रा	333	567	70%
पीएनसी इन्फ्राटेक	226	330	46%

- वित्त वर्ष 27 के लिए कुल पूंजीगत व्यय में 9% की बढ़ोतरी की गई है। अब ध्यान शहरी बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, जल और शिपिंग पर है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और 500 जलाशयों का निर्माण।
- **नई रणनीतिः** सरकार अब पूरी तरह सरकारी फंडिंग के बजाय पीपीपी और 'एसेट मोनेटाइजेशन' पर निर्भरता बढ़ा रही है। शिपिंग और टियर 2/3 शहरों के इंफ्रा पर निवेश से भविष्य में बेहतर रिटर्न की उम्मीद है।

तेजी की वजह | सस्ते क्रूड और 'अच्छी खबर' से आया उछाल

बजट उम्मीदों के अनुरूपः एसटीटी वृद्धि को छोड़कर बजट काफी सकारात्मक रहा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रति लॉट लागत केवल 4-5 बढ़ेगी, जिससे वॉल्यूम पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

कच्चे तेल में बड़ी राहतः अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से डब्ल्यूटीआई क्रूड 5% से ज्यादा गिरा। चांदी की कीमतों में गिरावट से ऑटो और केबल जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का मार्जिन बढ़ेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डीलः केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के जल्द 'अच्छी खबर' देने के संकेत ने बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी निकली और मार्केट में रिकवरी देखी गई।

संसद के सवाल-जवाब

बिजनेस के लिए लोन लेने वाली महिलाएं दोगुनी हुईं

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

महिलाएं अब छोटे कारोबारों के लिए ज्यादा कर्ज ले रही हैं। 5 साल में संख्या दोगुनी हो गई है। रिटेल लोन लेने वाली महिलाएं 2.14 गुना और छोटे व मझोले कारोबार (एमएसएमई) के लिए कर्ज लेने वाली 2.62 गुना बढ़ी है। स्टैंडअप इंडिया स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी 82% है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि महिलाओं के छोटे कारोबारों पर मुद्रा योजना का असर जानने के लिए दो अलग-अलग अध्ययन कराए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 2018 के राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, 2015 से 2018 के बीच मुद्रा योजना से करीब 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए।

सरकारी योजनाओं में अब 80% तक शेयर

जीवन ज्योति बीमा	54%
सुरक्षा बीमा	51%
स्टैंड-अप इंडिया	82%
मुद्रा योजना	67%

उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में मांग ज्यादा

राज्य	खाते
बिहार	4.98 करोड़
तमिलनाडु	3.88 करोड़
उत्तर प्रदेश	3.57 करोड़
प. बंगाल	3.54 करोड़
महाराष्ट्र	3.50 करोड़

2.7 करोड़ महिलाएं क्रेडिट स्कोर ट्रैक कर रहीं

बिजनेस लोन में 9 फीसदी से बढ़कर 16 फीसदीः महिलाएं अब केवल व्यक्तिगत जरूरतों तक सीमित नहीं हैं। बिजनेस लोन के क्षेत्र में हिस्सेदारी 9 फीसदी (2019) से बढ़कर अब 16 फीसदी (दिसंबर 2024) हो गई है।

क्रेडिट स्कोर को लेकर सजगः महिलाएं वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं। वर्तमान में करीब 2.7 करोड़ महिलाएं अपना क्रेडिट स्कोर ट्रैक कर रही हैं। 2023 के मुकाबले 42 फीसदी वृद्धि।

- महिलाएं लोन लेने से पहले वित्तीय प्रोफाइल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही हैं, ताकि आसान शर्तों पर कर्ज मिल सके।
- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी और तेलंगाना जैसे राज्यों ने महिलाओं में क्रेडिट सशक्तीकरण को बहुत तेजी से अपनाया है।

बिजनेस ब्रीफ

2,000 के 98.42 फीसदी नोट आरबीआई में वापस

मुंबई | आरबीआई के अनुसार, 2,000 रुपए के नोटों का 98.42% हिस्सा वापस आ चुका है। 19 मई 2023 को 2,000 के नोटों को चलन से बाहर करते समय प्रचलन में रहे नोटों का मूल्य 3.56 लाख करोड़ था। 31 जनवरी 2026 को ये आंकड़ा घटकर 5,609 करोड़ रुपए रह गया है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए का नोट अभी भी एक कानूनी मुद्रा है।

ह्युंडई मोटर इंडिया का मुनाफा 6% बढ़ गया

नई दिल्ली | ह्युंडई मोटर इंडिया का वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंसॉलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 6.3% सालाना बढ़कर 1,234 करोड़ रुपए हो गया। त्योहारी मांग और निर्यात में बढ़ोतरी के चलते परिचालन राजस्व 8 फीसदी बढ़कर 17,974 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कर पूर्व आय (एबिटा) में वार्षिक आधार पर 7.6% की वृद्धि हुई। कंपनी का निर्यात 21.1% बढ़ गया।

बॉन्ड यील्ड में एक साल की सबसे ज्यादा उछाल

नई दिल्ली | सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2027 के लिए बॉन्ड के जरिये 17.2 लाख करोड़ रुपए की उधारी की घोषणा के बाद सोमवार को सरकारी बॉन्ड यील्ड में उछाल आई। बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 0.07% बढ़कर 6.77% पर स्थिर हो गई। यह एक वर्ष में सबसे अधिक है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक अगर वर्ष के दौरान 47 नीलामी मानें तो यह हर हफ्ते 31,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सुधरकर 55.4 पर आया

नई दिल्ली | नए ऑर्डर में तेजी से जनवरी में देश का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दिसंबर के दो साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर 55.4 पर पहुंच गया। नौकरी बढ़ने की रफ्तार 3 माह में सबसे तेज रही। हालांकि बिजनेस कॉन्फिडेंस साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर आया। सिर्फ 15% कंपनियों ने अगले एक साल में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई, 83% को कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।

चांदी • 4 दिन में 1.2 लाख टूटी; क्या खरीदारी का मौका?

दिन में 2.25 लाख तक गिरी चांदी, फिर संभली, 2.6 लाख पर पहुंची

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

कमोडिटी मार्केट में सोमवार को चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। एमसीएक्स पर चांदी का मार्च वायदा 2.67 लाख के ऊपरी स्तर से गोता लगाकर 2.25 लाख के निचले स्तर तक पहुंच गया। निचले स्तरों पर आई खरीदारी ने कीमतों को कुछ सहारा दिया। इससे यह एक दिन में 6.6% टूटकर 2.48 लाख रुपए पर रही। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में भी यह उलटफेर देखा गया और सोमवार सुबह चांदी टूटकर 236496 के स्तर तक आ गई। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोमवार को चांदी 2,59,500 प्रति किलो पर बंद हुई, जो एक दिन पहले 2,65,751 पर थी।

चांदी में यह गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि महज 4 दिन पहले, 29 जनवरी को इसने 3,79,988 का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर छुआ था। इस लिहाज से देखें तो चांदी अपने शिखर से करीब 1,20,488 प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। हालांकि, लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2,30,420 पर बंद हुई थी, यानी इस साल अब भी यह निचले स्तरों से ऊपर बनी हुई है।

बड़ा सवालः चांदी में क्यों आया क्रैश और आगे क्या?

चांदी की इंडस्ट्रियल मांग मजबूत बनी हुई है, लंबा व्यू हो तो 2.15 लाख पर खरीदारी शुरू करें

भास्कर एक्सपर्ट
कायनात चैनवाला
एवीपी, कमोडिटी रिसर्च, कोटक सिक्युरिटीज

- **चांदी में अचानक तेजी और फिर बढ़ी गिरावट क्यों आई?**
2025 चांदी के लिए असाधारण रहा। 29 जनवरी को चांदी 121.6 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंची। तेजी के पीछे चांदी की किल्लत, सोलर पैनल, ईवी की भारी मांग और अमेरिका द्वारा इसे 'अहम खनिज' घोषित करने जैसे कारण थे। इस बीच, चीन की चांदी निर्यात पर पाबंदी और ट्रम्प की ग्रीनलैंड, क्यूबा, वेनेजुएला को लेकर आक्रामक नीतियों ने चांदी के दाम को हवा दी।
- शुक्रवार को चांदी में 1980 के बाद की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट देखी गई। वजह ट्रम्प द्वारा महंगाई पर सख्त रूख रने वाले केविन वॉर्श को फेड अध्यक्ष के रूप में नामित करना रहा। एक्सचेंजों द्वारा 'मार्जिन मनी' बढ़ा दिए जाने के कारण निवेशकों को मजबूरी में अपने सौदे काटने पड़े, जिससे भारी गिरावट आई।
- **क्या चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में कमी देखने को मिल रही है?**
यह गिरावट मांग की कमी की वजह से नहीं है। सोलर-ईवी में मांग बहुत ज्यादा है। ईवी में 25-50 ग्राम ज्यादा चांदी लगती है। एआई, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती जरूरतें 2030 तक चांदी की मांग को मजबूत बनाए रखेंगी।
- **ऐसे में निवेशक क्या करें?**
2 फरवरी को मार्जिन में फिर से हुई बढ़ोतरी के बाद शॉर्ट टर्म में चांदी पर दबाव रह सकता है। अगर कोई नया भू-राजनीतिक तनाव नहीं आता है, तो कीमतें और नीचे गिर सकती हैं। हालांकि, चांदी का लॉन्ग-टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी का है, जो निवेशक 2 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखते हैं, वे 70 डॉलर प्रति औंस (करीब 2,15,000 के आसपास) के नीचे धीरे-धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं।

जीएसटी • संग्रह 6.2% बढ़कर 1.9 लाख करोड़

बढ़ती खपत ने जीएसटी दरों में कटौती की भरपाई की

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.2% बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। जनवरी 2025 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1. 82 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। जनवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 38 हजार 92 करोड़ रुपए रहा और राज्य जीएसटी यह संकेत देता है कि देश में बढ़ती खपत ने पिछले साल हुई टैक्स दरों में कटौती के असर की भरपाई कर दी है।

सितंबर 2025 से सरकार ने लगभग 375 वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम कर दी थीं। साथ ही, 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब को मिलाकर सिर्फ 5 और 18% के दो मुख्य स्लैब बनाए गए थे (लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब रखा गया)। भारत के औद्योगिक हब और बड़े राज्यों ने फिर सबसे ज्यादा राजस्व जुटाया है। हमेशा की तरह महाराष्ट्र सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। यहां 15% की ग्रोथ देखने को मिली। कर्नाटक और गुजरात, दोनों राज्यों ने घरेलू लेनदेन और आईटी/मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं के दम पर मजबूत प्रदर्शन किया है। यूपी में खपत के चलते सुधार दिखा।

मध्य प्रदेश का संग्रह 15%, झारखंड का 46% घटा

राज्य	संग्रह	सालाना ग्रोथ
महाराष्ट्र	17,747	▲15%
उत्तर प्रदेश	7,451	▲2%
कर्नाटक	7,684	▲7%
गुजरात	7,742	▲13%
तमिलनाडु	6,618	▲5%
तेलंगाना	4,261	▲5%
राजस्थान	4,182	▲2%
मध्यप्रदेश	2,830	▼15%
आंध्र प्रदेश	3,073	▲7%
बिहार	2,739	▲7%
छत्तीसगढ़	1,013	▼23%
झारखंड	666	▼46%

(सेटलमेंट के बाद एसजीएसटी करोड़ रुपए में, स्रोत- जीएसटी काउंसिल)

छोटे राज्यों के संग्रह में क्यों आ रही गिरावट?

जीएसटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम उपयोग की वस्तुओं और ऑटोमोबाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरों को घटाने का सीधा असर छोटे राज्यों के संग्रह पर पड़ा। इसके साथ ही रिफंड में बढ़ोतरी होने से भी शुद्ध जीएसटी संग्रह में कमी आ रही है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं (सिन गुड्स) पर लगने वाले सेस में तेज गिरावट दर्ज की गई।

ऑटो • थोक कार बिक्री में 13% इजाफा

मारुति-सुजुकी की बिक्री फ्लैट, टाटा की 46% बढ़ी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

जनवरी में कार की थोक बिक्री सालाना आधार पर 12.6% बढ़कर 4.55 लाख पार हो गई। इस बिक्री में एसयूवी और ईवी का दबदबा बढ़ रहा है। मारुति-सुजुकी की कुल बिक्री में 43% हिस्सा एसयूवी का रहा। एसयूवी कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 25 फीसदी बढ़कर 63,510 पहुंच गई।

टाटा मोटर्स की बिक्री 46 फीसदी बढ़कर 70,222 रही। फाडा एकेडमी एंड रिसर्च के चेयरमैन मनीष राज सिंघानिया के मुताबिक सरकार इस बात पर नजर रख रही है कि निर्माता जीएसटी छूट का फायदा सीधे ग्राहकों को दें। इसका असर भी दिख रहा है। ग्राहक बेस बढ़ रहा है और 6-7 लाख रुपए कीमत वाली एंट्री लेवल कारों की बिक्री भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। बिक्री बढ़ने की उम्मीद में डीलर्स भी ज्यादा गाड़ियां उठा रहे हैं।

कंपनियों की 2-3% दाम बढ़ाने की तैयारी

मार्केट से जुड़े लोगों के मुताबिक कंपनियां अगले 1-2 महीनों में कारों की कीमतें 2-3% तक बढ़ा सकती हैं। इसके पीछे एल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर, प्लेटिनम और रेयर अर्थ मेटल जैसे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला दे रही हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी

कंपनी	2025	2026	ग्रोथ%
मारुति सुजुकी	1,73,599	1,74,529	0.54%
टाटा मोटर्स पीवी	48,076	70,222	46.06%
महिंद्रा एंड महिंद्रा	50,659	63,510	25.37%
ह्युंडई इंडिया	54,003	59,107	9.45%
टोयोटा किर्लोस्कर	26,178	30,630	17.00%
किआ इंडिया	25,025	27,603	10.30%

(स्रोत- कंपनियों की रिपोर्ट)

डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे उछला, सोमवार को 91.49 पर बंद

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के एक दिन बाद, सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे बढ़कर 91.49 पर बंद हुआ। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी। विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.95 पर खुला। दिन के दौरान रुपए ने 91.45 का उच्च स्तर और 91.95 के निम्न स्तर को भी छुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि आरबीआई 92 प्रति डॉलर के स्तर का दृढ़ता के साथ बचाव करता दिख रहा है। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार नियामक के साथ मिलकर रुपए पर कड़ी नजर रख रही है और स्थिति असहज होने पर उपाय कर सकती है। ठाकुर के मुताबिक, 'अगर आंकड़ा 90 से ऊपर जाता है, तो हर कोई इसके बारे में बात करने लगता है। यहां तक कि हम भी इस पर बारीकी से नजर रखने लगते हैं।' हालांकि अनुराधा ठाकुर ने कहा कि रुपए के मूल्य में गिरावट से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है।

मार्च के बाद एलआईसी का कुछ हिस्सा बेच सकती है केंद्र सरकार

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

सरकार मार्च के बाद फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के जरिये एलआईसी में अपना कुछ हिस्सा बेच सकती है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में, एलआईसी में सरकार की 96.5% फीसदी हिस्सेदारी है। नागराजू के मुताबिक, यदि सभी मंजूरियां मिल जाती हैं और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है, तो अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का एफपीओ आ सकता है। सरकार ने मई, 2022 में आईपीओ के जरिये एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। सेबी के नियमों के अनुसार, सरकार को मई, 2027 तक एलआईसी में 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता पूरी करना जरूरी है। इसके लिए सरकार को अभी 6.5% हिस्सा और बेचना होगा।

टैक्स डिफॉल्ट मामले 3 साल में 6 गुना तक बढ़कर 20 लाख करोड़

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश में कर भुगतान में चूक (टैक्स डिफॉल्ट) के मामले पिछले तीन वर्षों में 5.7 गुना तक बढ़ गए। इसमें गैर-कॉर्पोरेट श्रेणी में चूक की दर सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक, 20 लाख करोड़ रु. की टैक्स डिमांड रहीं, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 25,396 करोड़ था, जो 8 गुना से ज्यादा की वृद्धि है। पिछले 3 वर्षों में कर संबंधी विवादों में भी 52% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 15.7 लाख करोड़ रु. तक पहुंच गया।

आईटीआर भरने वाले और टैक्स चुकाने वाले भी बढ़ेः बीते 4 वर्षों में जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 20% बढ़ी, वहीं, टैक्स देने वाले 50.4% तक बढ़े। 2020-21 में 6.72 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। इनमें 4.84 करोड़ जीरो टैक्स फाइलर थे, जबकि 1.88 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया था। वहीं, 2024-25 में जीरो टैक्स फाइलर 5.58 करोड़ हो गए, पर टैक्स देने वालों का आंकड़ा 2.82 करोड़ तक पहुंच गया।

क्रिप्टो • 75 हजार डॉलर के नीचे बिटकॉइन

क्रिप्टो में 'ट्रम्प तेजी' खत्म 10 माह के निचले स्तर पर

6 नवंबर 24... ट्रम्प की जीत पर $75 हजार पहुंचा था

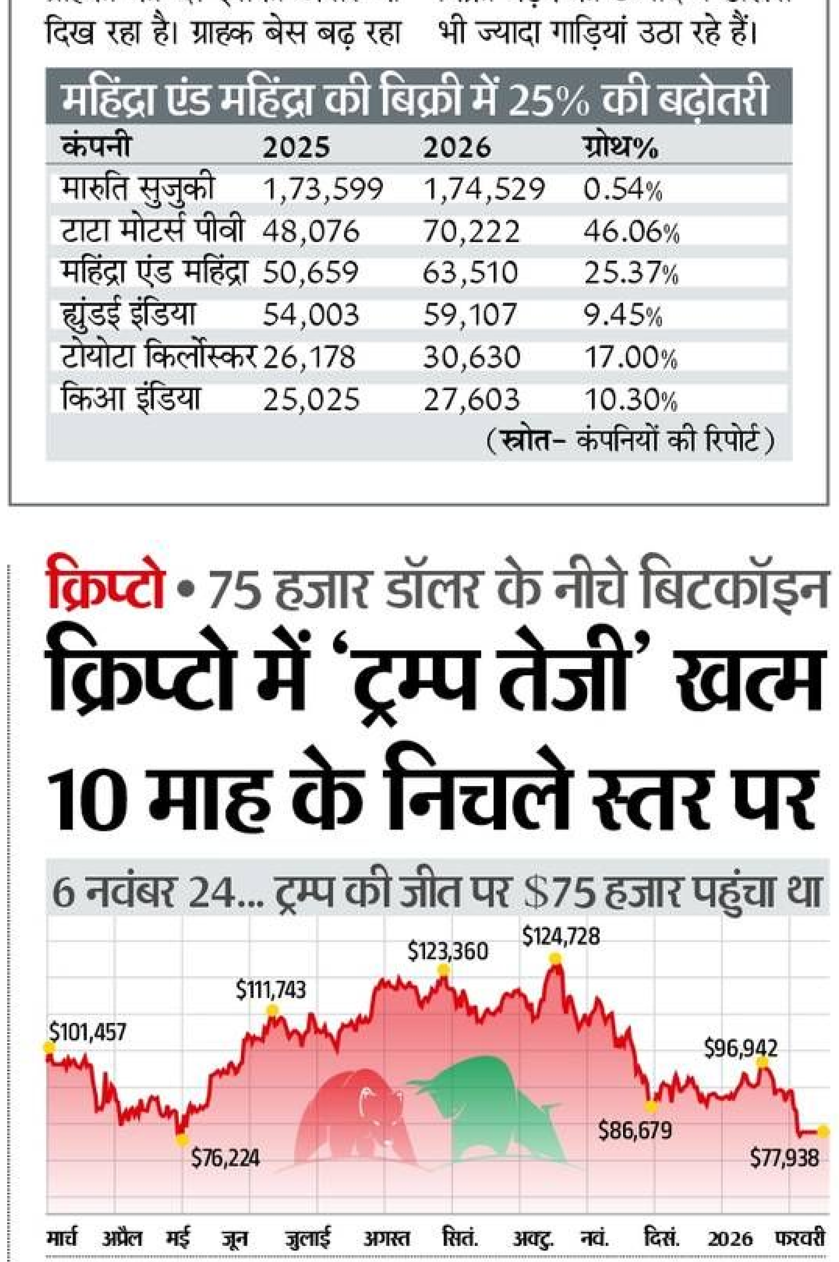

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी है। बिटकॉइन सोमवार को 80 हजार डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से टूटकर 10 माह के निचले स्तर 74,550 डॉलर तक पहुंच गई। बाद में थोड़ी तेजी आई और शाम तक 77,958 डॉलर पर पहुंच गई। बिटकॉइन बीते साल 5 अक्टूबर को ऑलटाइम हाई 126,272 लाख डॉलर पर थी, तब से 40% गिर चुकी है। ट्रम्प के 6 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर यह उछलकर 75 हजार डॉलर पर थी। उनके नरम रूख के चलते इसमें लगातार तेजी बनी हुई थी। यानी ट्रम्प राज की तेजी खत्म हो गई है।

उधारी में ली गई क्रिप्टो की ऑटो बिकवाली से पैनिक

- क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स गिरकर 14 पर आया, जो इसके निवेशकों में डर को दर्शाता है।
- केविन वॉर्श को फेड अध्यक्ष नामित किए जाने से चिंता बढ़ी। वॉर्श दरों में कटौती के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं, जिससे तरलता कम होने का डर है।
- बीते 24 घंटों में 3,300 करोड़ के सौदे जबरदस्ती बंद हो गए, जिन्होंने बाजार बढ़ने की उम्मीद में उधार लेकर पैसा लगाया था।
- जापानी येन की मजबूती और डॉलर की कमजोरी ने भी क्रिप्टो के प्रति सेंटिमेंट प्रभावित किया है।

बिजनेस एंकर इंटरनेट उपयोगकर्ता 1 अरब के करीब, 2019-25 के बीच शहरों में 32% ही बढ़े

शहरों की तुलना में गांवों में इंटरनेट यूजर 4 गुना बढ़े

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में बीते साल इंटरनेट उपयोगकर्ता 8% बढ़कर 95.8 करोड़ पहुंच गए हैं। इसकी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती इंटरनेट पहुंच, शॉर्ट-वीडियो की लोकप्रियता और एआई के बढ़ता उपयोग है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) और कैंटा की रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों में जहां इंटरनेट की ग्रोथ 3% रही वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 12% रहा। आबादी के लिहाज से भी बड़ा अंतर है। देश की 153.7 करोड़ आबादी में से करीब 55 करोड़ ग्रामीण आबादी के लोग इंटरनेट उपयोग करते हैं। 2019 से 2025 के बीच ग्रामीण यूजर्स 26.4 करोड़ से बढ़कर 54.8 करोड़ हो गए। यानी 100% बढ़ गए।

इंटरनेटः 2019 में उपयोगकर्ता 57.4 करोड़ थे, 2025 तक 95.8 करोड़ हुए

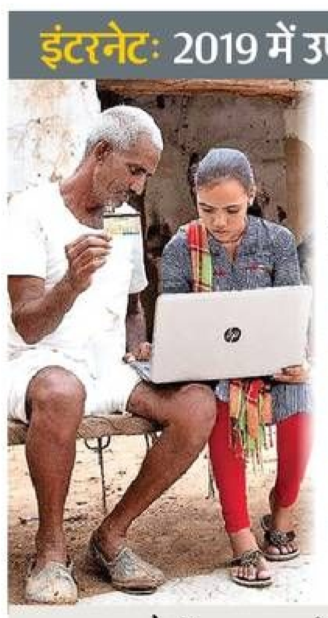

57% उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में, 6 साल में दोगुने

वर्ष	कुल	शहरी	ग्रामीण
2019	57.4	30.9	26.4
2020	62.2	32.3	29.9
2021	69.2	34.1	35.1
2022	75.9	36.0	39.9
2023	82.1	37.8	44.2
2024	88.6	39.7	48.8
2025	95.8	41.0	54.8

(आंकड़े करोड़ में)

देश में इंटरनेट यूजर की ग्रोथ अब घटने लगी है

वर्ष	कुल	शहरी	ग्रामीण
2019	11%	24%	45%
2020	4%	8%	13%
2021	5%	11%	18%
2022	6%	10%	14%
2023	5%	8%	11%
2024	5%	8%	10%
2025	3%	8%	12%

(स्रोत कैंटा रिपोर्ट)

- अनुमान है कि 2026 में भारत 100 करोड़ इंटरनेट यूजर का आंकड़ा पार कर जाएगा।
- शहरी इलाकों में इंटरनेट ग्रोथ 3% रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 12% रहा।

44% यूजर वॉइस-इमेज सर्च, जैसे एआई-इनेबल्ड फीचर्स उपयोग करते हैं

61% यूजर शॉर्ट-वीडियो कंटेंट देखते हैं, इनमें ग्रामीण उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरी यूजर से ज्यादा है

56% शहरी यूजर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रमुखता से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

20% इंटरनेट यूजर फोन-लैपटॉप जैसी एक से ज्यादा डिवाइसों पर इंटरनेट उपयोग करते हैं।

ओरेकल में 30 हजार की छंटनी की योजना

भास्कर न्यूज़ | न्यूयॉर्क

दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल करीब 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। इसके पीछे मुख्य वजह ओपन एआई के साथ किया गया करीब 27 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा सौदा है। इस सौदे के तहत 2027 से शुरू होकर 5 वर्षों में ओरेकल ओपनएआई के एआई मॉडल के लिए डेटा सेंटर बनाएगी जिसमें करीब 30 लाख ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) लगानी होंगी। इस डील के लिए ओरेकल को खर्च में कटौती करनी होगी और इसके चलते करीब 20 से 30 हजार कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ओरेकल ने पिछले दो महीनों में ही 58 अरब डॉलर का कर्ज लिया है।